अतः सरकार से आग्रह है कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति निश्चित करे और रक्षा वाहिनी के जवानों को दैनिक भत्ता पच्चीस रुपया स्वीकृत करे। रक्षा वाहिनी के जवान जो काफी दिनों से सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा को स्थाई करे जिससे वे भुखमरी के शिकार नहीं हों।

(viii) NEED TO ABOLISH SYSTEM OF ENGAGING STAFF ON EXTRA DEPARTMENTAL BASIS IN P&T DEPARTMENT

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan): Sir, out of a total of about eight lakh employees serving the Post and Telegraph Department, nearly three lakhs are those halpless EDAS, receiving a monthly allowance, varying from Rs. 118 to 172, for working generally three to five hours a day. They are not paid if they work beyond the scheduled hours, which they have to do not infrequently, and of course they are not eligible for promotion even after rendering service in the department for 30 years or over. No regular procedure is followed, either for their appointment or dismissal, and the EDA are deprived of all the facilities enjoyed by regular staff, though the nature of work rendered by both the categories is the same. The Rajan Committee recommended in their report, almost a quarter of a century earlier, that EDAS should be recognised in a phased manner, as regular staff. The Supreme Court also gave the verdict that they were civil servants and not casual workers. But no step has yet been taken to recognise the EDAS as departmental staff. They organised a 1,000 mile padajatra, from 10th to 25th March, from different parts of West Bengal to Calcutta, to place their demand before the Prime Minister of India in a memorandum, which was submitted to the Governor on 25th March, 1983. Their immediate demand is for the abolition of the system of engaging staff on extra-departmental basis. In the circumstances, I request the Government to take an immediate action.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we will take up the next item.

SHRIKRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, I have a small submission to make.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you given notice?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: No, Sir. Hear me for a minute. More than several hundred seamen under the leadership of Forward Seamens' Organisations have come from different parts of our country to stage a dharna in front of the Prime Minister's house. Sir, through you, I would request the Prime Minister, or the Minister of Transport and Shipping, to meet their representatives and try to redress their grievances. This is my submission.

12.25 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1983-84—*Contd.*

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES *Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Food and Civil Supplies. Shri K. C. Pandey was on his legs. He has already taken 8 minutes. He has now got 120 seconds.

श्री कृष्ण चन्द्र पान्डे (खलीलाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ता० 24 के अपने अपूर्ण भाषण को पूर्ण करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, ता० 24 को मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी ही दुर्दशा हो रही है। 20 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से मांगा था, तरन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं मान्यवर, जो भारत सरकार की पांच मिलें हैं वे भी किसानों को उचित मूल्य

[श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे]

नहीं दे रहीं हैं। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में किसानों में जनाक्रोश है। हमारी प्रदेश सरकार चिंतित है कि किसानों को जो उनका बकाया है, गन्ने का जो मूल्य बकाया है, वह उनको अदा किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करें।

मान्यवर, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के बारें में इस समय देश में बड़ी चिंता व्याप्त है। रेलवे बोर्ड के बारे में बराबर आलोचना की जाती रही है परन्तु अब आलोचना का विषय धीरे-धीरे फूड कारपोरेशन बनता जा रहा है और बन भी गया है। परन्तु मुझे खुशी है कि इस विभाग की जिम्मेदारी एक ऐसे योग्य और कुशल प्रशासक श्री आजाद जी के हाथ में है जिससे कि फूड कारपोरेशन जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसमें सुधार आएगा।

मान्यवर, प्रतिवर्ष 112 करोड़ का लास फूड कारपोरेशन ट्रांजिट और स्टोरेज में करता है। वह प्रतिवर्ष 5.52 करोड़ रुपया डेमरेज का रेलवे को देता है। मान्यवर, आप सोच सकते हैं कि फूड कारपोरेशन 112 करोड़ रुपये का लास ट्रांजिट और स्टोरेज में करके 5 करोड़ रुपया रेलवे को डेमरेज का देकर के 117 करोड़ रुपये का भार इस देश के किसानों पर डालना चाहता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस सारे लासिज की जिम्मेदारी तुरन्त बड़े अधिकारियों या छोटे कर्मचारियों पर फिक्स की जानी चाहिये जिससे कि यह जो 117 करोड़ रुपये का फूड कारपोरेशन को लास होता है, वह न हो और इसका भार किसानों पर भी न पड़े।

माननीय उपाध्यक्ष जी, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की जिम्मेदारी किसानों से सीधे गल्ला खरीदने की है। परन्तु फूड कारपोरेशन के अधिकारी आढ़तिये रखे हुये हैं। आज भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे गल्ला न खरीद कर के आढ़तियों की मार्फत गल्ला खरीदा जा रहा है। यदि किसी बड़े किसान ने कह दिया कि हम आपको गल्ला सीधा बेचेंगे तो कारपोरेशन के अधिकारी उसको कहते हैं कि हम तुम्हारा गल्ला घटिया करवा देंगे, उसे अच्छे किस्म के गल्ले में नहीं लिया जायेगा। मेरी मंत्री जी से अपील है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि फुड कारपोरेशन गल्ला आढ़तियों की मार्फत न खरीदे, बल्कि सीधे खरीदे। भारत सरकार किसानों को जो लाभ देना चाहती है इससे वह लाभ किसानों को सीधा मिलेगा। तभी किसानों का मनोबल ऊंचा होगा और आज विदेशों से जो गल्ला आयात किया जाता है वह भी आपको आयात नहीं करना पड़ेगा। फूड कारपोरेशन द्वारा किसानों को उत्साहित किया जाना चाहिये, उनका मनोबल ऊंचा किया जाना चाहिये। आज फूड कारपोरेशन बिचौलियों की मार्फत गल्ला खरीदता है, आढ़तियों की मार्फत खरीदता है। इससे सरकार की बदनामी होती है। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया सीधे किसानों से गेहूं खरीदे। इस से किसानों का भला हो सकता है।

मान्यवर, खाद्य विभाग की भी कुछ बातें सुनने में आई हैं। कुछ उच्च अधिकारी भी अपने दायित्व का पालन नहीं करते। सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड में प्रतिवर्ष ठेका होता है। नियम है कि लोएस्ट टेंडर जिसका हो उसको ठेका मिलना चाहिये। आप पुराने कागजात मंगवा कर देख लें। उनका टेंडर मंजूर

हुआ है जिनका हाइएस्ट टेंडर था। ऐसा क्यों हुआ और किन लोगों ने ऐसा किया ? इसकी पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिये ।

सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड की बैठक होती है। बैठक में कभी आधे आइटम्स पर विचार कर लिया जाता है। और कभी तिहाई आइटम्स पर विचार कर लिया जाता है। संयुक्त सचिव और डायरेक्टर स्तर के अधिकारीगण ताज होटल में भोजन करते हैं। मेरे पास उदाहरण हैं। दिनांक 22-7-1982 को सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड की बैठक थी। इसमें 26 आइटम्स में से 21 आइटम्स पर विचार किया गया और 5 आइटम्स छोड़ कर हमारे उच्चाधिकारी लोग ताज होटल में भोजन करने चले गये और 1400 रुपये का बिल बनाकर फूड एण्ड सिविल सप्लाई विभाग को भिजवा दिया। अगर इस तरह से हमारे बड़े अधिकारी लोग काम करेंगे तो देश की नेता इंदिरा गांधी जी का जो उद्देश्य है कि हमें इस देश से भ्रष्टाचार हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त करना है, उस उद्देश्य को धक्का लगेगा। आप इसकी जांच करवा लें ।

1978 में विश्व बैंक ने खाद्य निगम को 157.50 करोड़ रुपया गोदामों के निर्माण के लिये सहायता के रूप में देने का संकल्प किया। फाइलों का निपटारा समय पर नहीं हो पाया। एक बड़े अधिकारी के पास फाइल लगभग 5,6 महीने तक पड़ी रही। परिणामस्वरूप जिन गोदामों का निर्माण 1979 तक पूरा हो जाना चाहिये था वे 1986 तक पूर्ण होंगे। इस तरह से जिन गोदामों पर 157·50 करोड़ का खर्च आना चाहिये था वे अब 190 करोड़ रुपये में बनेंगे। इसकी जवाबदेही किस पर है ? फाइलों का निपटारा क्यों नहीं किया गया ? किसानों के ऊपर क्यों बोझा डाला जा रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसको देखेंगे और अगर कोई दोषी पाया गया तो वैधानिक कार्यवाही करने में इनकी कलम नहीं चूकेगी।

मान्यवर, गोदामों का निर्माण होता है लेकिन जो विभाग गोदामों का निर्माण करते हैं उनमें आपस में मेल नहीं है। सेंट्रल फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग बोर्ड, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और कोआपरेटिव सेक्टर के लोग गोदामों का निर्माण करते हैं।

चारों एजेंसियां एक ही स्थान पर गोदाम बना लेती हैं और सरकार को दिखा देती हैं कि घाटा हो रहा है क्योंकि गोदाम में रखने के लिये जगह नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि गोदामों का निर्माण एक ही स्थान पर न कराया जाए। एक स्थान पर एक ही एजेंसी का गोदाम होना चाहिये चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो ।

फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से हमारे माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्रय केन्द्रों को ब्लाक स्तर पर किया जाना चाहिये। एक ब्लाक में दो क्रय केन्द्र होने चाहिये जिससे किसान अपने गल्ले को आसानी से फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की दुकान पर जमा कर सकें। यदि ऐसी व्यवस्था हो गयी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिचौलियों से बचा जा सकता है। आपने जो टारगेट गल्ला खरीदने का बनाया है, वह पूरा नहीं होगा बल्कि कई गुना बढ़ सकता है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि हैसर बाजार से खलीलाबाद बाजार करीब 35 किलो मीटर दूर है जहां किसान को ट्रैक्टर या ट्राली पर रखकर धान लाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही

[श्री कृष्ण चन्द्र पान्डे]

बिचौलिये किसान का कह देते हैं कि तुम्हारा गल्ला हम बेंच देंगे, आप पैसे लो और घर चले जाओ। इस प्रकार बिचौलियों से बचने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

एन० सी० सी० एफ० के बारे में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान अच्छी तरह से आकृष्ट कराया जा चुका है। । देश की कोई पत्रिका या पत्र ऐसा नहीं है जिसमें एन० सी० सी० एफ० के कारनामों के बारे में न छपा हो। दालों का घोटाला और कंट्रोल रेट का कपड़ा जो कलकत्ता और गोहाटी में बिक गया लेकिन सही उपभोक्ताओं को कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार काकीनाडा का केस भी इस सदन में उठाया जा चुका है। मेरी अपील है कि एन० सी० सी० एफ० को ऊपर से नीचे तक सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि एन० सी० सी० एफ० के कार्यों और कारनामों से सरकार की बदनामी होती है।

हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारा 17वां सूत्र है "गरीबों के बच्चों को सस्ती पुस्तकें और पुस्तिकायें उपलब्ध कराना"। मैं कहना चाहता हूं कि कापियां बनाने का अधिकार बिग हाउसेज को दिया जाता है जैसे करमचन्द थापर एण्ड कम्पनी को दिया गया। जितनी कापियों की छपाई होनी चाहिए उतनी नहीं होती है और नतीजा यह होता है कि गरीबों के बच्चों को कापियां महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि एक ही बिजनेस हाउस को इस प्रकार का कार्य न दिया जाये। कोआपरेटिव सेक्टर जो प्रदेशों में हैं और यहां भी हैं उसको यह काम दिया जाना चाहिए जिससे देश के गरीब मजदूर का बेटा पढ़ने के लिये कापी प्राप्त कर सके।

राशन की दुकानों के बारे में मंत्रीजी ने राज्य सभा में अपने एक बयान में कहा था कि देश में जो खाद्य वितरण की बात है उसकी ऊपर से नीचे तक सुधारने की आवश्यकता है। अभी कोआपरेटिव सैक्टर को यह काम दिया गया है, परन्तु उत्तर भारत में कोआपरेटिव की क्या स्थिति है वह मंत्री जी को मालूम है। मंत्री जी आप फूड एण्ड सिविल सप्लाई की जो परिषद् है उसके अध्यक्ष हैं, आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जो लोग निकल रहे हैं वह बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। इसलिये मेरी मंत्री जी से अपील है कि जो भी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं देश के कोने कोने में कम से कम 50 प्रतिशत दुकानें बेरोजगार नोजवानों को मिलनी चाहिए ताकि उसकी बेरोजगारी दूर हो। और प्रभावशाली लोग जो 25, 25 दुकानें लिये बैठे हैं, हमारे मंत्री जी ने राज्य सभा में जवाब भी दिया था कि दिल्ली में ही एक आदमी ऐसा पकडा गया जिसके पास 25 राशन की दुकानें थीं, ऐसे लोगो को न देकर बेरोजगार नौजवानों को यह दुकानें दी जायें क्योंकि जब उनका धैर्य धीरे-धीरे टूट रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं मंत्री जी से बेरोजगारी दूर करने का जो संकल्प हमने अपने घोषणा-पत्र में दिया है उसे पूरा किया जाना चाहिए।

अभी तक गेहूं का मूल्य निर्धारण नहीं हुआ। हमारा गेहूं खेत में खड़ा है, किसानों को चिन्ता है, खाद और बिजली मंहगी हो गई परन्तु गेहूं का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ, मैं चाहूंगा कि यह जल्दी से जल्दी किया

जाना चाहिए और ऐसी सम्भावना है कि 142 रु० की जगह शायद 150 रु० प्रति क्विंटल भाव तय हो । लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Even in making a demand, why are you so thrifty? Why don't you ask for more?

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसमें पहल कदमी कीजिये और किसानों को कम से कम 175 रु० प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मिलना चाहिए जिससे किसानों का मनोबल ऊंचा हो । प्रति दिन समाचार-पत्रों में निकलता है कि गेहूं विदेशों से मंगाया जा रहा है, यह हमको विदेश से न मंगाना पड़े । अगर किसानों को आप सही दाम देंगे तो कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे किसान इतना गल्ला पैदा करेंगे कि बाहर से मंगाने का सवाल ही नहीं उठेगा । भारत को आजाद हुए 35 साल हो गये, परन्तु आज भी हम विदेशों से गेहूं मंगायें यह अति चिन्ता का विषय है और इस पर किसानों को भी शर्म आती है ।

मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का जो नट-वोल्ट ढीला हो गया है, उसको टाइट किया जाये जिससे किसानों से सीधा गल्ला खरीदा जाये और किसानों का टर्न-ओवर ऊपर किया जा सके ।

हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री जी से अपील की है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि मार्च के महीने में उन्होंने 1 लाख टन गेहूं दे दिया । मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला आधे उत्तर प्रदेश के लिये सूखाग्रस्त है । बुन्देलखण्ड की स्थिति भी वे स्वयं जानते हैं । पूरा प्रदेश सूखे से तबाह हो गया है । मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में भी वह 1 लाख टन गेहूं और दे दें तो अच्छा हो ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : नया गेहूं बाजार में आ गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : इससे हमारे किसानों को और गरीब मजदूरों को खाद्यान्न पहुंचाया जा सकेगा ।

इसके साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल का कोटा भी पूरा नहीं मिलता है । हमारे प्रदेश की सरकार ने बार-बार प्रार्थना की है कि जन संख्या के आधार पर तेल दिया जाये । इसके लिये कम से कम 75 हजार किलोलीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगा । किन्तु उत्तर प्रदेश को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है ।

हमारे गन्ना किसानों की पहली मांग है कि उनका जो बकाया पैसा है, वह उनको मिलना चाहिए । उत्तर प्रदेश सरकार उनको देना चाहती है किन्तु वहां पर जो कस्टोडियन मिले हैं, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य अभी तक नहीं दे रही है । अभी तक वह 17 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 40 पैसे और 18 रुपये 85 पैसे ही दे रही है । मेरा निवेदन है कि घोषित नीति के अनुसार केन्द्र की कस्टोडियन मिलों से बकाया राशि किसानों को दिलवाने की कृपा की जाये ।

20 करोड रुपये जो कर्ज के रूप में प्रदेश सरकार मांग रही जो किसानों को देना है, वह जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, जो समय इसके लिये मुझे आपने दिया, उसके लिये धन्यवाद ।

गन्ने की स्थिति जो आज पूरे देश में बनी हुई है, उसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । थोड़ा सा अगर हम पिछले साल की तरफ ध्यान दें तो चीनी मिलों ने 84 लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा की है । उस साल चीनी का उत्पादन रिकार्ड है लेकिन इसके साथ ही साथ गन्ना उत्पादकों की बकाया रकम का रिकार्ड भी कि बहुत रुपया किसानों का बकाया है । इसकी तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

पिछले साल से गन्ने का उत्पादन 8 प्रतिशत ज्यादा है । उसमें भी सूखा पड़ता रहा । सरकार ने प्रयास किया कि चीनी मिलों को जल्दी पिराई का काम शुरू कर देना चाहिये, लेकिन बावजूद इस आदेश के वह जल्दी नहीं चला सके और जो ज्यादा चीनी का लाभ हो सकता था, वह नहीं लिया जा सका । सारी मिलें देर से चलीं । अक्तूबर में मिलें चलनी चाहिए थीं । उस समय के लिए टैक्स में जो रियायतें थीं उनका भी लाभ वह नहीं उठा पाए । इसके साथ-साथ रिकवरी बेसिस पर गन्ने की कीमत तय की जाती है । पिछले दो सालों की औसत रिकवरी पर इस साल का बेसिक कोटा बनाया गया और गन्ने का भाव तय किया गया । हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी मंहगाई बढ़ गई है फिर भी गन्ने का मूल्य ज्यों का त्यों रखा गया है । पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली में 50 प्रतिशत, खाद में साढ़े 62 प्रतिशत, डीजल में 30 प्रतिशत, मजदूरी में 50 प्रतिशत, रेल का भाड़ा (दो साल में) 30 प्रतिशत और रोडवेज में 40 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है लेकिन फिर भी इस साल पिछले साल का भाव ही रखा गया है । इसके अलावा किसानों का जो गन्ने का दाम बाकी रहता है उस पर उनको सूद भी नहीं मिल पाता है । दूसरी तरफ किसान जितना भी कर्जा कहीं से लेता है उस पर उससे पूरा सूद वसूल किया जाता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर नियमों में कहीं पर ढिलाई है तो उसको दूर किया जाना चाहिए । जैसा कि प्रावधान है, उसके अनुसार 14 दिन के बाद सूद दिया जाना चाहिए लेकिन वह दिया नहीं जाता है । यह प्रावधान केवल कागज पर ही रह जाता है । इसकी तरफ मन्त्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए ।

सारे देश में कुल 301 चीनी मिलें हैं जिसमें से 92 उत्तर प्रदेश में ही हैं । उत्तर प्रदेश में पांच प्रकार की चीनी मिलें चल रही हैं । एक तो कोआपरेटिव मिलें हैं । दूसरी कारपोरेशन की मिलें हैं । तीसरी मिलें वह हैं जिनको टेक-ओवर किया गया है । चौथे प्रकार की प्राइवेट मिलें हैं । पांचवीं सेन्टर की मिलें हैं जो कस्टोडियन मिलें कहलाती हैं । शुरू में इस बात की कोशिश की गई थी कि चीनी मिलों को जल्दी आरम्भ किया जाए लेकिन जब सरकारी मिलें ही नहीं चल सकीं तो दूसरी मिलों पर भी उनका प्रभाव पड़ा । जहां तक गन्ने की स्थिति का सम्बन्ध है, फिक्की के जो चेयरमैन हैं, मि० जैन, उनका एक बयान निकला था कि मिलों पर 40 करोड़ बकाया था जो मैं समझता हूं इस साल तक 2 अरब हो जायेगा । इस प्रकार किसानों का बकाया रहने पर मिलों को चलाना कठिन होगा । अतः

इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास होना चाहिए । चीनी का रेट बढ़ाया जाना चाहिए । इसके अलावा एक लाबी तैयार हो रही है जोकि गन्ने का दाम कम कराना चाहती है । सरकार को यहां पर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि वह कभी भी उस लाबी के दबाव में नहीं आयेगी । साथ ही किसानों का जो बेसिक कोटा है उससे ज्यादा गन्ना लिया जायेगा—इसकी भी घोषणा की जानी चाहिए । इसकी वजह से आज किसान बहुत परेशान है । आज वे गुड़ व खंडसारी के लिए अपना गन्ना सस्ता बेच रहे हैं । उनको गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल रहा है । इसलिये सरकार को यहां पर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि किसान ने जो भी गन्ना बोया हुआ है वह पूरा का पूरा पेरा जायेगा । एक तरफ तो सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में 70 मिलें और खोलने की है इसलिए अगर वह किसानों को प्रोत्साहन नहीं देगी तो वे गन्ना क्यों बोयेंगे ? जो स्थिति इस साल चल रही है उसको देखते हुए अगली बार किसान कम गन्ना बोयेंगे क्योंकि उसको उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को सूद समेत बकाया दिया जाए और चीनी का बफर स्टाक बनाया जाए । तथा दूसरे देशों में यदि सस्ते दामों पर भी जाती हो तो भेजना चाहिये, जिस से उन का तनाव कम हो । जितनी चीनी पिछले साल बनी थी उतनी इस साल भी बन जायगी—इस लिये इस को आप विशेष रूप से देखें ।

आज हम किसानों को रियायत देने की बात कहते हैं—यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि गन्ना किसानों को उन का बकाया सूद समेत मिले तथा गन्ने की पूरी कीमत मिले । उस के मन में यह चिन्ता लगी हुई है—इस लिये मंत्री जी को इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये ।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हमारे अनेक साथियों ने प्रकाश डाला है तथा श्री पांडे जी भी अभी बोल रहे थे—गेहूं की कीमत का ऐलान होना है—मैं चाहता हूं कि 200 रुपये से कम का ऐलान नहीं होना चाहिये । सरकार को कीमत का ऐलान करने से पहले हर चीज़ पर दृष्टि डालनी चाहिये—पिछले साल में क्या-क्या चीज़ें तेज़ हुई हैं, किसानों को पैदावार प्राप्त करने के लिये क्या-क्या खर्चा करना पड़ता है—उन सब को देख कर भाव की घोषणा करनी चाहिये ।

आप ने मुझे बोलने का समय दिया, इस के लिये आप को अनेक धन्यवाद ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य और आपूर्ति विभाग की जो मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, मैं उन का समर्थन करता हूं ।

आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जब से श्रीमती इन्दिर गांधी का राज वापस आया, 1980 से, तब से उन्होंने प्रोक्योरमेन्ट की जो पालिसी एडाप्ट की है उससे देश में एक अच्छा वातावरण बना है तथा हम ने हायेस्ट प्रोक्योरमेन्ट किया है । करीब 15 मिलियन टन का प्रोक्योरमेन्ट हुआ है जो आज तक यहां तक कि जनता पार्टी के जमाने में भी नहीं हुआ । जनता पार्टी की सरकार ने तो सारे देश का बंटाधार कर दिया था.... (व्यवधान) ....लेकिन उस अव्यवस्था को दूर कर के जो प्रोक्योर-

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मेन्ट की पालिसी हम ने एडाप्ट की, निश्चित तरीके से उस से देश में अच्छा वातावरण बना है । हम ने प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था जिन-जिन एजेन्सियों की मारफत की—चाहे एफ०सी०आई० हो; सेन्ट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन हो या स्टेट बेयर हाउसिंग कारपोरेशन हो—उन के सम्बन्ध में चाहे जो शिकायतें हों, उन की व्यवस्था अच्छी थी या नहीं थी, उन के प्रोक्योरमेन्ट में क्या-क्या गड़बड़ी थी, इन सब के बारे में मैं बाद में कहूंगा—लेकिन जो भी एजेन्सियां हैं, जिन के द्वारा 15 मिलियन टन गेहूं प्रोक्योर किया गया है, उतना अब तक किसी भी वर्ष में प्रोक्योर नहीं हुआ, इसलिये इस कार्य के लिये हम सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं । इन्होंने बड़ी मज़बूती के साथ इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये कारगर कार्यवाही की है, विदेशों से भी फूड-ग्रेन्ज़ मंगा कर बफर-स्टाफ बनाने की व्यवस्था की है—इस से भी देश में एक अच्छा वातावरण बना है । क्योंकि जब तक देश में बफर-स्टाक नहीं होता है, प्राइसेज़ का एक्स-केलेशन होता है, उस में रुकावट नहीं आती है, लेकिन जब लोगों को मालूम होता है कि बफर-स्टाक मौजूद है, जिस के द्वारा हम सारे देश को व्यवस्थित तरीके से सप्लाई कर सकते हैं, उस स्थिति में दाम नहीं बढ़ पाते हैं । मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं—पिछले वर्ष में फूड ग्रेन प्राइस में बहुत थोड़ा अन्तर आया । 1978 में जब कि 16 परसेन्ट से ज्यादा का फर्क था, पिछले वर्ष केवल 4.9 परसेन्ट प्राइस की बढ़ोतरी हुई । इस बात के लिये भी हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है, उन्होंने प्राइसेज़ को बढ़ने से रोकने में बहुत बड़ी मदद की है ।

मगर आज देश में जो स्थिति है—आधे से ज्यादा देश में भयंकर अकाल है । राजस्थान में तो उस से भी ज्यादा अकाल है । लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा भयंकर अकाल होते हुए भी जिस तरह से प्रोक्योरमेन्ट किया, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये विदेशों से अनाज मंगाया, और जिस तरीके से उन्होंने वितरण व्यवस्था करने की कोशिश की है उससे हमें मालूम होता है कि हमारी सरकार इस मामले में सजग है । जिन स्टेट्स में खाद्यान्न की कमी है उन स्टेट्स के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है जिससे कि भूख और प्यास से लोगों के मरने की हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आई । बेशक लोग बीमारियों से मर गये हों लेकिन भूख और प्यास से कोई नहीं मरा । इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है ।

13.00 hrs.

इस देश में इतने भयंकर अकाल के होते हुए और अकाल से इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित होते हुए भी जो वितरण व्यवस्था की गयी है, उसके लिए निस्सन्देह सरकार धन्यवाद की पात्र है । मगर इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप और माकूल बनाए । मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पिछले चार-पांच सालों से भयंकर अकाल पड़ता है । आप हम को 19 हजार टन गेहूं हर माह देते हैं । जब बंगाल वाले कहते हैं कि हम को एक लाख टन गेहूं और चावल दो, बिहार और यू०पी० के लोग भी कहते हैं हम को भी एक-एक लाख टन खाद्यान्न दो, केरल वाले भी एक लाख टन चावल की मांग करते हैं और आप उन्हें भरसक देने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थान जहां कि आबादी साढ़े तीन

करोड़ है, उसके लिए आप ने 19 हजार टन गेहूं दिया तो इतने अनाज से राजस्थान की इतनी बड़ी आबादी किस प्रकार प्रभावित होगी, उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं आप इस पर पुनर्विचार करें । और वहां की जनसंख्या को देखते हुए राजस्थान को पूरा खाद्यान्न सप्लाई करें । अब तक तो लोगों की शिकायत सरकार के सामने नहीं आई है । वहां यह भी स्थिति पैदा हो सकती है कि लोग भूख और प्यास से मर जाएं । इस पर आपको ध्यान देना चाहिए ।

आपने इस देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कोआप्रेटिव सोसायटीज के जरिये से मजबूत करने की कोशिश की है । आपने 2.82 लाख फेयर प्राइस शाप्स पिछले वर्षों में खोली हैं । मगर इन दुकानों की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए । आपको यह भी देखना है कि क्या आपकी कोआप्रेटिव्ज वाएबल यूनिट्स हैं या नहीं । उनके पास इतना पैसा है या नहीं जिससे कि वे वितरण सामग्री लोगों को उपलब्ध करा सकें । मैं पिछले तीन सालों से आपको बराबर कह रहा हूं कि अगर आप इन कोआप्रेटिव सोसायटीज को इकोनोमिकल्ली वाएबल नहीं बनायेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चल पायेगा । इसलिए इनको वाएबल यूनिट बनाने की परमावश्यकता है तभी जा कर कोआप्रेटिव्ज वितरण के मामले में कदम उठा सकेंगी । वरना आप दुकानें खोलते जाएंगे, उनका लाभ कोई नहीं होगा । आप जो सामग्री वितरण के लिए देंगे भी, उसका दुरुपयोग होगा । वह सामग्री लोगों तक ठीक प्रकार से पहुंच पाए, इसके लिए आपको इकोनोमिकल्ली वाएबल यूनिट्स बनाने के सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने चाहिएं

तीसरा मेरा निवेदन है कि आपने कोआप्रेटिव सोसायटीज के अलावा प्राइवेट लोगों को भी फेयर प्राइस शाप्स दे रखी हैं । माननीय पांडे जी कह रहे थे दिल्ली में आपने बीस दुकानें एक आदमी को दे रखी हैं । मैं तो कहता हूं कि प्राइवेट लोगों को वितरण की एजेन्सी नहीं मिलनी चाहिए । ये लोग वितरण सामग्री का दुरुपयोग करते हैं । मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं । हमारे यहां किसी भी देहात में इन दुकानों से एडीबल आयल और कपड़ा नहीं मिलता है । हमारे यहां गेहूं और शक्कर तो जरूर मिल जाता, उसके अलावा और कोई सामग्री वहां नहीं मिल पाती । इसका मुख्य कारण यह है कि आपने जो होल सेल या रिटेल एजेन्सीज कायम कर रखी हैं, वे दी गयी सामग्री का ठीक प्रकार से वितरण नहीं करतीं और उस सामग्री को काले बाजार में बेच देती हैं । वे इस प्रकार से गरीबों को सामान सप्लाई न कर के पैसे वालों से, उनको वह माल दे कर नाजायज फायदा उठाते हैं । अगर व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी तो असेंशियल आयटम्स जो आपने 6–7 बनाए हैं वे आम जनता को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । रैपसीड आइल, कलाथ तथा अन्य प्रकार की चीजें उचित दर की दुकानों तक नहीं पहुंच पातीं । मेरा निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

एक निवेदन और करना चाहता हूं । कंट्रोल के कपड़े का निर्माण एन टी सी करता है । पहले यह तरीका था कि अन्य मिलों को भी कुछ निश्चित परसेंटेज कंट्रोल क्लाथ बनाना पड़ता था । किन्हीं कारणों से अब प्राइवेट मिल्स को इस नियम से मुक्त कर दिया गया है । इसको देखने की आवश्यकता है । तमाम गरीब लोगों को, किसानों और मजदूरों को सस्ता कपड़ा सुलभ हो सके, यह काम केवल एन टी सी के द्वारा नहीं किया

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

जा सकता । इसके लिए कोई कदम उठाना होगा तभी गरीब लोगों को कंट्रोल क्लाथ उपलब्ध हो सकेगा । इस ओर तवज्जह देने की आवश्यकता है ।

इसी प्रकार रैपसीड आइल और वेजीटेबल आइल भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध नहीं हो पाता है । जो संस्थाएं इंपोर्ट करती हैं उनको भी कई कंसेशंस दिए गए हैं । लेकिन यह देखने की आवश्यकता है कि जो संस्थाएं अरबों रुपए की सामग्री इंपोर्ट करती हैं वे सही जगह पहुंचती भी हैं या नहीं या ब्लैक मार्केट में पहुंचती हैं । जब तक इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक असेंशियल आइटम्स आप आम जनता को उपलब्ध नहीं करा सकेंगे ।

शुगर प्रोडक्शन के बारे में आज क्या स्थिति है । आज जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किसानों को गन्ने की कीमत ज्यादा मिलनी चाहिए । जनता पार्टी के समय में क्या स्थिति थी। 5 रुपए क्विंटल गन्ना भी कोई किसानों से खरीदने को तैयार नहीं था । परिणाम यह हुआ कि किसानों को खेतों में गन्ना जला देना पड़ा । हमारी नेता इंदिरा जी के आते ही आपने देखा कि 22–23 रुपए क्विंटल गन्ना खरीदा गया । इसकी वजह से देश में गन्ने का उत्पादन बहुत बढ़ा । आज आपको यह जानकर खुशी होगी कि दुनियां में सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन यहां किया गया । यह कोई कम बात नहीं है । एक समय था जब हम देश की मांग की पूर्ति नहीं कर पाते थे और आज हम लाखों टन शक्कर का निर्यात कर सकते हैं । जनता पार्टी के समय में 35 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ जबकि पहले 60–70 लाख टन का उत्पादन होता था । इंदिरा जी के आने के बाद 80, 84 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ है । आज हम इस देश को इस स्थिति में ले आए हैं । आपको इस बात पर गर्व करना चाहिए ।

जनता पार्टी की सरकार ने तीन साल तक राज करने के बाद सारी सरकार का दिवाला निकाल दिया ।. . . (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : जनता पार्टी का राज तो ढाई साल के बाद खत्म हो गया लेकिन आपकी सरकार तो तीन साल से चल रही है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने ही इस देश का भट्ठा बैठा दिया और सिर्फ 38 लाख टन चीनी पैदा की। आपको मालूम होना चाहिए कि जनता पार्टी के राज में किस प्रकार का अत्याचार और अन्याय किसानों के साथ हुआ । हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के साथ हमदर्दी रखने वाली सरकार है । हम लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग नहीं हैं । हमारा आर्थिक प्रगति का लक्ष्य है । आप देख सकते हैं कि श्रीमती गांधी की सरकार मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए किस प्रकार से काम कर रही है ।

माननीय मंत्री जी से शुगर प्राइस के बारे में कहना चाहता हूं। आपने सस्ती शुगर गरीबों को फेअर प्राइस शाप्स द्वारा देने के लिए योजना बनाई है, इसलिए शुगर की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए । सस्ते दामों पर ही गरीबों को शुगर उपलब्ध होनी चाहिए । आपने पिछले साल तीन-तीन, चार-चार दफे कीमतें बढ़ाई हैं और गरीबों को कन्ट्रोल रेट पर देने की बात भी कही है । मिल-मालिक करोड़ों रुपया खा गए और सब मिलों को सिक बना दिया । करोड़ों

रुपया किसानों का बाकी है, इसके बावजूद भी आप इन पर दया कर रहे हैं । आपने सिक मिल्स को ऊपर उठाने के लिए 9 रुपया प्रति क्विंटल सैस लगाया है । पहले आप इस बात की जांच कीजिए कि इन मिलों को सिक किसने बनाया और किसने पैसे का दुरुपयोग किया और किस तरह से इस पैसे को कहां-कहां ले गए । अगर देश के इन्टरेस्ट में इन्होंने काम किया है तो अवश्य ही आप इनकी मदद कीजिए । अगर इन्होंने बेईमानी की है और पैसा खा गए हैं तो निश्चित ही इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । मैं चाहता हूं कि आपको अवश्य ही सिक मिल्स को अपने पास लेना चाहिए जिससे मजदूरों को मजदूरी मिले और उसके बाद इन मिल्स को माडर्नाइज और रिहेबिलिटेट करके ऐसी यूनिट बनाई जाए जो प्राफिटेबल और वायेबल हों ।

इनको वापिस मत कीजिए बल्कि नेशनलाइज किया जाए । एफ० सी० आई० में बड़ी भारी गड़बड़ी है । एफ० सी० आई० के सम्बन्ध में आप ध्यान रखें ताकि सामान खरीदते वक्त बिचौलिये बीच में न आयें, क्योंकि इससे गरीब किसान को कम पैसा मिलता है । बिचौलिया अगर होगा तो किसान का शोषण होगा । इसलिये इस व्यवस्था को माकूल बनायें और ब्लाकवाइज आप परचेज सेंटर खोलिये । इसके अलावा एफ०सी०आई० गोदाम से जब दुकानदार को माल दिया जाता है तो उसमें भी गड़बड़ करते हैं कर्मचारी लोग । 5, 10 किलो गेहूं हर बोरी में कम मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि दुकानदार उपभोक्ताओं को कम माल तोलता है और उनको तकलीफ होती है । एफ० सी० आई० के जो अधिकारी गरीबों का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये ।

आप फसल के समय पर तो अच्छा गेहूं किसान से लेते हैं फिर समझ में नहीं आता कि उसमें रेत और कंकड़ कहां से आ जाते हैं वजन बढ़ाने के लिये ? इस अव्यवस्था को रोकना चाहिये । अच्छा गेहूं प्राइवेट दुकानों में चला जाता है और खराब गेहूं राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को मिलता है । इस व्यवस्था को आपको ठीक करना चाहिये । आप प्रोक्योरमेंट के समय अच्छे से अच्छा गेहूं लेते हैं लेकिन बाद में कज्यूमर्स को सड़ा गेहूं मिलता है । इस अव्यवस्था को रोका जाए ।

एफ० सी० आई० के जितने भी अधिकारी हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं आप देखिये कितने लोग इसमें होने चाहिये । कोई तो नौर्म होगा जिसके मुताबिक कर्मचारी होने चाहियें ? 10,000 के करीब जो अतिरिक्त स्टाफ एफ०सी०आई० में है और उस पर बोझ बने हुए है उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह भेजिये जिससे गरीबों का शोषण न हो सके ।

इसी तरह से एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के अन्तर्गत आप राज्यों को अनाज और पैसा देते हैं । आपको देखना चाहिये कि किस-किस राज्य ने इसका सही उपयोग किया है और किसने नहीं । जिन राज्यों ने एन.आर.ई.पी. कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया उनके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें ताकि अनाज और पैसे का दुरुपयोग न हो और कोई अपना पार्टी काडर बनाने के लिये इस व्यवस्था का दुरुपयोग न करे । मैं दूसरों के लिये ही नहीं कह रहा हूं, हमारे यहां भी पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ । इसलिये वहां पर भी आप व्यवस्था कीजिए । अगर पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो किस वजह से ऐसा हुआ है इसको

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

देखिये और व्यवस्था ठीक करने के लिये आवश्यक कदम उठाइये ।

बाड़ोर जिले में शेरगढ़ तहसील में, अभी राजस्थान विधान सभा में प्रश्न इस बारे में उठा था कहा गया कि 200 आदमी भूख से मर गये। मैं इस बात को तो नहीं मानता कि भूख से मरे, लेकिन कुपोषण से जरूर मरे हैं क्योंकि उनको पूरा खाना नहीं मिला । इसके पीछे किसका हाथ है ? और जो दोषी लोग हैं जिनकी वजह से 55 आदमी मरे हैं उनके खिलाफ भी भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये । जो राज्य अपनी रियाया को पूरा भोजन न खिला सके....उनको पूरा न्यूट्रिशस फूड नहीं दिला सके, उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से नहीं चला सके । आज उस तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ आपको कदम उठाने चाहियें । आप उनके कुपोषण की पूर्ति कराइये और उनको सारी सामग्री दिलाने की व्यवस्था कराइये । ऐसी व्यवस्था कराइये ताकि गरीब आदमी मैल-न्यूट्रिशन से मरे नहीं, वह जिन्दा रह सके ।

आपकी जो सैंट्रल एजेन्सीज हैं एक तो एस०टी०सी० है और एक पांडे जी ने एम० एम० टी० सी० बताई । इस प्रकार की जितनी भी एजेन्सीज हैं देश के लेबल पर, जिनमें अरबों रुपये का सामान यह मंगाती हैं, उनकी कोई न कोई पड़ताल आपको करनी चाहिये कि उनमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है । उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं ? हमारी सब स्टेट्स को उनके जरिये जितना सामान मिलना चाहिये, दालें, मिट्टी का तेल, रेपसीड आयल और अन्य प्रकार का सामान, वह ठीक मिल रहा है या नहीं ? जितनी उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार मिल रहा है या नहीं ? कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है, यह आप अच्छी तरह देखिये और व्यवस्था को सुन्दर कीजिये ताकि श्रीमती इंदिरा गांधी के राज्य को लोग याद रखें कि इंदिरा जी के नेतृत्व में जितना भी सामान हम इकट्ठा करते हैं, वह ठीक प्रकार से वितरित होता है और उससे गरीब का भला होता है । इस तरह से गरीब इंदिरा जी के हाथ मजबूत करने में मदद करेंगे । हम पूरे लोग आपके साथ हैं । आप इंदिरा जी के हाथों को मजबूत करें और देश की व्यवस्था को माकूल बनाने में पूरी ताकत लगायें । इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की डिमांडस का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल की ओर से बोल रही हूं, लेकिन मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि मैं एक कज्यूमर मूवमेंट की प्रतिनिधि हूं । मैं समझती हूं कि जैसे लोकतंत्र में eternal vigilance is the price to be paid for democracy, eternal vigilance is necessary to develop consumer movement.

कज्यूमर्स मूवमेंट चलाने वाले लोगों को सिर्फ पोलिटीकली विचार नहीं करना चाहिये, यह भी मैं मानती हूं । इसीलिये मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब जनता पार्टी का राज्य चल रहा था, मैं जनता पार्टी की सदस्य पहले से ही हूं, जब हमारी पार्टी का राज्य इस देश में चल रहा था तब भी बजट के जरिये खवामाखवाह दाम बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने कज्यूमर्स का बहुत बड़ा जलूस निकालकर, उस समय भी इसका विरोध किया था । मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पीठ बजाने से कोई फायदा नहीं होता है ।

जो हुआ है, वह हमने किया है और जो नहीं हुआ है, वह दूसरों ने नहीं किया है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखती हूं । इसलिये मैं आपकी बात आपके सामने रखना चाहती हूं । आप यह न समझिये कि सिर्फ पोलिटिकली मोटिवेटेड हमारे चाजज हैं । आप उन पर विचार कर अपनी राय दीजिये ।

आपको कज्यूमर्स मूवमेंट को बलवान बनाना चाहिये, आपके हाथ में जितनी ताकत है उसका सहयोग देकर इसको बढ़ाने में मदद देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं ।

आज पूरे देश में बड़ा भारी अकाल है । पिछले हफ्ते सारे विरोधी दल के लोग इकट्ठे होकर एडजार्नमेंट मोशन इसलिये मांग रहे थे कि आज गरीब वर्ग की हालत बहुत खराब है । देश में लोग मर नहीं रहे हैं, लेकिन मृत्यु की रेखा पर बैठे हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है । तमिलनाडु में पीने का पानी कम है, केरल में चावल ज्यादा चाहिये । महाराष्ट्र के 26 जिलों में से 20 जिलों में अकाल पड़ रहा है । आपके अन्दाज के मुताबिक अकाल होने के बावजूद भी 10 मिलियन टन अनाज ज्यादा होगा । आप पहले साल भी कह रहे थे कि अनाज ज्यादा हुआ है । अगर आपका यह कहना है तो आप लोगों को अनाज कहां दे रहे हैं ? आप अलग-अलग स्टेट्स को राजनीतिक विचार न करते हुए, दूसरी पार्टी का राज्य है तो भी वहां की जनता देश की जनता है, यह समझते हुए उनको ठीक प्रकार से अनाज पहुंचाने की व्यवस्था कहां कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहती हूं । 1978–79 में 132 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ था । वह मैक्सिमम अनाज पैदा हुआ था और उस समय पर कैपिटा कंजम्शन 480 ग्राम था । आज 460 ग्राम ही रह गया है । जबसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तब से आज सबसे कम फूडग्रेन का पर कैपिटा कंजप्शन है । हमारे देश के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट श्री डी० सी० कोठारी ने कहा है कि 230 लाख बच्चे जो पैदा होंगे उनमें से 40 लाख पांच सालों में इसलिए मर जायेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए पूरा अनाज नहीं मिलेगा । 30 लाख बच्चे अच्छे घरों में पैदा होंगे, उनकी सेहत तो ठीक रहेगी लेकिन 160 लाख बच्चे मालन्यूट्रिशन की वजह से शरीर और दिमाग से कमजोर रहेंगे क्योंकि अकाल की स्थिति हो रही है ।

महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम शुरू हुई थी जिसका बाद में अन्य राज्यों ने भी अनुकरण किया । आज जनसंख्या को रोकने में, कारण जो भी हों, उतनी सफलता नहीं मिल सकी है । आज अकाल की स्थिति बनी हुई है । इसलिए फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए केन्द्रीय सरकार को दुगुना तिगुना अनाज देना चाहिए और राज्यों से कहना चाहिए कि वहां पर ऐसे कार्य किए जायें जिनसे भविष्य में अकाल की स्थिति पैदा न हो । महाराष्ट्र में तालाब और बांध बनाने की योजनायें हैं । आपने इस योजना के लिए जो अनाज का कोटा रखा है उसको दुगुना तिगुना करना पड़ेगा । एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत आप अनाज देने की व्यवस्था कर सकते हैं । इस प्रकार से जो मालन्यूट्रिशन का सवाल पैदा हुआ है उसको भी थोड़ा बहुत हल कर सकते हैं ।

सरकार ने यहां पर बजट पेश करने से पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 800 करोड़ के टैक्स लगाए । फिर आपने डूअल प्राईसिंग की घोषणा की ।

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

फिर आपने तालियों के साथ-साथ किरोसीन की कीमत घटाने की घोषणा की थी। मैंने ताली नहीं बजाई थी क्योंकि मैं एक ग्रहणी हूं और मुझे पता है कि पहले आपने 800 करोड़ बढ़ा दिए और फिर कम करने का बहाना किया। उसके बाद अब 19 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे।

1979 में जब जनता पार्टी का शासन नहीं रह गया था, आपने श्री चरण सिंह को शासन में बिठाया था उस समय से लेकर अब तक पांच बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। 1979 में आपको 880 करोड़ मिले जबकि अन्दाजा था 1,170 करोड़ मिलेंगे। उस के बाद 8-6-1980 को आप ने बढ़ाया— अन्दाज था कि 2466 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन 2080 करोड़ मिला। उस के बाद 13-1-1981 को बढ़ाया, अन्दाज था कि 1600 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन 1195 करोड़ रुपया मिला। उस के बाद 10-7-1981 को बढ़ाया और अब फिर बढ़ाया जिससे 800 करोड़ रुपया मिलेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक चीज बन गये हैं। इन का दाम बढ़ाने से तमाम चीजों पर उस का असर पड़ता है। यातायात के दाम बढ़ जाते हैं, फ्रेटचार्जेज बढ़ जाते हैं, किसान का डीजल का खर्चा बढ़ जाता है। आप कहेंगे कि इस का सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री से क्या सम्बन्ध है ? आप का सम्बन्ध अनाज के साथ है, इस लिये इन चीजों के दाम बढ़ाने की जो नीति चल रही है उस का सीधा असर अनाज पर पड़ेगा, इस लिये इस पर आप को ध्यान देना चाहिये।

कहा गया है कि बहुत से लोग हाई स्पीड डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट करते हैं, इस लिये उस का दाम बढ़ाना जरूरी है। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार की नीति इस तरह की होनी चाहिये कि हाई स्पीड डीजल की कीमत कैरोसीन से भी कम रखें जिस से लोग मिलावट न कर सकें। इस नीति का दूसरा लाभ यह होगा कि अनाज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आप ने मिट्टी के तेल के दाम जो 10 पैसे बढ़ाये हैं, वे आप को वापस लेना चाहिये, क्योंकि आप ने पहले ही 9 पैसे बढ़ा दिये हैं। इस लिये आप ने 10 पैसे बढ़ा कर कोई अच्छा काम नहीं किया है।

अनाज के जो गोडाउन्ज आज देश में हैं उन की पूरी जांच होनी चाहिये। ता० 21 को महाराष्ट्र के सिविल सप्लाइज मिनिस्टर ने बतलाया कि महाराष्ट्र के गोदामों में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण 16 करोड़ रुपये का अनाज खत्म हो गया।

It is not now fit for human consumption.

यह जवाब उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेचर की मीटिंग में दिया है। धूलिया में ज्वार का सत्यानाश हो गया, 75 लाख रुपये का नुकसान हुआ। परसों हरियाणा की बात भी सामने आई थी। अलग-अलग जगहों पर हम देखते हैं कि अनाज रखने का तरीका ठीक नहीं है—पिलफरेज होती है, चूहे खा जाते हैं, इन कारणों से एक तरफ तो अनाज कम होता है और दूसरी तरफ माल चोर-बाजारी में चला जाता है और तीसरी तरफ लोगों तक ठीक से नहीं पहुचता है। अन-फिट-फार-ह्यूमन-कंजम्पशन कह कर, जानवरों को देते हैं।

पिछले साल आप ने 4 मिलियन टन अनाज विदेशों से इम्पोर्ट किया। जनता पार्टी के राज्य के समय हमें ऐसा

लगता था कि आगे चल कर हम अनाज को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस समय उल्टी बात हो गई है । आस्ट्रेलिया से आप ने जो गेहूं लिया है । उसके बारे में आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा था कि उस पर पेस्टीसाइडस स्प्रे किया गया है, इस लिये उस को धो कर खाना चाहिये । यह सवाल मैंने लोक सभा में उठाया, जबाब आ गया कि इसीलिये भीगा हुआ गेहू खरीदा है, लेकिन उस पर भी फंगस पैदा हो गया । बाद में खबर आई कि उस को किसी को नहीं देंगे लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अलग-अलग राशन की दुकानों पर वह भीगा हुआ गेंहूं दिया गया । पिछले दिनों दिल्ली को राशन की दुकानों पर जो गेंहू दिया गया मैं उस का नमूना भी लाई थी, लेकिन बैलेट में नहीं आया इस लिये नहीं रख सकी ।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिये आप कहते हैं —1980 तक आप ने 2.81 लाख दुकानें खोलीं हैं । दुकानें तो आप ने खोल दीं, लेकिन उन पर राशन कहां है ? लोग उन दुकानों पर जाते हैं–एक बार में सब चीजें नहीं मिलती हैं, एक बार एक चीज मिल जाती है दूसरी बार दूसरी चीज मिल जाती है, 15 दिन खत्म हो जाते हैं लेकिन सारी चीजें नहीं मिल पातीं । बार-बार सरकार के पास लोगों को जा कर कहना पड़ता है कि हमें अनाज नहीं मिला है, इसलिये दूसरे समय में देने की व्यवस्था करें ।

दिल्ली शहर में चुनाव होने वाले थे । चुनाव का ऐलान होने के बाद हजारों की संख्या में लोगों को राशन कार्ड दिये गये और कहा गया कि सब को अनाज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला । लोगों को राशन कार्ड तो दे दिये गये लेकिन दुकानों पर अनाज नहीं था । कहते हैं दिल्ली शहर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाजी मस्तान है, उस की 76 लाख रुपये की प्रापर्टी है । पुलिस ने उस को पकड़ा था, लेकिन आगे चल कर क्या हुआ मुझे पता नहीं है । लेकिन यह दिल्ली की हालत है, केपिटल की हालत है । राशन की दुकानों पर चीजें नहीं मिलती हैं । फेअर प्राइस शाप्स वाले फूड कारपोरेशन से अच्छी चीजें खरीद कर लोगों को गन्दी चीजें देते हैं । जो चीजें सरकार अच्छी देती है वह भी लोगों को नहीं मिल पाती है । इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि आपको ऊपर से ले कर नीचे तक विजिलेंस कमेटियों की व्यवस्था करनी चाहिए । उनमें आपको व्यापारियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके वैस्टेड इन्ट्रेस्टस रहते हैं । इन विजिलेंस कमेटियों में आपको कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को रखना चाहिए । इनमें मेन्यूफेक्चरर के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी हो सकते हैं ।

आपकी वनस्पति आयल की कीमत कौन तय करता है ? गवर्नमेंट और मेन्यूफेक्चरर मिल कर तय करते हैं । इसलिए आपको मेन्युफेक्चरर के प्रतिनिधियों को लेना चाहिए । इतने सालों से ये बातें चल रही हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । अभी तक हम अपनी प्राइस पालिसी तय नहीं कर सकते हैं । मार्जिन आफ प्राफिट क्या होना चाहिए, इस बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं कर सके हैं ।

कहा जाता है कि जगह जगह पर चोरी चल रही है । यहां कहा गया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी अच्छी हैं, बाकी और लोग भी अच्छे होंगे लेकिन चोरों का समर्थन कौन लेता है ? इसी से हम अपनी प्राइस पालिसी को तय नहीं कर पाते । अगर आपको कंज्यूमर्स को फायदा

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

पहुंचाना है तो आपको कंज्यूमर्स मूमेंट को बढ़ाने के लिए मदद करनी पड़ेगी । आप कितना ही अच्छा काम करें, सरकार कितना ही अच्छा काम करे, लेकिन व्यापारी की नीयत को आप ठीक नहीं करते हैं तो लोगों को फायदा होने वाला नहीं है । इसलिए आपको कंज्यूमर कमेटिया बनानी चाहिएं ।

आज पूरे देश में गन्दा खाना खा कर कितने बच्चे अन्धे हो जाते हैं, मर जाते हैं । 40 हजार बच्चे अन्धे हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए आपको कदम उठाने चाहिएं । यह सब काम करने के लिए आपको कंज्यूमर मूमेंट को खड़ा करना होगा । इसके लिए आप कदम उठाएं ।

जनता पार्टी के राज में खाद की कीमत कम कर दी गयी थी इसलिए हमारे देश में अनाज की पैदावार बढ़ी । उसके बाद फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ने लगी जिससे फर्टिलाइजर की कंजप्शन कम हो गयी । इसी से हमारे देश की पैदावार पर असर पड़ा । आपने सिक्सथ फाइव इयर प्लान में 154 मिलियन टन का टार्गेट फिक्स किया है । आपका सिक्सथ फाइव इयर प्लान खत्म होने जा रहा है । आपने पिछले साल दस मिलियन कम का टार्गेट फिक्स किया । आप हम लोगों को 154 मिलियन टन अनाज नहीं दे सकते। बल्कि होना तो यह चाहिए था कि यह टार्गेट दुगना होना चाहिए था । यह टार्गेट कम से कम 200 मिलियन टन का होना चाहिए था जिसको कि पूरा करने के लिए लोग लगते ।

हमारे देश में अनाज कम क्यों हो रहा है ? इसलिए हो रहा है कि किसान को उसकी पैदावार की रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिलती है । उसके इनपुट्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से उसको कीमतें नहीं मिलती हैं ।

मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि कृषि मंत्री जी ने एक कालिंग अटेंशन के समय यहां पर यह मंजूर किया था कि अमेरिका से जो हम गेहूं मंगाते हैं उस पर 230 रुपये क्विन्टल का खर्च आता है जबकि हम अपने यहां के किसान को 142 रुपये देते हैं । इसीलिए आज किसान कम पैदावार कर रहा है । फर्टिलाइजर की कंज्म्पशन कम होती जा रही है । अगर आप किसान को उसकी पैदावार की रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं देते तो किसान अपनी पैदावार को नहीं बढ़ायेगा ।

आज हमारे चीनी के कारखाने वाले कहते हैं कि वे बहुत क्राइसिस में हैं । शूगर इंडस्ट्री हमेशा क्राइसिस में रहती है । आज उनका यह कहना है कि वे गन्ने की कीमत नहीं दे सकते हैं । इंडस्ट्रीज बन्द हो जाएगी इसलिए गन्ने की कीमत कम कर दीजिए । आज ये लोग किसान का नाम लेते हैं । उस वक्त इन्हीं लोगों ने कहा था कि —"We release all this." मार्केट में फी कर दीजिए । इससे चीनी की कीमत कम हो गई । मैं खुद उस डेलीगेशन में थी । हम लोग किसानों के साथ थे । किसानों ने गन्ने की उचित कीमत की मांग की । सरकार ने कहा कि अगर मिल मालिक गन्ने की उचित कीमत नहीं देंगे तो सरकार देगी । लेकिन तब तक सरकार गिर गई । बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं । जब तक किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं देंगे तब तक आप किसान को अधिक अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकेंगे ।

इंपोर्टेड फर्टीलाइजर का कोटा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मार्च तक नहीं आया । इससे वे जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं कर सकेंगे । जून तक किसानों को खाद मिल जाना चाहिए । किसानों को समय पर खाद मिल सके इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आम जनता की भलाई के लिए चलाय जा रहा है । इसको किस प्रकार सुविधाजनक बनाया जाए इसके लिए आपको एक कमेटी बनाकर सोचना होगा । इस सिलसिले में महिला दक्षता समिति ने एक सेमीनार किया था । उसमें एक सुझाव दिया गया था कि इस तरह की एक बास्केट होनी चाहिए कि गरीब लोग जिस जगह पर काम करते हैं उनको वहीं पर उनकी जरुरत का सामान दिया जाना चाहिए । उनके लिए उचित दर की दूकानें वहीं पर खोली जानी चाहिएं । इसके लिए गांवों और शहरों के लिए अलग-अलग तरह की व्यवस्था करनी होगी । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

आज कल होल सेल प्राइस इंडेक्स का और रिटेल प्राइस इंडेक्स का कोई संबंध नहीं है । होलसेल प्राइस 3.5 और रिटेल प्राइस इंडेक्स 9 85 प्वाइंट बढ़ता है । ऐसा क्यों है ? इसी प्रकार जब होलसेल प्राइस बढ़ती है तो रिटेल प्राइस फौरन बढ़ जाती है । दूकानदार कहता है कि होलसेल प्राइस बढ़ गई है। लेकिन जब होलसेल प्राइस कम होती है तो वही दूकानदार कहता है कि हमने पहले से खरीद रखा है इसलिए अभी हम कीमत कम नहीं कर सकते । इसको दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाने वाले हैं ।

अंत में एक बात और कहना चाहती हूं । कंज्यूमर्स आर्गनाइजेशंस को आपने पिछले साल सिर्फ 65000 के लगभग रुपए दिए थे । मैं भी एक आर्गनाइजेशन से संबंधित हूं । साल के शुरू में ही एप्लीकेशंस दे दी गई थीं । उस वक्त कहा गया कि अभी पालिसी तय नहीं हुई हैं, गाइड लाइंस नहीं आई हैं । दो चार महीने बाद दिल्ली-एडमिनिस्ट्रेशन में गए वहां से भी कोई जवाब नहीं आया । 15 मार्च तक कोई जवाब नहीं आया । इसके लिए पत्र भी लिखा है ।

आप कन्ज्यूमर्स आरगेनाइजेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं लेकिन नाडार जैसी कन्ज्यूमर्स आरगेनाइजेशन बनाने की ताकत इस देश के लोगों में नहीं है । अगर हमें बनानी है तो सरकार को चाहिए कि वह पूरी तरह से मदद करे । इसके लिए आप कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं ।

कल 31 मार्च है । आप कहेंगे कि हम सारा पैसा वापिस कर देंगे । आप ऐसा मत कीजिए बल्कि उनकी मदद करने की ओर ध्यान दें । कन्ज्यूमर्स मूवमेंट की बहुत जरूरत है । इसके लिए आप अवश्य कदम उठाइए । विजीलेंस कमेटी आप कब बनायेंगे और किस प्रकार के कदम उठायेंगे, यह मैं जानना चाहती हूं ।

एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में आप छोटी-छोटी मिरची बेचने वालों को पकड़ते हैं लेकिन बड़ी मिरची वालों को कुछ नहीं कहते ।

श्री मधु दंडवते : बड़ी मिरची वालों को कोई हाथ नहीं लगाता ।

श्रीमती प्रमिला दंडवत : मेरी प्रार्थना है कि शुगर के बदले आनज इम्पोर्ट करके इस देश के भूखे लोगों को आनज देने की व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं ।

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): Hon. Deputy-Speaker, Sir, before I start my speech in this debate on the Demands for Grants of the Ministry of Food and Civil Supplies, after hearing the speeches preceding mine, those of Shrimati Dandavate and Shri Vyas, I am reminded of one thing. A major component of food management policies concerns procurement, public distribution, maintenance and operation of buffer stock etc., and the main responsibility of our Minister is to see that food is sent to the scarcity pockets, to the poor and downtrodden people, the middle classes and the other people in the areas hit by natural disasters. The main policy is of Jagannath Sanskriti. The main policy of food management is Jagannath Sanskriti. By seeing our dynamic Minister, I am reminded of one sloka:

सर्वेभवन्तु सुखिना सर्वेसन्तु निरामाया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित दुःख भाग भवेत ।

So, my hopes and aspirations will not be exaggerated if Mr. Bhagwat Jha Ajad fulfils my demands. If you had heard his speeches when he was not a Minister, that is, when he was not in office, you will find that he believes in socialism. He believes in public distribution system, which is essential for the country and it is the moral obligation of the people in the Ministry to do it effectively.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Azad himself is a socialist; not a question of believing.

DR. KRUPASINDHU BHOI: Yes, he believes in socialism, to help and solve the problems of the down-trodden, the have-nots, the *adivasis*, the Harijans, the industrial workers and the middle class people. So, how is procurement being done now? What is the percentage of procurement? The thinking of the Food Ministry seems to be that they are not responsible to distribute food to meet the requirements of the villages, or even some urban sectors where there is deficiency. They only have some arrangement to partially supplement the supply. So, they are procuring only 12.5 per cent of the total food produced in the country. Mrs. Dandavate analysed it and said that in 1978-79 the *per capita* grain availability was 480 grams and now it has been reduced to 460 grams. What about availability of calories? In terms of calorific value it has not been reduced because of the dynamic management of the food policy by the present Government. She said that according to a report by a nutrition expert, 30 lakh children will suffer from mal nutrition and blindness disability. The Government is trying to combat these deficiencies through Anganbari Programme supplying nutritional value food to the children and the expectant mothers. It is the duty of every Member of Parliament and State Legislators to see that this Programme is implemented effectively and the food goes to the needy.

If you go through the speech of the initiator of the debate, Mr. Lawrence, you will be surprised to note that he has not talked about the food policy of the Government of India, but he has criticised the land ceiling implementation policy of different State Governments. His Government was there in Kerala. There are several estates of rubber and coffee plantations. Why have they not implemented the land ceiling there? There are still big zamindars holding thousands of acres of land.

The Department gives a very rosy picture in its report. They must recall the time from 1971 to 1976. That was an era of discipline in all fields including food management and public distribution system also. At that time ,the State Governments were dependent upon panchayats, panchayat samities and cooperative sector. Mrs. Dandavate narrated that vigilance committees should be set up. Such committees were there during that period, consisting of one Adivasi, one Harijan and three persons from other castes. Some other committees were also there at that time. The management system was so magnificient. Now, more than 2.81 lakh retail outlets are there throughout the country. The Minister is also convinced that more than 70 per cent of the public distribution system is managed by the pri-

vate people. Why not we control this system through public sector, different corporations, cooperative societies, panchayat and panchayat samities? There are so many items which can be sold through public distribution system.

About edible oil, except one or two districts in Orissa, nobody has received a drop of edible oil. Who will check this irregularity? Is it not the responsibility of the Central Government also to monitor that the food stocks which have been supplied by the Centre, goes down to the retail shops and the consumer gets it?

About Vanaspati Ghee, edible oil etc.,— people are getting kerosene now, I have got no problem to complain about it— there are complaints: Sugar also, due to the present dual pricing policy is available to people; there is not much difficulty. But, about rice now-a-days, there are complaints. What is the total amount of rice now distributed through the public distribution system? I want to know it. What is the per capita distribution in the present state of affairs? The per capita consumption has decreased and nobody has mentioned it? Also, population is increasing at the rate of 2.45 per cent per year. But the production of foodgrains is not increasing at the rate. In 1978-79 only 131 million tonnes of foodgrains were produced. Now the production is only 133 million tonnes, according to the last year's figures. This year, it will be still less because of droughts, floods, cyclone and other natural disasters. Definitely it will be decreasing. What is the percentage of increase? Has irrigation also increased correspondingly? The percentage of irrigation has, of course, increased. If you take the figures from 1978 to this year, per year, it comes to 2.3 million hectares, So, the percentage of irrigation has increased. But the fertilizer consumption has not increased to that level. But what is the defect in the monitoring system? The Minister should see to it that the agriculturist is given a fair price, and look into the deficiencies.

Shrimati Dandavate mentioned about the reduction in the rate of fertilizer. We are getting nephtha from off-shore and on-shore drilling also. Why should the Government not consider this fact and ensure that in future the rate of fertilizer is reduced? Otherwise, the agriculturist cannot cope with this.

About procurement, I want to mention one thing. A few years back the State Governments were procuring the foodgrains and there was lot of *hullagulla*, So, my only request to the Government is that the F.C.I. should be the only agency to procure rice, wheat and other foodgrains.

The prices of pulses are going down. The main reason is that the agriculturists are not getting adequate remunerative prices for the pulses produced by them. The State Governments and the cooperative cocieties are not coming forward to purchase pulses from them. So, if the production of pulses is not enhanced, and if more incentive is not given, then we will not get enough proteins, i.e., the non-animal protein. Definitely, the calories will be reduced. Therefore, my suggestion here is that instead of having several agents of the Food Corporation of India, the FCI should procure grains from the block headquarters and the FCI should procure the pulses also. The Agricultural Prices Commission has fixed the rate for wheat and rice but it is on a low footing. because, whenever FCI takes up procurement, generally the rate the consumer gets is higher than the rate fixed by the Agricultural Prices Commission. Actually, the millers are the agents of the FCI. In Orissa, for example, the rate of paddy procurement is about Rs. 125 to 128 per bag, that is a bag of 75 kg. How can the agriculturist give the levy rice or levy paddy to the FCI at the prices fixed by the Government? How is it going to benefit the consumer? So, my suggestion here is the Minister should take up this question and the procurement must be increased from 12.5 per cent to at least 20 per cent, so that the agriculturist gets more money, the consumers also will be benefited, because through the public distribution system he can get more foodgrains. This is one of my suggestions.

(Dr. Krupasindhu Bhoi)

14.00 hrs.

The country is facing a very worst condition of drought. More than 310 million people are suffering and more than half of the land is facing this drought condition and still our target of food procurement is not less. On that day there were an Adjournment Motion from the Opposition because it seems that they are not interested to give concrete suggestions to the Food and Civil Supplies Minister to come to the rescue of the drought victims but they want to have a political propaganda on the Floor of the House so that it will go to the Press and their electorate will hear that our People have shouted. They should have been present here today .... (*Interruptions*).

Well Madam, just hear me. I am coming to your rescue. Why do you bother?.... (*Interruptions*).

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): How can he say that it is for publicity? When our people are starving, we have to raise the questions here and he says it is for publicity.... (*Interruptions*)

DR. KRUPASINDHU BHOI: Nobody is interested to give concrete suggestion to the Minister.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: This kind of things will not do. Are you talking for publicity?

DR. KRUPASINDHU BHOI: No, never.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN. Only you are not talking and we are all people who talk for publicity. How can you say like that?

DR. KRUPASINDHU BHOI: When your turn will come, you will answer, what is there?

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: No such small talk.

DR. KRUPASINDHU BHOI: No small talk, this is a fact. On railway accident you were shouting but nobody was present during the Railway debate. This is our moral.

So, Sir, Orissa also is now facing severe drought and last year cyclone, flood and all types of natural disasters were there. What is the criterion fixed by the Food and Civil Supplies Department for supplies through public distribution system and through different works? We know that the population of one State 2.85 crores and Orissa's population is also the same. The Ministry of Food and Civil Supplies is giving 90,000 to 1,00,000 tonnes per month to that State. Only West Orissa is a rice producing area, other parts of the State are deficient areas. The Food and Supplies Ministry is supplying only 22,000 tonnes per month. So, it is the demand of our State Government to make it at least 60,000 tonnes per month so that the rice, wheat and other essential commodities reach the drought-stricken people.

Another suggestion by my friend Mrs. Dandavate was about Food-for-Work Programme and ERRP programme. It is a very good programme. The Central Government is giving money to the State Government for flood, drought cyclone relief and rehabilitation reconstruction programmes. Why not a part of that money be channelised through FCI or the Ministry so that more food is given to different States? So, that is one of my suggestions.

Then about the storage, Mrs Dandavate has alleged and many members of Parliament have alleged that due to lack of scientific preservation of food, these things are happening and the FCI is sustaining loss of few crores in each year due to a lack of scientific preservation. These dates are there but how many private people are engaged in storage? So, why not the Ministry should approach the Finance Minister and the Planning Commission for providing the space required by FCI to store a minimum of 26 million tonnes of foodgrains? Because, scientific storage is a must for linkages. Now there are shortages for which the FCI people are criticised. I want to know

how many people have been prosecuted in the FCI for negligence, for supplying people food which is not fit for human consumption. I want to know how many of them have been thrown out. I hope the Minister will look into the matter, take some exemplary measures and see that the back sheep are thrown out.

Coming to edibe oil, so far as vanaspati is concerned, there are 93 factories in the country. But, so far as Orissa is concerned, there is not even one single vanaspati factory. I congratulated the Minister for the policy decision of the Government that in future licences will be given only to the co-operative sector, and not to private people. Already a licence has been given to Orissa for a factory in the co-operative sector. The Government of Orissa has decided that it should be located in the district of Bolangir, which is one of the 85 districts selected by the Ministry of Industries, where there is no industry. The vanaspati factory should come up in that district immediately with the help of the Apex Co-operative Marketing Federation of Orissa. I do not know whether they have given a proposal for it. It is also the desire of the people that the State Government should recommend another factory in the district of Kalahandi where 30 per cent of indigenous raw material will be available.

Last but not the least, I must congratulate the Department for their performance in two or three fields. The Modern Bakeries, during the Janata regime, reserved the production of certain items like biscuits for the small scale sector. The Government should see that the Modern Bakeries expand and have their units throughout the country, because their performance was magnificent. In 1981-82 they earned a profit of more than Rs. 2 crores and in 1982-83 also they earned Rs. 1 crore as profit.

Then Rasika is another product which the Government should encourage. Instead of giving encouragement to different types of Colas, they should encourage Rasika type of fruit industries. In that case, the production of fruit can be diverted for making Rasika, which has food value.

Shrimati Dandavate raised so many pertinent questions. Of course, she has also appreciated the difficulties of the Department. She has given many good suggestions. Here I want to impress upon the Minister the chronic problem of Orissa. The main thrust of our demand is that the only organisation for procurement should be the FCI. Now the Food Ministry have given permits to parties in other States to purchase foodgrains from Orissa. We say that this should be canalised through the FCI, because it has got the marketing organisation in different States and people have got faith in it. If there are some black sheep, who are responsible for giving it a bad name, you should remove them so that the organisation can function efficiently.

SHRI N. SELVARAJU (Tiruchirapalli): Mr. Chairman, on behalf of my Party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to say a few words on the Demands for Grants of Food and Civil Supplies Ministry.

I am really happy that after all, Civil Supplies has come to its proper place from Civil Aviation. I am also glad that the former Minister for Civil Aviation and Civil Supplies has become the Minister for Food and Civil Supplies. The other day I read in the newspaper a news item that the Secretary, Civil Supplies Department, could not cope up with the dynamism of the Minister and he was wanting to be relieved of his post. I am sure that the dynamism of the hon. Minister would reflect in the widening of the public distribution system in the country which is vital for the poor people. There was an omnibus Ministry such as Agriculture, Irrigation, Rural Development and Civil Supplies. With a view to ensuring efficiency of all the four Departments, they have got independent Ministers. Of all these Ministers, our Minister has got an important charge and he has to manage the affairs of the Food Corporation of India, which is entrusted with the procurement of foodgrains in the Central pool and also with the export of rice to

[Shri N. Selvaraju]

Soviet Russia. He has to face a lot of difficulties. Regarding the Food Corporation of India so many Members have spoken about the mismanagement of its affairs. The annual food subsidy being given is Rs. 750 crores. This is not sufficient to give remunerative price to the farmers. When I say 'remunerative price' to the agriculturists, it is my duty to emphasise more price for paddy. Now, the Government of India is giving Rs. 142 per uintal for wheat and at the same time Rs. 110 per uintal for paddy. This is the high injustice done to the farmers of South India in general, and in particular, farmers of Tamil Nadu who are mainly cultivating paddy. I learnt that the Tamil Nadu Government has recommended Rs. 155 per uintal for paddy. Even this is not sufficient taking into account all the inputs necessary for cultivating paddy. I request the hon. Minister to fix Rs. 200 per uintal for paddy. Then only paddy cultivators will be inclined to continue paddy cultivation without switching over to the cultivation of cash crops. For this, I suggest that the Agricultural Prices Commission should also be brought under the Ministry of Food and Civil Supplies. Then only there will be effective coordination in the procurement of foodgrains after giving remunerative prices to the farmers.

In 1983-84 a sum of Rs. 10,000 crores has bee allotted for implementing hon. Prime Minister's 20-point programme. In the 20-point programme, the 17th point is opening of more fair price shops for strengthening the public distribution system. I have to point out here that the public distribution system is effective only in the metropolitan cities and in the municipal towns. This can be judged by the number of fair price shops available in the urban as well as rural areas. The Tamil Nadu Chief Minister, Mr. M. G. Ramachandran, has proclaimed from the house-tops that his Government is implementing the 20-point programme of the Prime Minister more effectively than any other State. From 7000 fair price shops, it is reported that the number has gone up to 17,000.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central): Only in the papers it is reported, but it is not implemented. MGR has more publicity.

SHRI N. SELVARAJU: It is a fact. In Tamil Nadu, the population is about 5 crores and there is only one fair price shop for every 3000 people. This is not sufficient. At least for every 1,000 people one fair price shop must be provided. If the fair price shops are equally distributed throughout the State, only then we can tide over the present difficulty.

In the rural areas we do not have any fair price shop at all. In the fair price shops essential commodities are not at all available. In their shops only soaps and such other minor items are available.

DR. A. KALANIDHI: The same situation prevails every where—it may be rural or urban area.

SHRI N. SELVARAJU: In the fair price shops essential commodities like rice, edible oils, kerosene, sugar, are not at all available. I am told that in the fair price shops the prices sometimes for certain commodities are more than the prices of the commodities in the open market.

Recently I have visited more than 200 villages in my Constitutency. Most of the people complained to me that they are supplied only one kilo rice per card per week. The rice too is not of good quality. It is of bad quality and is not fit for human consumption. Good quality of rice must be supplied.

I was told by some people that they have to cover three to five kilometres to reach the fair price shop to get essential commodities. They have to waste one full man-day. This is a factor which must be taken into account. Fair price shops must be provided near the villages.

If 20 Point Prgoramme is properly implemented, it is possible to provide one fair price shop in each of six lakh villages in this country. More than 70 per cent of our people are living in rural places and they are feeding the entire nation. It is really unfortunate that those who feed

the nation are not really fed. Their essential demands can be met only by opening more fair price shops in the rural places. When you are providing facilities and adding so many luxuries for the people living in the urban areas, you may consider the asperations of the villagers who want to get their essential commodities at fair price.

DR. A. KALANIDHI: Urban people are also not getting the faciilties. I am from the urban area.

SHRI N. SELVARAJU: The Central Planning Commission had admitted that more than 40 crores of people are living below the poverty line. They are mostly from the rural places. Their daily income is not more than even Rs. 1/-. This is the position even after 35 years of independence. It is pathetic. I hope the new Minister will chalk out the programme to eradicate all these irregularities.

Day before yesterday I read in the newspaper that foodgrains worth more than Rs. 100 crores had been spoiled by keeping the foodgrains in the open in Punjab. The FCI has also admitted that 10 per cent of the foodgrains held in stocks are annual loss due to pilferage and due to getting spoiled in stock and being eaten away by rats. This is valued at more than 100 crores. This is because of improper storage facilities. Proper storage facilities must be provided. FCI must construct their own godowns in District Headquarters. We lost so much of foodgrains due to lack of storage facilities. When we are short of food grains we cannot afford to lose so much quantity of foodgrains every year. Drastic steps must be taken to stop the losses.

Tiruchirapalli is known as the granary of Tamilnadu. There is no proper storage facility available there. I request the hon. Minister to instruct the FCI to get a godown constructed in Tiruchirapalli.

Coming to my State, I would say that Tamil Nadu is severely affected by drought. The Centre has also sent a team to study about the drought condition in Tamil Nadu and the Team has studied the situation and submitted a report. I also met the Central Team at Tiruchy and apprised them of the drought condition in Tamil Nadu in general and about Tiruchy district in particular. On 28-3-83, our honourable Prime Minister also visited Tamil Nadu and studied the problem of drinking water and everything in person and she has also granted some relief to the people of Tamil Nadu by way of Rs. 10 crores and also 10,000 tonnes of rice and 6,000 tonnes of wheat. Also, when the Team has come and submitted their report, our hon. Minister promised to send 5000 tonnes of rice and 4,000 tonnes of wheat. I think it has not been sent so far. So, I would like to know from the hon. Minister when all the commitmens in respect of Tamil Nadu would be fulfilled. Besides, the Tamil Nadu Government has requested to send 80,000 tonnes of foodgrains to meet the demands of Tamil Nadu. So, compared to their requirements, I would say that it is a very negligible quantity. The hon. Minister should at least give 75 per cent of the quantity required. Then only we can tide never the situation.

DR. A . KALANIDHI: Sir, while we congratulate the Prime Minister for the generosity..... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN No, no. Just for a while, kindly listen to me.

DR. A. KALANIDHI: Sir, only by way of clarification.

MR. CHAIRMAN: Kindly listen to me first.

(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Kindly listen to me first. Can't you just listen.

..DR. A. KALANIDHI: Only an explanation.

(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: When an hon. Member is on his feet speaking, no prompting is necessary. This is not done. Therefore, very kindly hold your horses. Later, on, when you get the opportunity, you speak.

(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Kindly go on with your speech.

SHRI N. SELVARAJU: There was a controversy about giving foodgrains to the Central pool by the State of Tamil Nadu. I would like to point out that when our beloved leader, Dr. Krunanidhi was the Chief Minister of Tamil Nadu, he had contributed in 1969, 1972 and 1975 when there was surplus. But under the present regime, even though they got surplus in 1979, or 1980 and 1981, they had diverted the surplus quantity to the other State without informing the Centre by engaging a private agency, thereby the Ruling Party added several crores of rupees to their coffers. (*Interruptions*). Tamil Nadu was originally a surplus State in foodgrains, but by improper planing of the MGR Government, is made a deficient State. Even the Prime Minister has pointed out about the mismanagement of the Tamil Nadu Government. By the improper planning and mismanagement of the Tamil Nadu Government, the people of Tamil Nadu should not be penalised. (*Interruptions*).

When there is severe shortage of food, there is every possibility for the Chief Minister of Tamil Nadu to approach the Centre, but instead of approaching the Centre in person, the Chief Minister of Tamil Nadu has resorted to political gimmick by undertaking fast for seven hours, from 10 a.m. to 5 p.m. After taking breakfast, he undertook the fast and he was ready for the evening tiffin by breaking his fast at 5 p.m. So, all the while they wanted to attract the attention of the voers of Tiruchendur Assembly consituency, where a bye-election had to be held. He is not interested in fulfilling the demands of the people. Formerly he was an actor, and with the Government machinery also he still acting to satisfy the people. He did not ask the Central Government to send rice to Tamil Nadu earlier. Even when it was asked in the Rajya Sabha, hon. Minister Rao Birendra Singh told that the Chief Minister of Tamil Nadu was not ready to receive the Central team till March, 1983. And he told that whenever he asked about the requirements of rice for Tamil Nadu, he was keeping mum. It shows clearly that how he is interested about the welfare of the people of Taiml Nadu. Sir, for his mistake, the Minister should not penalize the poor and innocent people. He is diverting the foodgrains to various items. If you come to NREP programme, he is diverting that to Nutrition Programme and other things. He is saying that he is feeding the poor children. But in the name of poor children, the Ruling Party people are minting money. If that scheme is implemented properly and the poor children are served food properly, it is a welcome step. But they are not doing it. Just for the sake of advertisement and for the benefit of the Ruling Party in the State they are implementing this scheme. Now, the number is also reduced to half of its size. For various reasons, people are not ready to send their children to the nutrition meals centres. Now, they have stopped giving food for anoher 90 days.

I would therefore request that the Minister should insruct the State Government to utilise the funds properly meant for the NREP programme and that foodgrains should be distributed properly. There must be a high-level committee with all Party members to regulate or watch the distribution part and the performance of NREP programme.

MR. CHAIRMAN: Now, kindly wind up. I have given you plenty of time and therefore, please conclude now.

SHRI K. MAYATHEWAR (Dindigul): We are badly in need of food. We have no food; no drinking water.

SHRI N. SELVARAJU: They are prepagating that the DMK Party is not for the cause of people and that it is not demanding anything at the Centre for the benefit of Tamil Nadu. So, I want to inform the House that we are continuously demading more rice to Tamil Nadu. Even our leader. Dr.Kalaignar many times requested the Central Government to give more rice and he spoke on the situation in Tamil Nadu in the Assembly also. Our Members of Parliament are jointly and individualy requesting the hon. Minister to give rice to Tamil Nadu because we know the importance of food. There is one proverb in Tamil Nadu that *Unavu Udai, Iruppidam,* (Food, Clothing and shelter) is imporant for the livelihood of the people. They are the three important things for people. We bear his proverb in mind and we are asking for more rice for Tamil Nadu.

On 14-10-1982, our Party leader in Lok Sabha Shri C. T. Dhandapani as well as Shri Mayathevar requested the Central Government to provide rice for Tamil Nadu. The Tamil Nadu Chief Minister undertook 'fast' on 9-2-1983. Our Deputy leader in Lok Sabha Shri Mayathevar met the hon. Minister, and gave the memorandum and requested for rice on 11-2-1983. Even the police of Tamil Nadu prevented us on 28-3-1983 from giving a memorandum to the hon. Prime Minister. Even our M. P. has been assaulted and our leader Dr. Kalaignar was pushed back and manhandled by the policemen. With all the difficulties, we handed over the memorandum to the Prime Minister for the benefit of our people in Tamil Nadu. Madam accepted the memorandum and gave some relief.

I would request you to give immediate relief because we are not only short of food but short of power and drinking water. (*Interruptions*) One bucket of water is being sold at paise 50.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): We cannot give water.

SHRI K. MAYATHEVAR:** We want drinking water.

SHRI N. SELVARAJU: You can give more money for providing drinking water.

The Food Department of Tamil Nadu recently issued one order saying that the persons who are getting less than Rs. 1,000 will be supplied essential commodities at fair price shops. This is highly discriminatory. The middle class people and the persons working in banks and factories will be badly affected. So, I would urge upon the hon. Minister to instruct them suitably that there should not be any discrimination and that they must give equal treatment to all the working class people.

Lastly, I would again request the hon. Minister to give immediate relief to Tamil Nadu by way of rice and money.

With these words, I support the Demands.

MR. CHAIRMAN: Tamil Nadu is a very special case. It was a good speech.

The hon Members are once again requested to be judicious with the time and try to avoid repetition, if they can.

SHRI M. C. DAGA.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, इस गौरवशाली देश के लिये 35 सालों के बाद जिस बात पर चर्चा हो रही है, यह थोड़ा सा लज्जाजनक विषय है । हिन्दुस्तान में 2 लाख 81 हजार दुकानें खोलने के बाद अगर कोई दावे के साथ कह सकता है कि आज गांव के दूर-दूर अंचलों में अनाज पहुंचता है तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी ।

**Not recorded.

[श्री मूल चन्द डागा]

मैं समझता हूं कि जो लोग आज बा। सकते हैं, आर्गेनाइज्ड सैक्टर, म्युनिसिपैलिटीज़ के रहने वाले, आर्गेनाइज्ड लेबर, गवर्नमेंट की सर्विस क्लासिज वगैरह, उनको अनाज मिलता है :

हमारे योजना मंत्री जी बैठे हैं, हमने 20-प्वाइन्ट प्रोग्राम बनाया । पहली बार योजना में यह बात ली गई कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के ज़रिये हम गांव के प्रत्येक नागरिक को हिन्दुस्तान के 68 करोड़ लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्रस्तुत करेंगे । लेकिन आज शर्म की बात है कि खाद्य सामग्री में मिलावट है, जीवन-दायक औषधियों में मिलावट है । यह कोई गौरव की बात नहीं है । आज देश में कौनसी चीज़ ऐसी है, जिसमें मिलावट नहीं है । लोग यह कहते हैं कि अगर ज़हर भी मिलता है तो वह भी मिलावटी है । आप एक बात सोचिये, आपने बड़े अच्छे फोटो निकाले हैं 20 प्वाइंट प्रोग्राम के । इसके एक फोटो को मैं आपके सामने रख रहा हूं——

The extent of public distribution through fair price shops including mobile shops.

मुझे जहां तक जानकारी है, हमारे राजस्थान के गांव के अंचलों में न तो को-आपरेटिव सिस्टम काम कर रहा है और न खुदरा व्यापारी काम कर रहा है, केवल भ्रष्टाचार काम कर रहा है । ईमानदारी की बात यह है कि बहुत कम दुकानें यह धान उठाती हैं । मंत्री जी अभी चले गये हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह उत्तर दें कि जिस भाव से आप धान देते हैं, वह वहां के खुदरा व्यापारी किस भाव पर बेचते हैं ? किरासिन का एक टीन उनको मिलता है । हम लोग यह चाहें कि सस्ते धान की दुकानें खुलें । कल के अखबार में आया है कि दुकानें उनको दी जाती हैं जो एन्फोर्समैंट इन्सपैक्टर से या सिविल सप्लाई आफिसर से मिल जाता है, जो कालाबाजारी करने में होशियार हो, उनको दुकानें मिलती हैं । उन दुकानों के ज़रिये अगर अब चीजों के वितरण की उम्मीद करते हैं कि गांव में यह होगा तो असंभव है ।

सभापति महोदय, आप पंजाब से आये हैं, आपके यहां अनाज का भंडार है, लेकिन मैं एक सूखे प्रदेश से आया हूं जहां गांव में कुछ नहीं मिलता है और दावे के साथ कहता हूं कि कुछ नहीं मिलता है । न गेहूं है, न शुगर है, न केरोसिन है, न कपड़ा है और न वनस्पति है । आपने कहा है कि मोबाइल शाप्स बनाई जायेंगी जिसमें बैठकर चौधरी सुन्दर सिंह जी वितरण करेंगे । मन्त्री जी अपने जवाब में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने खुदरा व्यापारी हैं और उनको एक शुगर की बोरी पर क्या मिलता है । उनको खाली बोरा मिलता है । मिट्टी के तेल में भी सिर्फ पीपा बचता है । क्या यह उचित है ? मैं आपके सामने प्रैक्टिकल बातें ही रख रहा हूं । उस खुदरा व्यापारी को तहसीलदार के पास परमिट के लिए चार बार चक्कर लगाना पड़ता है । इसी तरह से दुकान लेने वालों को सिविल सप्लाईज़ आफिसर के पास अपना नजराना पेश करना पड़ता है । आजकल उसको रिश्वत नहीं, नजराना कहना चाहिए । हमारे मन्त्रीजी बड़े स्पष्टवक्ता हैं, वे सही को सही और गलत को गलत कहते हैं । आपने 17वें सूत्र के आधार पर तथा अपनी नीतियों के आधार पर खुदरा दूकानें खोलने के लिए गाइडलाइन्स दे रखी हैं और एक कमेटी भी बना रखी है जोकि सेक्रेटेरियट में दो महीने में एक बार जांच करती है । आप

वास्तव में बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन देखने की बात यह है कि जनता को अनाज मिलता है या नहीं । मान लीजिए आज मुझे तीन रुपए मजदूरी के मिले, मैं सरकारी दूकान पर जाकर चाहता हूं कि मुझे दो रुपए का गेहूं मिल जाए लेकिन वहां पर कहा जायेगा कि 15 दिन का कोटा एक साथ उठाओ । मेरे लिए पूरा राशन एक साथ उठाना सम्भव नहीं है । ऐसी हालत में वह अनाज कहां जाता है ? आप सारी बातें जानते हैं कि इन दुकानों को वही ले सकता है जो काला बाजारी करता है या जो सिविल सप्लाईज़ और एन्फोर्समेन्ट आफिसर के साथ मिला हुआ है । इसलिए इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं कि इतने लाख टन गल्ला बांट दिया गया । मैं समझता हूं यह राशन उन लोगों के लिए बन्द कर देना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है । मन्त्रीजी ने लिखा भी है कि वीकर सेक्शन्स और समाज के अन्तिम व्यक्ति को हम अनाज देंगे । बीस रुपया रोजाना कमाने वाले को यह अनाज भले ही न मिले लेकिन जो केवल 4–5 रुपया रोजाना कमाते हैं उनको जरूर मिलना चाहिए । आपने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 39 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनके पास पास क्रय शक्ति नहीं है । जहां पर फेमीन है वहां पर जो काम चलते हैं उनमें महीने के बाद पैसा चुकता किया जाता है और वहां पर आपकी दूकान नहीं है । राजस्थान में जहां हमेशा ही अकाल पड़ता रहता है वहां आप ने मोबाइल शाप्स चलवाई है। कल के अखबार में नवभारत टाइम्स में आप ने पढ़ा होगा क्योंकि वह आपके विषय से सम्बन्धित था कि जिन-जिन लोगों को राशन की दुकानें दी गई थीं, वे ईमानदार लड़के छोड़ कर चले गये। क्यों छोड़ कर चले गये ? आप बतलाइये— जो चीजें इन दुकानों पर दी जाती हैं क्या वे स्टेण्डर्ड की होती है? सब–स्टैण्डर्ड की होती हैं — चूंकि आप के इंस्पेक्टर मिले होते हैं चाहे आप के डिपार्टमेन्ट के हों या हैल्थ डिपार्टमेन्ट के हों — कुछ नहीं होता है। मैं राशन की ही बात नहीं करता, हर चीज में मिलावट होती है। आज देश के अन्दर आप को हर खाद्य पदार्थ में मिलावट मिलेगी — यह इस गौरवशाली देश के लिये बहुत लज्जा की बात है। आप का डिपार्टमेन्ट इस को सख्ती से नहीं ले सकता क्योंकि आप के सिविल सप्लाई अफसर या इंस्पेक्टर या फूड इंस्पैक्टर सब मिले होते हैं।

आज हमारे क्षेत्र की हालत क्या है। हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें केरोसीन आयल नहीं मिला, चीनी नहीं मिली । यह कन्ट्रोल क्लाथ, जनता का कपड़ा किस को मिलता है? कौन हिम्मत के साथ कहेगा कि मुझ को मिल गया है? आपने जो निर्णय लिये हैं— आप जरा उन निर्णयों को पढ़ें । उनको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि मंत्री महोदय कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप का जवाब आता है —

To make a thorough assessment of the situation to ensure proper and adequate supply of essential commodities through retail outlets to remote and inaccessible areas...."

अरे, भगवान के नाम पर सड़क पर ही पहुंच जांय तो ठीक है कहां इन एक्सेसिविल एरियाज की बात करते हैं। ये फोटोज देख कर बड़ी खुशी हुई कि हमारी मोबाइल शाप्स बहुत अच्छी चल रही हैं। यह भी कहा गया है कि ब्लैक मार्केटियर्स की दुकानों को बन्द कर दिया गया है। लेकिन बन्द करने वाले कौन हैं? मैं फिर रिपोट करता हूं —ये खुदरा व्यापारी, कोआपरेटिव सोसायटी वाले जो शुगर और गेहूं का वितरण कर

[श्री मूल चन्द डागा]

उन के लिये मंत्री महोदय बड़ा सटीक उत्तर दे देंगे कि डागा बकवास करता है, वितरण का काम राजस्थान सरकार का है, मेरा काम नहीं है । . . .

श्री भागवत झा आजाद : आप बतलाइये यह गलत है या सही है ?

श्री मूल चन्द डागा : लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं और आप के यहां वह कमेटी होती है इस लिये आप भी उस के लिये जिम्मेदार हैं आप उस कमेटी को हैण्डिल करते हैं . . . .

श्री भागवत झा आजाद : आप भी इलैक्टेड मेम्बर हैं इस लिये आप भी जिम्मेदार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो एडवाइजरी कान्सिल है उस के आप अध्यक्ष हैं। एक बात और बतलाता हूं—जो आप की शुगर को बांटने के लिये ले जाता है उस को एक बोरा बांटने पर क्या मिलेगा ? एक जो टिन केरोसीन ले जा कर बेचना चाहता है उसे आप क्या देंगे—यह बतला दीजिये चूंकि उस को उचित पैसा नहीं मिलता इस लिये पैसा कमाने के लिये वह गलत काम करता है।

हमारे पास आंकड़े है कि करीब 1 करोड़ 85 लाख आदमी प्रति वर्ष विकलांग इस लिये बनते हैं कि उन को प्रापर डाइट नहीं मिलती, उन के अन्दर मैल-न्यूट्रीशन होती है, आवश्यक कैलारीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है। सरकार फूड कारपोरेशन को सब्सिडी देती है और सब्सिडी देकर उस सफेद हाथी को जिन्दा रखने की कोशिश करती है, उस को सांकल लगा कर रखती है । मैं कहना चाहता. हूं कि मेहरबानी कर के उस के अन्दर की व्यवस्था को ठीक कीजिये। लेकिन ऐसा करना आप के लिये इम्पासिबिल है क्योंकि स्ट्राइक, चोरी करना यह फूड कारपोरेशन का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है । उस की किसी भी चीज को ले लीजिये अभी पांडे जी जो कह रहे थे, समय कम होने से मैं उस को रिपोट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आप देखिये मेरे यहां पाली से गेहूं लिया, उस को उठाकर जयपुर ले जातें हैं । मेहरबानी कर के, मैं हाथ जोड़ता हूं इस गेहूं को जोधपुर डिवीजन में ही खर्च करें, उस को वहीं बांट दें। तमाम ट्रांसपोर्ट चार्जिज नहीं पड़े । लेकिन श्रीमन वह गेहूं वहां से जाता है और हमारे लिए गेहूं कहीं और से आता है । हमें जो गेहूं मिलता है उसकी हालत क्या होती है । सैकड़ों कंकड़ उसमें होते हैं । हम से दुकानदार कहता है कि आइये एम० पी० साहब, देखिये यह है आपका गेहूं। हमारे लिये गेहूं नहीं, केरासीन नहीं। हमें इन दुकानों से कंट्रोल का कपड़ा नहीं मिलता और कंट्रोल का कपड़ा बाजार में खूब मिलता है।

श्रीमन् इस से स्पष्ट है कि आपकी नीति अच्छी है, आपके ख्यालात अच्छे हैं, बड़े स्वच्छ और पवित्र हैं लेकिन उनको आप जरा जमीन पर उतारिये। देश के अन्दर. सिवाय केरल स्टेट है जहां कि यह काम हुआ है।

"It is painful to note that the Public Distribution System in India miserably

failed to cover the rural masses. With the exception of Kerala, PDS in India covers only major cities and towns. Foodgrains, edible oils, cooking fuel (kerosene) and other essential commodities are not regularly supplied in sufficient quantities."

श्रीमन् सिवाय केरल के कहीं भी यह सप्लाई ठीक से नहीं होती । आप साल में जो भी दो मीटिंगें करते हैं उनमें आप मंत्रियों से पूछिये, सेक्रेटरियों से पूछिये कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप जा कर के इस काम को ठीक क्यों नहीं करते हैं ?

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): That is why we are not getting rice. We have got a pucca distribution system. That is why the Government is not supplying enough rice to our public distribution system.

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप उन चीजों को भी काम में लो जो चीजें आपके पास रहती है । श्रीमन अशेशल कमोडिटीज एक्ट क्या कहता है ? हमारा रेडियो रोज बोलता है कि जो कोई भी कलाबाजारी करेगा, जो कोई भी मुनाफाखोरी करेगा, उसको सात साल की सजा होगी । मंत्री जी जो आपका रेडियो बोलता है क्या उसके मुताबिक अपने कानून में तबदीली करेंगे ? अगर आप तबदीली करेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि आपके एन्फोर्समेन्ट वाले और सिविल सप्लाई आफिसर मालामाल हो जाएंगे । मैं आपको रिकार्ड से बता सकता हूं कि वही आदमी पकड़ा जाता है जो आदमी सिविल सप्लाई अफसर को पैसा नहीं देता है ।

"The Central Ministry also has issued guidelines to the State Chief Secretaries on expanding fair price outlets in rural and inaccessible areas...."

यह सवाल आज देश में हो रहा है । आप जो भी कानून बनाते हैं, उसका कितना पालन होता है ? आपने ब्लेक मार्किटियर्स के लिए कानून बनाया, उसका क्या हो रहा है ? आपका कोई भी सिस्टम नहीं है । एन० सी० सी० ई० एफ० के दो, तीन करोड़ रुपये कहां जाते हैं ? आपका कारपोरेशन क्या काम करता है ? हम लोग जो बोलते हैं क्या उस पर वह ध्यान देता है ? आप अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को गरीब लोगों तक पहुंचाइये, बिलों पावर्टी लाइन वालों तक पहुंचाइये ।

Only those people who are below the poverty line should get.

अगर आप यह कर देंगे तो मैं कहूंगा कि हमारा यह सिस्टम ठीक है । ।

श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा मानता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं । आपके नियम अच्छे हैं, नीतियां अच्छी हैं, अखबारों में भी खबरें अच्छी अच्छी आ जाती हैं लेकिन मंत्री जी इनको जमीन पर उतारने की मेहनत से कोशिश करिये तभी आप कामयाब होंगे ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोहतरम चैयरमैन साहब, डागा साहब ने सरकार की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है । मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । केवल इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि नीति अच्छी जरूर है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिये है । अमल के लिये नहीं है । इनकी नीयत साफ नहीं है ।

खाद्य विभाग के द्वारा गेहूं, चावल आदि का वितरण किया जाता है । डागा साहब ने इस बारे में काफी रोशनी डाल दी है । मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र और खासतौर पर उत्तरी भारत के किसानों को जो आजकल प्रमुख समस्या

[श्री अशफाक हुसैन]

है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे ख्याल से आप मेरा मतलब समझ गये होंगें । मैं गन्ना किसानों की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी हमारे मित्र पांडे जी कह रहे थे कि आज हमारा देश विश्व में सबसे अधिक शक्कर का उत्पादन कर रहा है । हमें भी इसके लिये फक्र है । लेकिन हम को इस बात पर शर्म आती है कि हम दुनिया में सबसे कम नहीं तो बहुत कम दाम अवश्य गन्ना किसानों को देते हैं ।

किसान मेहनत करता है । उसके उपयोग में आने वाली चीजों, खाद्य, पानी आदि का दाम बढ़ा दिया गया है । डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है । लेकिन जब गन्ने की ज्यादा कीमत की मांग की जाती है तो मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि गन्ने की कीमत के बारे में दोहरी नीति बनाई गई है । पता नहीं मंत्री महोदय इससे सहमत हैं या नहीं । केन्द्र सरकार के अधीन कुछ मिलें चलती है । उनमें अलग दाम दिया जाता था । आपने मेरे ही सवाल के जवाब में बताया था 1980–81 में 19 रुपये से लेकर 22 रुपये, 1981–82 में 20.50 रुपये और 1982–83 में 17.40 रुपये यह कहा जा रहा है कि 17.40 रुपये वाजिब दाम हैं । जब आप इसको वाजिब दाम कहेंगे तो कौन सा प्राइवेट मिल मालिक किसानों को 20.50 रुपये या 21.50 रुपये देगा ।

इसके अलावा सबसे अहम समस्या किसानों को समय पर गन्ने की कीमत का न मिलना है । यह समस्या पिछले तीन-चार सालों में देखने में आई है । इस मामले में बराबर सवाल करता रहा हूं, पत्र भी लिखता रहा हूं कि गन्ना किसानों को उनके पैसे का जल्दी भुगतान किया जाये । जवाब क्या आता है । जवाब यह आता है कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

मैं कहना चाहता हूं कि असेंसियल कमोडिटीज एक्ट आपका बनाया हुआ है । इसके तहत ही शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर 1976 आपने ही बनाया था । उस शुकरकेन कन्ट्रोल आर्डर 1976 में आगे 1978 में एक अमेंडमेन्ट किया गया और सैक्शन तीन में तीन (ए) जोड़ा गया । उसमें यह साफ तौर पर कह दिया है :—

"Where a producer of sugar or his agent fails to make payment for the sugarcane purchased within 14 days from the date of delivery he shall pay interest."

he shall pay interest on the amount due at the rate of 15 per cent per annum for the period of such delay beyond fourteen days. "शल" का लफ्ज है "भे" का नहीं है ।

"Where payment of interest on delayed payment is made, the canegrowers' society shall pay the interest to the canegrowers after deduction of administrative charges, if any, permitted by the rules of the said society."

एसेन्सियल कमोडिटीज एक्ट के तहत शुगर कन्ट्रोल रेट आर्डर है जिसमें यह अमेंन्डमेंट 1978 में लाया गया । मैं बार-बार सवाल करता रहा कि इस एक्ट के तहत किसानों को कब और कितना सूद दिया गया । लेकिन मेरे अगस्त सन् 1982 के सवाल के जवाब में कहा गया कि :—

"The enforcement of statutory provisions of the Sugarcane Control Order, 1966 relating to the payment of interest is the responsibility of a State Government who has the necessary powers and field organisation in this regard."

यह सही है कि नेसेसरी पावर्स उनके पास हैं । लेकिन आप किस लिये बैठे हैं। आप रूल बनाने के लिये नहीं बैठे हैं बल्कि उसको इम्पलीमेंट करने की ओर भी आपको नजर होनी चाहिए। जब आपने सवाल का जवाब इस तरह से दिया है तो मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने पत्र लिखा । मेरे पत्र के जवाब में कहा गया कि आपके प्रश्न का नोटिस प्राप्त होने पर यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था तथापि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश सन्, 1966 के अधीन दिया गया और वे मूल्यवार ब्यौरा समय से न दे सके इस लिये केन्द्रीय सरकार यह सूचना न भेज सकी । लेकिन बाद में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे जिलों से सूचना इकट्ठी कर रहे हैं जिसमें काफी समय लगेगा इस लिये आपको सीधे सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया जाता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं ताकि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं मिली है कि ब्याज और बकाये की रकम किस-किस तरह से दी गई । इस सेशन में मैंने इसी संबंध में सब 21 फरवरी को सवाल उठाया था ।

"As per information available with the Central Government, only a few factories are paying interest to the canegrowers on account of the delay in caneprice payment."

"No further details are available."

साल भर के बाद भी डिटेल एवेलेबल नहीं है ।

"Necessary action in case of infringement of the Sugar-cane Control Order has to be taken against defaulting units by the State Government which has the necessary powers and field organisation."

पांच फैक्ट्रीज आपकी कस्टोडियनशिप में चलती हैं । किसानों को गन्ने का दाम उन पर बकाया रहा है । और आज भी बाकी है ।

श्री चित्त बसु : इन्टरेस्ट दिया या नहीं ।

श्री अशफाक हुसैन : नहीं दिया, यही तो मैं कह रहा हूं । आपने अपने ही कानून को लागू नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट की बात अलग है । आप सूद किसानों को नहीं दे रहे हैं । ये मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक केन सोसायटी है जो दो मिलों को सप्लाई करती है । मैं बेतालपुर चीनी मिल जो देवरिया जिले में है, की बात कर रहा हूं । वह आपके नियंत्रण में चलती है ।

15.00 hrs.

दूसरी मिल प्राइवेट चलती है, उसको बाध्य किया जाता है, और वह देने को मजबूर भी है, देना चाहिए उसे । 20 रु० 50 पैसे वही सोसायटी मांगती है उससे । और वही सोसायटी आपके यहां जो किसान सप्लाई करते हैं उनको 17 रु० 40 पैसे देती है । तो यह अजीब बिडम्बना है कि आपके अधीन चलने वाली मिलों में ऐसा हो रहा है।

अब राज्य सरकार के अधीन चलने वाली जो मिलें हैं जो रिसीवरशिप में चलती हैं या दूसरे तरीकों से चलती हैं, केवल आप यही बता दें कितनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने पहली किस्त का भी भुगतान नहीं किया है किसानों को ? आज 30 मार्च, है । और झगडे की बात आती है आप की तरफ से हो सकता है कि कुछ मिलों के बारे में यह कहा जाय कि सोसायटी को इतना रुपया दिया गया । लेकिन बहुत सी मिलों में झगडा इस बात का है कि वह कहती हैं कि पर्ची

[श्री अशफाक हुसैन]

पर दाम न लिखिए और 80.90 लाख या 1 करोड रु० की क्षमता है मिलों की सोसायटी को दें । सोसायटी से कहा जाता है आप 14, 15 16, इस तरह से एडवांस पैमेन्ट कर दीजिये । इस लिये यह रास्ता आपने दिखाया ।

15.02 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*].

आपने कहीं 17 रुपये 40 पैसे पेमैन्ट दिया है । तो यह भी कहते हैं कि हम क्यों ज्यादा पेमन्ट दें । आपने जो मुझे 16-2-83 को जवाब दिया, तो मैंने अपने पत्र में उनसे यह कहा था और उसकी प्रतिलिपि प्रधान मंत्री को भी भेजी थी और मुझे जवाब दिया गया कि खाद्य विभाग को भेज दिया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है । और मुझे यह जवाब मिला कि भारत सरकार के देश में विभिन्न खंडों में स्थित चीनी मिलों की आर्थिक क्षमता की भली भांति जांच करने के पश्चात् गन्ने का मूल्य 17 रुपये 40 पैसे प्रति क्विंटल लगाया है। इससे अधिक कोई मूल्य उचित नहीं होगा और सरकार के लिये उच्चतर मूल्य अदा करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा । गत सत्र में अदा किये गये मूल्य को इस सत्र की अदायगी के लिये पाबन्द नहीं बनाया जा सकता है । गत सत्र में आपने 20 रु० 50 पैसे दिया । इस सत्र में किस चीज के दाम कम हो गये, कौन से इनपुट्स के दाम में कमी हो गई जो आपने दाम कम कर दिये ? और आप उसे उचित भी ठहराते हैं । यह समस्या है गन्ना किसानों की । क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मार्च का महीना है अभी कही आधा और कहीं तिहाई और कहीं इससे कुछ 60 परसेंट गन्ने की ही पीराई हुई है, बाकी गन्ना खेत में खड़ा हुआ है। हमारे एक मननीय सदस्य ने इस बात की तरफ इशारा किया था । 1978-79, 1979-80 में जनता सरकार के जमाने में गन्ना खेतो में फूंका गया । आप ऐसा न कीजिये कि आप उस रिकार्ड को को भी तोड़ दें । हालत यहीं बता रही है कि आप उस रिकार्ड को तोड़ने जा रहे हैं ।

आप कहेंगे पार साल हमने मिले चलाई जून, जुलाई और अगस्त तक लेकिन मिलें जून, जुलाई, अगस्त तक चलाने में किसका नुकसान होता है ? राष्ट्र का नुकशान होता है क्योंकि शूकरोज का जो कटैट होना चाहिए वह नहीं निकलता है, उससे कम 7 परसेंट, 6 परसेंट ही निकलता है। किसानो को दाम कम मिलता है और गन्ना लकड़ी की तरह जला दिया जाता है मैंने बहुत पहले आपको पत्र के जरिये आगाह किया है, सवाल के जरिये आगाह किया है और आज इस सदन के जरिये आगाह कर रहा हूं कि ऐसी हालत पैदा न होने दें कि आप जनता पार्टी के जमाने का रिकार्ड ब्रेक कर दें और किसानों को नुकसान हो ।

अभी हमारे डागा साहब ने भी अर्ज किया था कि नीति हमारी ठीक हैं । हम भी उस नीति के मानने वाले हैं जो आपने भुवनेश्वर में बनाई थी, जो हमने भुवनेश्वर में बनाई थी । कि टोटल स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन । आपने उस पर अमल नहीं किया । आपने उस नीति को पास तो कर दिया, लेकिन आपकी नियत नहीं है । जब आप अपनी नीति बदलेंगे और नियत बदलेंगे तभी आप कामयाब होंगें । केवल दिखावे

के लिये आप 20 सूत्री कार्यक्रम बनाइये या 25 सूत्री बनाइये उससे काम चलने वाला नहीं है ।

कन्ट्रोल के कपड़े के बारे में दो शब्द इस लिये कहूंगा कि कंट्रोल का कपडा एन० टी० सी० के साथ-साथ हैन्डलूम सैक्टर को दिया गया । जब कामर्स मिनिस्ट्री की डिमांड्स आयेंगी उस वक्त मैं इसकी तफसील में जाऊंगा । यहां तो यह कहना चाहूंगा कि कंट्रोल का कपड़ा, जिसको जनता कपड़ा कहते हैं जो कि कोआपरेटिव के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की बात है, वह जनता तक नहीं पहुंच रहा है । वह कहां पहुंच रहा है ? हमारी कान्स्टीटुएन्सी बार्डर पर है । नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का बार्डर लगता है । यह कपडा हमारे देश की दुकानों पर न जाकर गांठ की गांठ और ट्रक के ट्रक नेपाल में चला जा रहा है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गल्ला, खासतौर से गेहूं की बात में कहता हूं , चावल की नहीं , यह खुले आम नैपाल में जा रहा है । राशन और कंट्रोल का गेहूं खुले आम नेपाल में जा रहा है । हमारे श्री डागा ने इंस्पैक्टर्स की बड़ी दुहाई दी, उनकी खिंचाई भी करनी चाहिए थी लेकिन उनके पीछे कौन सी बातें हैं यह सब जानते हैं।

राशन की दुकानें पोलिटिकल प्रैसर पर दी जाती हैं । पोलिटिकल प्रैसर पर ही नहीं बल्कि पोलिटिकल हिस्से-दारी पर । मैं आपकी निगाह उस पर भी रखना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : नजरे इनायत पर ।

श्री अशफाक हुसैन: हमारे श्री दन्डवते जी ने ठीक ही हां कि नजरे इनायत पर दुकान बटती हैं । मेरा कहना है कि आप परवरिश कीजिये अपनी पार्टी के लोगों की लेकिन इस तरह से कीजिये जिससे जनता को कोई नुकशान न हो ।

(व्यवधान)

अगर में परवरिश करता रहता, तो आपके साथ ही रहता । मैंने यही सही बात कही है, आप सदन में नहीं कह पायेंगे लेकिन बात सही है ।

खाना पकाने की गैस एंसशियल कमोडिटीज में नहीं आती, आप कहेंगे, कि हमारे सबजैक्ट में नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को खासतौर से शहर के लोगों को इस पर निर्भर रहना पड़ता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाना पकाने की गैस भी सही तरीके से तक्सीम की जानी चाहिए । इसको भी एसेंशियल कमोडिटी मान कर चलना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य ने सस्ती कापियों की बात कही है । सस्ती कापियां आजकल खिलवाड़ बनकर रह गई हैं । दामों में बहुत कम फर्क रह गया है । इसका शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्ध है, इस बात को मैं मानता हूं लेकिन आप इसको एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत लाइये इसलिए मैं यह कह रहा हूं ।

अन्त में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आप गन्ना किसानों की दशा की ओर ध्यान दें । आप इस बात का इन्तजाम करें कि उनका सारा गन्ना पेरा जा सके । गन्ना किसानों की एक और भी समस्या है। क्शर के जरिए से जो गन्ना

[श्री आशफाक हुसन]

पेरा जाता है या जिस गन्ने का गुड़ बनता है उसके लिए किसानों को 10-12 रुपए क्वींटल का दाम ही मिलता है। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि केवल आंध्र प्रदेश में ही इस सम्बन्ध में कुछ पाबन्दी लगाई गई है। वहां पर ऐसे गन्ने का एक मिनिमम दाम तय किया गया है। मैं चाहूंगा पूरे देश में जो क्रशर के जरिए गन्ना पैरा जाता है या जिस गन्ने से गुड़ और खण्डसारी बनाई जाती है उसका मिनिमम दाम तय किया जाना चाहिए। पूरे देश के लिए नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर बिहार के लिए भी आप ऐसा न करना चाहें तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए जरूर कोई कीमत मुकर्रर कर दें।

यह चन्द समस्यायें थीं जिनकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था। एक बार फिर मैं इंट्रेस्ट की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अगर 14 दिन के बाद किसानों को इन्ट्रेस्ट मिलता रहे तो मिल वाले किसानों को गन्ने का दाम सही वक्त से देने के लिए मबूजर हो जायेंगे क्योंकि मीटर चलता रहेगा। इसलिए आप मीटर चलाईये ताकि उनको समय पर दाम मिल सके। इसके साथ-साथ आप इस बात की भी हिदायत दीजिए कि जब तक किसानों का पेमेन्ट न हो जाए तब तक किसानों के खिलाफ कुर्की और वसूली भी रोकी जाए। आज की जो हालत है उसमें एक तरफ तो आप किसानों का पेमन्ट नहीं करते हैं और दूसरी तरफ उनसे खाद और पानी की डयूज की वसूली करवाई जाती है और बिजली के कनेक्शन भी काट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया ताकि मैं गन्ना किसानों की समस्याओं को इस सदन के सामने रख सकूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति जी मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह वह मंत्रालय है जिसका सीधा सम्बन्ध इस देश की जनता से है और उसके जीवन से है। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा बालक हो या बूढ़ा स्त्री हो या पुरुष उनके लिए खाना और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जिम्मेदारी और दायित्व इस मंत्रालय पर ही है। जिस प्रकार एक अर्से से समय-समय पर इस सदन में और इस सदन से बाहर भी रेलवे बोर्ड की आलोचना होती रही है और वह एक सफेद हाथी बताया जाता रहा है उसी प्रकार से भारतीय खाद्य निगम की भी आलोचना होती रही है। मैंने पक्ष और विपक्ष के साथियों को सुना है और मैं समझता हूं सभी ने भारतीय खाद्य निगम की कार-गुजारियों और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की आलोचना की है। मैं आज अपने नेता और भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री भागवत झा आजाद जैसे एक सुयोग्य और सक्षम मंत्री के मजबूत कन्धों पर इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा उन्होंने पिछले हफते राज्य सभा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा था मैं इस मुल्क में चीजों

की, आवश्यक वस्तुओं की, कीमतों को नहीं बढ़ने देंगा और यह बतलाते हुए मुझे गर्व हो रहा है उन की इस सिंह-गर्जना के साथ ही गेहूं के दाम, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में 300 और 325 रुपये क्विंटल थे, 80 से 90 रुपये क्विंटल टूट कर 210 और 215 रुपये क्विंटल हो गये। मुझे पूरी आशा है—यदि उन्होंने इसी मुस्तैदी से, इसी हिम्मत से, इसी हौसले से काम किया तो शीघ्र ही एफ०सी०आई० और जो ऐसे दूसरे ईशूज हैं—वितरण प्रणाली से सम्बन्ध रखने वाले, जिन की इस सदन में आलोचना होती रही है, शायद अब किसी को इस तरह की आलोचना का मौका नहीं मिलेगा।

कुछ बातें ऐसी हैं जिन की तरफ आप के माध्यम से मैं इस माननीय सदन और इस देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में ये जो धंधा करने वाले व्यापारी हैं, गल्ले के आढ़तिये और थोक-विक्रेता हैं वे आज बड़े सुनियोजित ढंग से, कानून की आंखों में धूल झोंक कर, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से, काला-धंधा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश से चालक के ट्रक-के-ट्रक बिहार में तस्करी के रूप में जा रहे हैं . . .

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour): On a point of order. Such an imporant debate is going on in the House, and there is no quorum. Only eighteen Members are present.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may resume his seat because the quorum is being challenged. Let the bell be rung. ....Now there is quorum; the hon. Member may continue his speech.

श्री चन्द्रपाल शैलानी : श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से बिहार में चावल की तस्करी हो रही है। काला धंधा करने वाले लोग, व्यापारी लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर बड़ी शान से इस काम को कर रहे हैं। वैसे तो चावल के लिए सारा देश एक जोन है लेकिन चावल लेवी के रूप में जो देना पड़ता है उसके लिए ये चालाक व्यापारी लोग दिल्ली से ट्रकों के कागजात तैयार कराते हैं और गलत कागजात तैयार कराते हैं जिनका कि कहीं पर सत्यापन या वेरीफिकेशन नहीं होता और उन कागजातों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिलों से चावल की तस्करी करते हैं। इनको पुलिस भी रोकने में असमर्थ है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस बारे में सवाल भी उठा था और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से तस्करी रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाने के बारे में कहा था। इस तरह की तस्करी बड़े जोरों से चल रही है। इसको रोकने के बारे में जल्दी से जल्दी प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।

यही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो इलाका नेपाल से लगा हुआ है, जिसे पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, गोरखपुर, देवरिया आदि इन इलाकों से नेपाल के लिये चावल और गुड़ की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है और उच्चाधिकारी इसे रोकने में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। चावल और गुड़ की तस्करी करने के लिए एक बड़ा गिरोह है जो नेपाल के लिए उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह नेपाल से भारत के लिये कपड़ा, घड़ियां, टार्च, टेपरिकार्डर, ट्रांजिस्टर तथा अन्य वस्तुएं तस्करी कर के भारत में लाने के लिए एक गिरोह सक्रिय है।

श्रीमन चावल की तस्करी में बताया जाता है कि खाद्य निगम के अधिकारियों

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

का आशीर्वाद प्राप्त है । धान मिल-मालिकों की इस गिरोह से सांठगाँठ है । इस तस्करी में पुलिस की भी मिलीभगत रहती है ।

श्रीमन् खाद्य निगम के बारे में बहुत सी शिकायतें यहां की गई हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने उसकी कार्यवाहियों पर प्रकाश डाला । इस सम्बन्ध में मैं उनकी बातों को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम जैसी जो सरकारी एजेन्सियां हैं वे किसानों से गेंहू खरीदती है । इसकी ए०बी०सी० श्रेणियां नहीं होनी चाहिए। गत वर्ष आपने जो 142 रुपये गेंहु का भाव घोषित किया था, उसमें होता यह था कि जब गेंहू एफ०सी०आई० के केन्द्र पर किसान लाता तो उसको एक-एक हफ्ते तक वहां पर रहना पड़ता और इतने दिन तक उसको कोई नहीं पूछंता था। हमारा दुर्भाग्य था कि पिछले साल बरसात की वजह से गेहूं कुछ खराब हो गया था, लेकिन फिर भी किसान से सीधा गेहूं नही खरीदा गया । एफ०सी०आई० के कर्मचारियों की मिली भगत से आड़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदा गया । गेहूं की जो तीन श्रेणियां तय की गई उनमें प्रथम श्रेणी का गेहूं 142 रुपए प्रति क्विंटल, दिवतीय श्रेणी का 140 और तृतीय श्रेणी का 138 रुपये प्रति क्विंटल के भावसे खरीदा जाता था इसके बादये तीनों तरह का गेंहू एक ही गोदाम में रख दिया जाता । इसका लाभ न तो किसान को मिलता है और न कंजूमर्स को मिलता है । फेयर प्राइस शाप से सारा गेहूं एक ही कीमत पर बेचा जाता है । फिर ये तीन श्रेणियां रखने का क्या औचित्य है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

गेहूं का मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया है । फसल आ गई है और किसान नहीं सोच पा रहा है कि उसको सरकार को बेचे या आढ़तियों को बेचे । किसान की इस परेशानी को दूर किया जाना चाहिए । फसल के समय ही किसान अपनी जरुरत की चीजों को खरीदता है। इसलिए मूल्य जल्दी घोषित किया जाना चाहिए ।

ए० पी० सी० में किसानों के बराबर प्रतिनिधित्व है । आज देश में साइकल, फ्रिज, टेलीविजन आदि बनाने वाले अपने सामान की कीमत स्वयं निश्चित करते हैं किन्तु किसान अपने उत्पादों की कीमत स्वयं तय नहीं करता । इसलिए मेरा आग्रह है कि ए० पी० सी० में किसान का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए । इस दिशा आवश्यक और शीघ्र कदम उठाए ज चाहिए ।

एफ०सी०आई० की स्थापना उपभोक्ता और किसान की भलाई के लिए की गई थी । आज उपभोक्ता और किसान का सबसे ज्यादा शोषण एफ सी आई के द्वारा ही हो रहा है। भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें यहां बताई गई है मैं उनको दोहराना यहां नहीं चाहता । पिछले दिनों देखने में आया है कि गल्ले के रिजर्व भण्डार में बहुत कमी आई है । पिछले वर्ष गेहूं की रिकार्ड वसूली हुई थी इसके बाव-जूद भी खाद्य निगम के सुरक्षित भण्डार में कमी आई है । कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों

का कहना है कि सुरक्षित भण्डार में हर समय एक करोड़ 80 लाख टन अनाज रहना चाहिए । इस समय लगभग 60 लाख टन अनाज कम है। खाद्य विभाग के सूत्रों से पता चला है कि सुरक्षित भण्डार की पूर्ति के लिए ही सरकार द्वारा अमरीका से 40 लाख टन गेहूं का आयात किया गया है । इन बातों का सरकार को बड़ी गंभीरता से मनन करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए ।

वितरण प्रणाली के संबंध में भी यहां पर पक्ष और विपक्ष की ओर से बहुत सी बातें कहीं गई । मेरा निवेदन यह है कि आम आदमी को इसका लाभ पहुंचाने के लिए इसके ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । सस्ते दर की दूकानें प्रइवेट लोगों को एलाट की जाती है और इसलिए उपभोक्ता तक वस्तुएं नहीं पहुंच पाती । सब बीच में हो तय हो जाता है । देहातों में जो दूकानें हैं उनके मालिक तो कर्मचारियों से ही पर-संटेज लेकर चले जाते हैं । देहात के लोगों को शक्कर चावल तेल इत्यादि कुछ नहीं मिल पाता है ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें वितरण प्रणाली के ढांचे में आमूल –चूल परिवर्तन करना चाहिये । इसका लाभ पहाड़ पर रहने वाले, आदिवासियों सुदूर जंगल में रहने वाले और विद्यार्थियों को मिलना चाहिए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । हमारे उत्तर प्रदेश में तथा दूसरे सूबों में हाई स्कूल और इन्टर मीडिएट बोर्ड की परिक्षाएं चल रही हैं। विद्यार्थियों को मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से बड़ी भारी परेशानी है । यह विषय इसी मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । देहातों में बिजली भी न के बराबर है क्योंकि वहां बिजली के खम्भे लगे हुए हैं लेकिन बिजली नहीं पहुंचती है। मेरा निवेदन है कि गरीब परिवार के छात्र – छात्राओं की दयनीय हालत पर तरस खाएं और जितनी जल्दी हो सके प्रान्तों की सरकार और जिला प्रशासन को हिदायत दें कि वे मिट्टी का तेल सप्लाई करे । यह अभियान चलाएं कि जब तक विद्यार्थियों की परीक्षाएं समाप्त नहीं होगीं तब मिट्टी के तेल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी ।

एक बात डागा साहब ने मिलावट के बारे में कही थी। मिलावट को मैं कत्ल और मर्डर जैसे भयंकर अपराध से कम नहीं समझता । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के दोषी पाए जाएं उनको वही सजा दी जाए जो दफा 302 के अन्तर्गत कत्ल करने वाले अभियुक्त को दी जाती है। इस देश में जनता के साथ एक नाटक खेला जा रहा है लेकिन मिलावट करने वाले लोगों पर अभी तक अंकुश नहीं लगा है। गेंहूं, चावल वनस्पति और चीनी और ऐसी चीजें हैं जिनको हरेक इन्सान एस्तेमाल करता है और जब इन चीजों में मिलावट होगी और जन-जीवन के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या स्थिति होगी ? अभी हमारे विरोधी दल के लोगों ने कहा कि भूख से काफी लोग मरे हैं । मैं समझता हूं भूख से आज कल कोई भी नहीं मरता.. (व्यवधान) ..... जब मैं देखता हूं कि सड़क पर सफाई करने वाला या जूतों की मरम्मत करने वाला या खोमचे लगाकर बेचने वाला ट्रान्जीस्टर रखकर सुनता है और टेरीकाट के कपड़े पहनता है तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस देश में भूख से मौत होती है । ..... (व्यवधान)

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): I am not against that. Nineteen persons

[Shri K. Mayathevar]

died of starvation in Tamil Nadu last week.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): It was raised in the House itself.

SHRI K. MAYATHEVAR: It was a case of gross mismanagement by Tamil Nadu Government.

MR. CHAIRMAN: We are not discussing Tamil Nadu Budget here now.

श्री चन्द्रपाल शैलानी : हमारे कुछ विरोधी पक्ष के लोग कुछ अखबार वाले हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रोपोगंडा करते हैं कि इस देश में भूख से मौत होती है ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सरकार को विशेष कानून बनाना चाहिये । केवल कानून बनाकर ही काम नहीं चलने वाला है । क्यों ? इस देश में छुआछूत समाप्त करने के लिए कानून बना हुआ है और भी बहुत सी बुराइयों को समाप्त करने के लिए कानून बने हुये हैं, दहेज को भी समाप्त करने के लिए कानून है, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं नहीं किया जाएगा तब तक उस कानून की कोई कीमत नहीं है ।

अन्त में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो भी मिलावट के लिए दोषी पाया जाये उसको किसी भी कीमत पर न छोड़ा जाए क्योंकि वह हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है और यह एक अमानवीय कार्य है, गलत काम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाय और किसी भी कीमत पर चाहे राजनीतिक या आर्थिक दबाव पड़े, उसके सामने सरकार को नहीं झुकना चाहिये, और जो लोग मिलावट के लिए दोषी पाये जायें उनको सख्त सजा देकर सबक सिखाया जाए ताकि आइन्दा जन-जीवन के साथ खिलवाड़ न कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी): सभापति जी, मैं मंत्री जी को डायनेमिक आदमी मानता हूं और 1967 से मैं देख रहा हूं जब से मैं लोक सभा में हू हमेशा डाउन ट्रोडन का जब भी सवाल उठता है उसको उन्होंने हमेशा मजबूती से सम्हाला है । लेकिन आज जब फूड पर डिबेट हो रही है उस समय स्थिति इतनी गम्भीर है, प्रधान मंत्री ने स्वंय कहा है कि देश की आबादी का तीन चौथाई हिस्सा अकाल और सूखे से पीड़ित है । केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार की तो यह स्थिति है कि 32 जिलों में से 26 जिले अकाल से पीड़ित हैं और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की स्थिति भयावह है । जो इलाका अन्न पैदा करने वाला था तमिलनाडु उसकी भी हालत बुरी है । यह गम्भीर स्थिति है इसको सम्हालने के लिए मंत्री जी के दिल में दर्द जरूर है । लेकिन आप फूड मिनिस्टर बना दिये गये, लेकिन जब फूड ही नहीं होगा तो सप्लाई कहां से करेंगे ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में स्थिति क्या है ? ग्रीन रिवोल्यूशन का युग समाप्त हो गया, हरित क्रान्ति का युग होता तो आपके प्लान के अनुसार 3 साल में 6 लाख हैक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की है, और 50 लाख हैक्टर पहले हुई थी । तो 56 लाख हैक्टर में सिंचाई की व्यवस्था है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स अच्छे बीज, कीटनाशक दवाओं का इस्ते-

माल भी बढ़ा है, फिर भी कृषि की पैदावार घट रही है । ऐसा क्यों है, यह सोचने वाली बात है । आपका ही ऐलान है कि हमारी हुकूमत होगी तो हम जमीन भूमिहीनों में बांटेंगे । क्या हो गया उसका ? आज हालत यह है कि जमींदारों की भारी जमीन जो आपके राज्य हैं, बांटी नहीं जा रही है । जमींदारों ने बेनामी पट्टे करके अपनी जमीनों को कानून से बचा लिया है । इसलिए बेसिक सवाल यह है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में पैदावार बढ़े तो भूमि का वितरण होना चाहिये । और जिन किसानों को भूमि देते हैं उनको सारी सुविधायें दीजिए ताकि पैदावार बढ़ा सकें । लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है ।

हिन्दुस्तान में कुछ इलाके, जहां आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, यह राज्य लगातार डेफिसिट स्टेट्स रही हैं । आप आंकड़े देख लीजिए । जो राज्य डेफिसिट में रहा है, आज तक उसके लिए आपने कौन सी ऐसी योजना बनाई है ? बिहार को आप जानते हैं, उपजाऊ है, पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां अकाल पड़ रहा है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है । जो अभावग्रस्त इलाके हैं, जहां आबादी के बहुत कम लोग रहते हैं, उनके लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया है । इसमें आपको बेइन्तहा फेल्योर है । इसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं आपकी प्रोक्योरमेंट पालिसी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं पश्चिमी जर्मनी और सोवियत यूनियन घूमने गया था । वहां 30 वर्षों से लगातार एसेन्शियल कमोडिटीज के दाम एकदम स्थिर हैं । चाहे गांव में जाइये चाहे शहर में जाइए लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं है । यहां लगातार मांग हो रही है कि आप प्रोक्योरमेंट पालिसी को बदलिए, अन्न उपजाऊ नीति को बदलिए । प्राइवेट बिचौलियों को जो आप रखे हुये हैं, उनको खत्म कीजिए । आप यह नीति अपनाइए कि फूड-ग्रेन का होलसेल ट्रेड सरकार अपने हाथ में ले । आपने कौटन का और तम्बाकू का एक्सपैरीमेंट किया है, उसके नतीजे अच्छे निकले हैं, फिर आप घबड़ाते क्यों हैं कि फूड-ग्रेन का ट्रेड अपने हाथ में नहीं लेते ? आपको एलान करना चाहिये कि क्या दिक्कत इसमें आपको है ?

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को देखिए, बिहार में गन्ने की 32 मिलें हैं, लेकिन वहां हालत यह है कि आपके राज्य में और जनता पार्टी के राज्य में भी किसानों का गन्ना खड़ा रहा गया, उनको जलाना पड़ा । आज भी वही स्थिति हो रही है । गन्ने की कीमत जो सरकार ने एलान की है, वह गन्ना उत्पादकों को नहीं मिल रही है इससे किसानों को नुकसान हो रहा है । आपकी सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है । लगातार लोक सभा में कहा जा रहा है कि इसकी ओर ध्यान दीजिए ताकि गन्ना किसानों को प्रेरणा मिल सके । यह बात बहुत जरूरी है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये लेकिन यह दिया नहीं जाता है । सादे और बीज का दाम बढ़ रहा है और दूसरी चीजों का भी दाम बढ़ रहा है । जनता पार्टी में और आप में कोई फर्क नहीं है आपकी भी किसान विरोधी नीति है और जनता पार्टी की भी यही नीति रही है । आप उनको लूट रहे हैं । किसान जो पैदा करता है, उसका कम दाम आप उसको देते हैं और जो चीजें किसान खरीदने जाता है, उसका दाम बढ़ता जा रहा है ।

[श्री कमला मिश्र मधूकर]

आपने नई आर्थिक योजना की बात कही है । आपने कहा है कि साम्राज्यवादी देश लूट करते हैं । आप अपने देश में पूंजीपतियों के इशारे पर किसानों को लूट रहे हैं, इसकी ओर आपको कदम उठाने चाहियें ।

आप गेहूं के दाम तय कीजिए । किसी माननीय सदस्य ने इसकी मांग की है और सही कहा है कि गेहूं की कीमत 175 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिये । इस बात को आप सोच लीजिए कि जो लागत लग रही है उसका कितना परसेंट आप किसानों को लाभ देने जा रहे हैं ?

साथ ही साथ जो इलाके डैफिसिट कहलाते हैं, उसके लिए विशेष प्रोग्राम बनाइए । आपने अन्न बाहर से मंगाया, कई सदस्यों ने कहा कि इसका दाम देना पड़ता है । 204 रुपए क्विंटल, क्या इसको रोका नहीं जा सकता है ? क्या किसानों का इन्सेंटिव नहीं दिया जा सकता है ? मैं बताना चाहता हूं कि आज सोवियत यूनियन की आबादी 26 करोड़ है और वह 20 करोड़ टन पैदा करता है । पर कैपिटा अन्न 800 के० जी० है और यहां पर 200 के० जी है । एफ० सी० आई० को रहना चाहिये--मैं इस बात को मानता हूं । आलोचना का मतलब यह नहीं है कि एफ० सी० आई० को खत्म कर दिया जाये । आलोचना का मतलब यह होना चाहिये कि एफ० सी० आई० में फैले हुये दुर्गुणों को रोका जाए । पांडे जी ने बहुत से प्वाइन्ट कहे हैं, एक प्वाइन्ट मैं भी कहना चाहता हूं । एफ० सी० आई० के गोदामों में मई में अन्न रखा जाता है और सितम्बर, अक्तूबर में निकाला जाता है । मौसम के चलते अन्न का वजन वहां बढ़ जाता है । आपने वहां पर मान लीजिए रखा 50 टन और निकाला भी 50 टन लेकिन वजन बढ़ जाने से जो अनाज बचता है वह कहां जाता है ? उसको अधिकारी हजम कर जाते हैं ।

मैं आपके सामने एफ० सी० आई० की जो हालत है उसको ब्यान करना चाहता हूं । एक कर्मचारी जिसका नाम है ठाकुर खुशी राम, उसके केस को आप भी जानते हैं 6 एम पीज ने ज्वाइन्टली दरख्वास्त दी और डेलिगेशन मिला लेकिन आज तक ठाकुर खुशी राम का मामला हल नहीं किया गया है । आपकी इजाजत होगी तो सभा पटल पर मैं इसको रख दूंगा ।

जहां तक मांग और सप्लाई का संबंध है पांडे जी ने बताया है कि कितने करोड़ के अनाज का स्टोरेज ट्रांसपोर्ट और पिलफ्रेज में नुकसान हो जाता है । केवल 1980-81 में 74 करोड़ का घाटा हुआ--स्टोरेज और ट्रांशिपमेंट में । अकेले स्टोरेज में ही 44 करोड़ का घाटा हुआ । यह घाटा सारे देश का हो रहा है । इसलिए एफ० सी० आई० को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में आप जो भी कदम उठायेंगे उनका हम समर्थन करेंगे ।

आप जो भेदभाव की नीति बरतते हैं उसके सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है । पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में जहां पर गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, उनसे आप आवागमन के लिए चार्ज करते हैं लेकिन यहां पर दिल्ली में नहीं चार्ज करते हैं--इसका क्या कारण है ? दूसरी बात यह है कि आपने यहां लोक सभा में तो कह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार को इतना अन्न दे दिया लेकिन ऐसी मैनोवरिंग की जाती है जिसके जरिए वह कोटा टाइम पर नहीं पहुंचता है । जो इस प्रकार का भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाना चाहिये ।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, आप स्वयं जानते हैं कि बिहार में अकाल की स्थिति है और वहां की सरकार मांग कर रही है कि हमें इतना अनाज दिया जाये, वहां के फूड मिनिस्टर ने मेमोरैंडम भी भेजा हुआ है लेकिन आप अन्न देने से कतरा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम क्या करें ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : अभी एक्स्ट्रा दे दिया है ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अभी उड़ीसा में साइक्लोन आया था, हम वहां पर गए थे, 8 जिलों का हमने दौरा किया । फिर वहां पर अकाल पड़ गया और सूखाड़ से भी प्रभावित है लेकिन आप यहां पर बना बनाया उत्तर दे देंगे । दूसरों के साथ-साथ आपकी पार्टी के लोगों ने भी यहां पर कहा है कि बफर स्टाक को बढ़ाना चाहिये । इसके लिए आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं ? मार्केट में अब ग्रेन आने वाला है लेकिन जब तक आप ठीक से पर्चेजिंग नहीं करेंगे तब तक बफर स्टाक पूरा नहीं होगा ।

आप कहते हैं—राज्य सरकारें वसूली नहीं करती हैं । आप के पास कोई ऐसा कानून या नियम है या नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं या नहीं, कि राज्य सरकारें भी वसूली में आप के साथ सहयोग करें, जिस से कि आप अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थोप कर बच न जायें ?

अन्तिम बात—आज आप ने जिस विभाग की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हैं, उस की हालत क्या है ? हमारे यहां एक कहावत है—एक साधू बाबा थे । उन्होंने क्या किया कि अपने तमाम चेलों को न्योता दिया । किस लिये—खीर खाने के लिये, । जब चेले खाने के लिये बैठे तो खीर के बदले खिचड़ी परोसी गई । लोगों ने पूछा—हम तो खीर खाने आये थे । बाबा जी ने कहा—होख पंचे भकोसू । अगर एलर्ट नहीं रहेंगे तो आप की व्यवस्था भी ऐसी ही होगी । यदि आप का प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा तो जनता के सामने आज जो सवाल हैं वे और ज्यादा भयावह स्थिति में पहुंच जायेंगे और आप परिस्थिति का मुकाबला करने में मुकम्मिल रूप से फेल कर जायेंगे । तब आप की जो पहले की कथनी और आज की करनी है हम लोगों को बाध्य हो कर उस की आलोचना करनी पड़ेगी । ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस लिये आप एफ० सी० आई० को मजबूत कीयजये तथा अन्य कठिनाइयों का समाधान कीजिये ।

इन शब्दों के साथ मैं आप के विभाग की मांगों का विरोध करता हूं ।

***श्री शान्तु भाई पटेल :** (साबरकंठा) : माननीय सभापति जी, सदन के सामने खाद्य व नागरिक पूर्ति विभाग की जो मांगे रखी गई हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

इस रपट में बताया गया है कि देश में अन्न, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि किस प्रकार से वितरित किया जाता है । इस को पढ़ने से लगता है कि....

MR. CHAIRAN: Have you given previous intimation to the Interpreters, because I find that no translation is....

SHRI SHANTUBHAI PATEL: Yes, I have given....

*The original speech was delivered in Gujarati.

सभापति महोदय : आपने शायद पहले सूचना नहीं दी है । आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी ताकि जो आपकी भाषा जानने वाले हैं, वे इन्टरप्रेट कर सकें । आप हिन्दी में या अंग्रेजी में बोल सकते हैं ।

श्री शान्तु भाई पटेल : बैठा है । हम हिन्दी में कम बोल सकते हैं । नागरिक पूर्ति विभाग की जो मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं । नागरिक पूर्ति विभाग के द्वारा सरकार अन्न, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, सीमेंट जैसी आवश्यक चीजें जनता तक पहुंचाने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है । इस प्रकार सरकार का यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है । हमारा देश बहुत बड़ा है, देश की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है । ऐसी स्थिति में जनता को आवश्यक चीजें पहुंचाना बहुत कठिन कार्य है । फिर भी नागरिक पूर्ति विभाग इस काम को अच्छी से अच्छी तरह करने की कोशिश कर रहा है । इस के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

आवश्यक चीजों की जो वर्तमान वितरण व्यवस्था है, उस में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि उस में कुछ कमियां ऐसी हैं जिन के कारण उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है । आज वितरण का काम दुकानदारों के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है । मेरा सुझाव है कि यह व्यवस्था केवल सहकारी समितियों के द्वारा ही की जाये क्योंकि इस से हम सब सामान उचित कीमत पर और ठीक समय पर गांव की जनता तक पहुंचा सकेंगे ।

एफ० सी० आई० के द्वारा किसानों से अनाज खरीदा जाता है । उस के द्वारा अनाज की खरीद के लिए जिस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है, उस पर इस सदन में काफी शिकायतें की गयी हैं । एफ० सी० आई० अनाज की खरीद करने के बाद उस को अपने गोदामों में रखता है । गोदामों में रखे गये अनाज पर वह कोई ध्यान नहीं देता है, जिस से बहुत सा अनाज खराब हो जाता है । इस प्रकार सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है तथा जनता को सड़ा हुआ अनाज खाना पड़ता है । इस व्यवस्था के लिये बड़े बड़े अफसर तथा अन्य कर्मचारी रखे गये हैं तथा तरह तरह के साधनों का उपयोग किया जाता है, लाखों रुपये का खर्च किया जाता है, फिर भी अगर इस प्रकार का नुकसान हो होता रहे तो वह अनुचित ही होगा । सरकार को चाहिये कि वह संग्रह किये गये अनाज को हिफाजत से रखे तथा उस का उचित समय पर वितरण करे । जिस से जनता को अच्छा अनाज ठीक समय पर मिले ।

आज लाखों टन अनाज विदेश से आयात किया जाता है । उस के लिए विदेश को ज्यादा भाव देना पड़ता है जिस से एक तो देश की विदेशी मुद्रा का अनावश्यक खर्च होता है, तथा दूसरी ओर देश के किसानों को नुकसान होता है क्योंकि जो भाव विदेशों को देते हैं, उस भाव से हमारे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा । आज हमारे देश के किसानों को बहुत कम भाव दिये जाते हैं । अन्न को पैदा करने में किसान को मंहगी खाद, कीट नाशक दवाएं, सिंचाई तथा मजदूरी के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है । उनके इन खर्चों को देखकर, किसानों को घाटा न हो, इस प्रकार के भाव देने चाहियें । ए पी०सी० को चाहिये कि कृषि उत्पादों का समर्थन

मूल्य निर्धारित करने से पहले इस को ठीक से देखें तथा फसल बाजार में पहुंचने से पहले ही समर्थन मूल्यों को घोषणा करें ।

खाद्य तेल के बारे में भी मैं एक बात कहूंगा । हम 800 से 900 लाख टन खाद्य तेल का आयात करते हैं । उसके लिये 700-800 करोड़ रुपये का खर्च करते हैं । इसके बदले हमारे किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये । ताकि वे अपने खेतों मे मूंगफली , कपास आदि तेल देने वाली फसलों को लगायें । किसानों के लिये पूरी जानकारी, अच्छे बीज, सिंचाई की आवश्यका सुविधा तथा पर्याप्त ऋण और आर्थिक सहायता की व्यवस्था होने पार ऐसी फसलों को लगाने के लिये तैयार होंगे । उस के हम विदेशी मुद्रा को बचा सकेंगे तथा हमारे किसानों को लाभ पहुंचा सकेंगे ।

सीमेंट के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। ता० 2-2-82 से सरकार ने सीमेंट वितरणत्र के लिये दोहरी मूल्य नीति को अपनाया था जिस में व्यवस्था की गई कि सीमेंट के उत्पादन का 63 प्रतिशत भाग लेवी के द्वारा प्राप्त कर के नियंत्रित मूल्य पर बेचा जायेगा । तथा बाकी 37 प्रतिशत भाग को खुले बाजार में बेचा जायेगा । नियंत्रित मूल्य के सीमेंट का भाव रु० 40.25 प्रति थैली निर्धारित किया गया तथा खुले बाजार में रु० 62.50 प्रति थैली बेचा जायेगा ।

लेकिन इस नीति से लाभ होने की बजाय जनता की परेशानी बढ़ी है क्योंकि नियंत्रित मूल्य का सीमेंट लोगों तक पहुंचने के लिए उचित व्यवस्था हम नहीं कर सके हैं । नियंत्रित मूल्य वाली सीमेंट का वितरण समय से नहीं होता है । सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनियां ट्रांसपोट आदि के बहाने बना कर विलंब करती हैं । बाद में उस सीमेंट को प्रति थैली 70-75 रु० लेकर बेचती हैं । इस प्रकार सामान्य जनता के लिए जो सीमेंट है, वह उसको नहीं मिलती । कंपनियां डीलर्स से पैसे एडवांस में लेकर उसका बिना ब्याज उपयोग करती हैं ।

मैं मांग करता हूं कि सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति को तुरंत बंद किया जाये । मिट्टी के तेल के बारे में भी ऐसी नीति को लागू किया था लेकिन जनता की परेशानी को देखते हुए उसे वापस ले लिया गया। इस पर मंत्री जी को बधाइयां भी बहुत मिलीं । ठीक उसी प्रकार सीमेंट की नीति को भी बदलना होगा क्योंकि वर्तमान नीति से जरूरतमंद उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है ।

नियंत्रित मूल्य पर देश की गरीब जनता को कपड़ा देने की एक नीति सरकार की है । एन० टी० सी० की मिलों द्वारा इस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है । लेकिन हमारी वितरण व्यवस्था इस दृष्टि से भी नाकामयाब रही है । आज हम इस प्रकार का उचित दर का कपड़ा गांवों के गरीब किसानों, मजदूरों को नहीं पहुंचा सके हैं । अगर हम सहकारी समितियों के द्वारा गांवों में भंडारों की व्यवस्था करके कपड़े का वितरण करने की जिम्मेदारी उनको सौंपेंगे तो अवश्य सफलता हासिल होगी । खाद्यतेल के लिए हम विदेशों से पाम आइल मंगाते हैं जिस के लिए हमें करोड़ों रुपये विदेश को देने पड़ते हैं । मुझ को एक सूचना मिली है कि विदेश में कई ऐसी कंपनियां हैं, जो हमारे देश की बीमार मिलों को सहायता कर सकती हैं । वे इन मिलों को सोयाबीन सीड, काटन सीड आदि भेजेंगी । जिस को पीस कर उस की खली को ले जायेंगी । लाने ले जाने का

[श्री शान्तु भाई पटेल]

खर्चा वे करेंगी तथा मजदूरी के रूप में निकला हुआ तेल यहां छोड़ेंगी । अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो हमें फायदा ही फायदा है क्योंकि इस से हमारी बीमार मिलों को मदद मिलेगी । विदेशी मुद्रा की बचत होगी, खाद्य तेल का संकट दूर होगा तथा मजदूरों को मजदूरी मिल सकेगी ।

16.00 hrs.

गुजरात में हाल ही में समुद्री तूफान से बहुत नुकसान हुआ है । उस के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सीमेंट व अन्न की मदद मांगी है । मैं आशा करूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहानुभूति से विचार करेगी तथा आवश्यक सहायता यथाशीघ्र पहुंचाएंगी ।

मैं पुनः इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदय, 35 वर्ष की आजादी के बाद, पांच पंचवर्षीय योजनाओं में खरबों रुपया लगाने के बाद और विदेशों से खरबों रुपया कर्ज लेने के बाद आज जो भारतवर्ष की खाद्यान्न की स्थिति है वह इस सदन में और सदन के बाहर चर्चा का विषय है । पक्ष और विपक्ष के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस स्थिति पर प्रकाश डाला है ।

मध्य प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर है । आज मध्य प्रदेश के महाकौशल विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां से गरीब, आदिवासी और हरिजन भाग रहे हैं और ये गांव उजड़ रहे हैं । पिछले 15 दिन का एक किस्सा है । जबलपुर की सिहोरा नामक तहसील में भूखे मजदूरों ने मजबूर होकर राशन की दुकाने लूट लीं । इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में हालत कितनी खराब है । अभी सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि विरोधी दल वाले और अखबार वाले भूख से मौत होने का प्रोपेगंडा करते हैं, इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं । मन्डला जिले में एक निवास तहसील है उसके पास एक गांव में शांति बाई नाम की आदिवासी महिला भूख से तड़प-तड़प कर मर गई । जिला अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि बदहजमी से मरी है । मैं उस गांव में गया था और वहां जाकर देखा कि जंगल के निवासियों ने लोमड़ी, भेड़िया और सांप तक खा डाले, उसके बाद भी भूख पूरी नहीं हुई । इस प्रकार बहुत बड़ी तादाद में उस जिले में लोग भूख से मरे हैं । फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया में भ्रष्टाचार की बात चल रही थी । अभी तक हम सुनते थे कि दाल में नमक के बराबर भष्टाचार चलता है । परन्तु मुझे समझ में आया कि भ्रष्टाचार में अब नमक में दाल आ गई है । जब मैं शांति बाई की सास को मिला और उनसे पूछा कि आपकी बहू को मरे हुए 9 दिन हो गए हैं, आपकी मध्य प्रदेश शासन ने कोई सहायता की या नहीं ? उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ दो किलो चावल की सहायता मिली है । सुनकर बड़ा अजीब लगा कि 25 वर्ष की बहू भूख से तड़प-तड़प कर मर जाए और सिर्फ दो किलो चावल देकर ही सहायता की जाए ? जब जड़ में पहुंचा तो समझ में आया कि इस बुढ़िया का दो बोरे चावल पर अंगूठा लग गया था । सौ किलो सरकारी गोदाम से निकला और एक किलो उसके घर पर पहुंचा, जो भूख से तड़प कर मर गई । हमारे एक सदस्य महोदय ने कहा

कि दिल्ली में 25 दुकानें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति चलाता है । मैं चाहुंगा कि खाद्य मंत्री महोदय उसकी जांच करें । मध्य प्रदेश में एक सविनी जिला है, वहां की एक मंत्राणी हैं, नाम नहीं लेनाचाहूंगा और इस सदन में एक श्रेष्ठ मंत्री है जो वहां के निवासी हैं । इनके विश्वासपात्र व्यक्ति तीन सो से अधिक दुकानें आज वहां पर चला रहे हैं इसमें किसका कितना हिस्सा है, यह समझने की ओर जांच की बात है ।

THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI): I think the hon. Member is referring to me. I say the charge is baseless.

श्री बाबू राव पराजपे । मैंने सिवनी जिले में के एक मंत्री जी यहां मंत्रिमडल में बैठे हुए हैं, उनकी बात की थी । अगर मामला साफ न हो तो और साफ कर सकता हूं । कुल-मिलाकर में प्रसन्न हूं क्योंकि विरोधी पक्ष का हूं । मगर भूख से तडप तडप कर इनसान मर जायेंगे तो क्या शांति बनी रहेगी । आज जबलपुर में राशन की दुकानें लुट सकती हैं तो क्यों नहीं भूखा इनसान सडक पर आ सकता और यदि वह आता है तो यह देश के लिये बहुत खतरनाक बात होगी । मैं चाहूंगा कि जहां तक मध्य प्रदेश के खाद्य का मामला है पुनः विचार किया जाये और उनका कोटा बढाया जाये ताकि भुखमरी कुछ मात्रा में समाप्त हो सके ।

एक अंदाज आप कीजिये । आप मध्य प्रदेश में एक किलो चावल और एक किलो गेहू प्रति यूनिट प्रति माह दिया जा रहा है । कुछ जिलों कर 2 किलो राशन एक यूनिट को एक महीने में अनेकों जिलों में सरकार की ओर से दिया जा रहा है । अब प्रश्न यह आता है कि कम से कम 450 ग्राम आज एक आदमी को दिन भर के खाने के लिये होना चाहिए । उसके परिणाम में मध्य प्रदेश में आज क्या दिया जा रहा है इसके आंकड़े आपके सामने हैं आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि वहां खाद्यान्न की कितनी भयंकर स्थिति है ।

रहा सवाल किसान को मिलने वाले मूल्य का । वह गोरी चमडी का किसान चाहे आस्ट्रेलिया का हो या अमरीका का, हमारी भारत सरकार उससे ज्यादा खुश है ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उसको गेहू का भाव 204 रु० दिया जाता है और दूसरे वर्ष में 230 रु० दिया जा रहा है , जब कि देश के किसान को 142 रु० दिया जा रहा है । इस वर्ष खाद्य की महंगाई बिजली और पानी की महंगाई है , इन सब को ध्यान में रखकर मुरी मांग है कि हमारे किसान को कम से कम 200 रु० प्रति क्विंटल गेहू का भाव तय होना चाहिए ।

कापियों की बड़ी चर्चा होती है । समाचर पत्रों, रेडियों, टी० वी० पर कहा जाता है कि इस सरकार को गरीब की बडी चिन्ता है । पिछले 6 महीने से काजग के कोटे के बारे में मैंने मंत्री जी को पत्र लिखे कि मध्य प्रदेश को पूरे एक वर्ष में कागज का कोटा रिलीज नहीं हुआ है कापियां बनाने के लिये । आज तक कुछ नहीं हुआ । आज भी वही हालत है जो एक साल पहले थी । आप इसकी जांच कर लें ताकि, आने वाले सत्र में गरीबो को कापियां मिल सकें । मध्य प्रदेश में गरीबो इतनी अधिक है कि 320 विधान सभा सीटो में 100 से अधिक सीटें हरिजन और आदिवासियों की हैं । इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वहां कितनी गरीबी है । इस लिये कापियों के सिलसिले में मध्य प्रदेश का जो भी काजग का कोटा है केन्द्र सरकार उनको तुरन्त रिलीज करें ।

[श्री बाबु राव पराजपे]

एक छोटी सी बात मैं तमिलनाडू के बारे में कहना चाहता हूं । तमिलनाडू में तीन प्रकार की चावल की मिलें चल रही हैं —लार्ज, मीडियम और स्माल जिसको सिंगल हलर राइस मिल कहते हैं। तमिलनाडू सरकार ने सबसे छोटी मिलों को, जिसमें 20,000 रु० की लागत लगती है, कहा है कि आपको अपनी मिल को मोर्डनाइज़ करना पडेगा अन्यथा आपका लाइसेंस कैंसिल हो जायेगा । बात कुटीर उद्योग की करते हैं, परन्तु तमिलनाडू सरकार क्या कर रही है ? मैं चाहूंगा तमिल नाडू सरकार को इस बात के लिये कम्पैल किया जाये कि इस प्रकार की मिलों को जो 6-9-83 तक का समय दिया है कि अगर तब तक मोर्डनाइज़ नहीं करगें तो उनका लाइसेंस खत्म हो जायेगा , ऐसे आदेश को वह वापिस लें । जो छोटे आदमी 25,000 रु से अपना धंधा कर रहा है उसको काम करने का मोका मिलना चाहिए । इस बारे में मंत्री जी अवश्य ध्याद दें ।

एक बार फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिये गेहूं, चावल और कागज का कोटा आप अधिक दें ।

इन शब्दो के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): Chairman, Sir, I rise to support the Demands of the Ministry of Food and Civil Supplies and to oppose all the cut Motions moved in the House on these Demands.

I congratulate the Union Government for the record food procurement for the year 1981-82. My friends on the other side are urging the Government to supply rice to States like Kerala, West Bengal etc. But they should realise that FCI or the Central Pool or the Ministry of Food and Civil Supplies has no machine to produce any quantity of rice at any time. Unless the FCI procures rice from the States, the Central Pool cannot supply foodgrains to the States to meet their requirements. I therefore urge upon the States that they should cooperate fully with the FCI in its programme of rice procurement from various States.

I wholeheartedly congratulate our Hon. Prime Minister Shrimati Indira Gandhi and her Government on the food policy which has been well thought-out and which has balanced the interests of the producers and the consumers. In spite of severe drought in almost all parts of the country, the procurement of foodgrains during 1981-82 was 15.2 million tonnes which exceeds the earlier recorded procurment of 14.46 million tonnes during 1978-79. I would like to draw the attention of our Hon.Minister to the fact that there is no coordination among the Ministries regarding the supply of foodgrains to various States. The Ministry of Agriculture is claiming that there is an increase in food production. The Ministry of Commerce is going on allowing the export of rice to foreign countries. But we have to remember that our Hon. Minister once said on the floor of the House that in case there is inadequate supply of rice, the rice consumers would have to switch over to wheat. So, the consumers will have to suffer unless there is coordination between these three Ministries.

I would like to mention that edible oils, rapeseed and Palmolive oil are imported by the State Trading Corporation and are sold at the rate of Rs. 6 per kg. But these oils are supplied to the multi-nationals like the Delhi Cloth Mills and Lever Brothers etc., who in turn produce vegetable ghee and re-sell it to the consumer at the rate of Rs. 14 to Rs. 15.00 per kg and the result is that the multinationals and the middlemen get the profit leaving the consumers to suffer. I would therefore urge upon the Union Government that these vegetable ghee producing industries should be nationalised. Due to

unprecedented natural calamities like cyclone floods and drought in 1982, the rice production in the State of Orissa has been decreasing. The open market availability of rice is also decreasing day by day and there is heavy pressure on public distribution system due to dependence on it of a much larger number of consumers. Apart from the target fixed for the procurement of two lakh tonnes of rice, the State is trying to procure rice from the open market. But unfortunately, availability of rice in the open market is scarce and, therefore, the State Government is trying to procure open market rice from outside the State but is it not available in other States also like Andhra Pradesh, because they are also in need of rice to meet their own demand. The State Government has been repeatedly requesting the Union Government to give more foodgrains form the Central Pool. For the kind information of the hon. Minister, I should mention that the request from the State Government is not heeded to by the Union Government. The scarcity conditions will become more acute during the coming months.

The requirements from January, 1983 to December 1983 from the public distribution system have been assessed at 6,60,000 metric tonnes of foodgrains—the requirement of the wheat is 2,62,000 metric tonnes. It is really most unfortunate that as against the requirement of 50,000 metric tonnes of rice and wheat, for the month of February, the Central Government has allotted only 18,000 metric tonnes of rice and 22,000 metric tonnes of wheat. Similarly, for the month on March, 1983, as against the requirement of 50,000 metric tonnes of rice and wheat, only 10,000 metric tonnes of rice and 12,000 metric tonnes of wheat have been supplied till today. I would request the hon. Minister to allot another 16,000 metric tonnes of rice and 12,000 metric tonnes of wheat for the current month since the assessment has been done including the foodgrains required to meet the requirements of gratuitous relief cards, food-for-work programme, etc.

I am grateful to the Government of India for having abolished the dual pricing system in respect of kerosene. The consumer will not mind paying ten paise more per litre provided kerosene is made available in adequate quantities. The hon. Minister may kindly look into this aspect also.

Regarding the requirement of cement, the hon. Minister is well aware of the fact that, in Orissa, due to unprecedented cyclone and floods in 1982, lots of houses and buildings, both private and Govt. in Orissa have been severely damaged and destroyed and some have been washed away. Special quota of levy cement is required to be provided to the State of Orissa for restroation and the construction of the buildings, bridges and culverts which have been severely damaged by the last cyclone and floods of 1982.

Before concluding, I would like to draw the attention of our hon. Minister that the foodgrains are damaged in FCI godowns due to inadequacy of godown facilities and also warehousing facilities by which thousands of tonnes of goodgrains are being destroyed. The hon. Minister may kindly look into this aspect and as far as my information goes, in reply to one of my questions the hon. Minister said that in the last 3 years 40,000 tonnes of foodgrains including vegetables etc. were damaged or destroyed due to lack of godown facilities. The State Governments and the Government of India should take adequate steps to tackle this problem in the right earnest so that necessary godown facilities may be available to the FCI as well as to the farmers in rural areas who keep their produce in those godowns.

With these words, I conclude.

*DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): Hon. Mr. Chairman, Sir, on the Demands for Grants of the Ministry of Food and Civil Supplies, I would like to place my views on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam. I am

*The original speech was delivered in Tamil.

[Dr. V. Kulandaivelu]

thankful to you for giving me a chance to participate in the debate.

At the very outset, I would like to record my grateful thanks to the hon. Prime Minister and I would like to convey my sincere compliments to her for having visited Tamil Nadu, in the midst of her multifarious engagements, to have a personal idea about the seriousness of drought in Tamil Nadu. On 28th March she was in Tamil Nadu. She assessed for herself the drought situation in certain parts of Tamil Nadu. She did not end her efforts there. Her great sense of humanism and her commitment to the cause of common people made her announce the sanction of Rs. 10.0 crores for drought relief measures and Rs. 10 lakhs from her Drought Relief Fund for the afflicted families. She has also ordered the supply of 10,000 tonnes of foodgrains to Tamil Nadu. Sir, on behalf of the people of Tamil Nadu I express my deep debt of gratitude to our hon. Prime Minister who has proved her concern for the common people by both words and deeds.

While participating in the debate on the Motion of Thanks to the President's Address, I had given a detailed narration of the woes of the people of Tamil Nadu consequent upon the failure of two monsoons last year, and due to inept handling of power generation in the State by the AIADMK Government of Tamil Nadu. I specifically drew the attention of the Centre to the inefficient administration of the State Government. I wanted that foodgrains should be rushed to the State to save the people from starvation and also demanded sanction of *ad hoc* amount of Rs. 200 crores for drought relief works. Our Prime Minister's visit to Tamil Nadu has confirmed what I had stated the other day in this House. Similarly, her statement about bad management of foodgrains by the State Government has also substantiated my contention about the ineffective functioning of the State Government. I wonder whether 11000 tonnes of foodgrains would meet the needs of the State in tackling the drought situation and whether the sum of Rs. 10 crores would be enough to take up all drought relief works in the State.

In my district of South Arcot there were 19 starvation deaths of both men and women. These are announced figures. But there are so many starvation deaths which are not known to the Government. For instance, there is an entity enumerated as starvation-diarrhoea leading to death. I am a Doctor in Medicine. That is why I am pointing this out. The people may think that they are dying of diarrhoea. Actually it is not; it is due to poverty and it is due to starvation. Thousands of children die due to starvation resulting in acute diarrhoea. These deaths are generally not known to the State Government.

My leader, Dr Kalaignar Karunanidhi has repeatedly stressed this fact of administrative mal-functioning of the State Government, substantiated by facts and figures, on the floor of Tamil Nadu legislative assembly. As pointed out by our hon. Prime Minister the present critical situation in Tamil Naidu is primarily due to the AIADMK Government of Tamil Nadu that does not work. Due to pressure of circumstances some people may shift their loyalties to the ruling party in the State. One such case is that of Babu Govindaraju, the M.L.A. from South Arcot District. Though he belonged to the ruling party he did not hesitate to highlight the failure of AIADMK Government.

16.31 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to conclude. You are the second speaker from your Party. Don't ask for more time. There are some more speakers whom I have to allow. Your party had already got one opportunity. Please conclude.

DR. V. KULANDAIVELU: Sir, I am narrating the exact problem there in Tamil Nadu. He has proved with photostat copies of concerned documents that the foodgrains meant for fair price shops in

Cuddalore were sold in blackmarket in Madras. He has pointed out that a bag of rice fetched a margin of Rs. 50 in the blackmarket. We have to commend his courage. The other ruling party Members in the Assembly complimented him for his boldness.

MR. DEPUTY SPEAKER: What can this Minister do on that? It is a State subject.

DR. V. KULANDAIVELU: It has to be welcomed that 50,000 fairprice shops have been opened, if the reports are to be relied upon. I want to know whether the problem of 80 per cent of our population living in the rural areas would be solved by merely opening more number of fair price shops. In Tamilnadu even the fair price shops have become the victim of rampant black-marketing in Tamilnadu. The good rise supplied to fairprice shops is sold in the market. The rice mixed with stonesand mud is distributed by these fair price shops. The sugar is adulterated in the fairprice shops. In my district, I know that Kerosene mixed with water was supled in Gangalkondan village. Some news items have appeared about the mixing of water with wagon-loads of kerosene. You have formulated the public distribution scheme with the laudable objective of serving the poor people. But the fairprice shops have become the centres of blackmarketing, where rice unfit for human consumption is supplied. The samples of rice with insects have been shown to the Finance Minister of the State in th Legislative Assembly.

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

DR. V. KULANDAIVELU: All are heraing patiently.

MR. DEPUTY SPEAKER: Everybody has got to hear whatever you say. Mr. Kulandaivelu, your party has already had one speaker.

DR. V. KULANDAIVELU: Five minutes more.

MR. DEPUTY SPEAKER: I cannot give you any more time. The Minister has got to reply at 5 o'clock. Your colleague has already spoken. You say one sentence 'I conclude' and resume your seat.

DR. V. KULANDAIVELU: Sir, each fairprice shop is to supply 20 kgs. of rice per family. 1.3 crore family ration cards have been distributed. Actually, each family gets only 2 to 4 kgs. of rice on this ration card. You can imagine how the rural people can survive. The people who feed the nation are not being fed adequately.

When Dr. Kalaignar Karunanidhi was the Chief Minister, he had ensured that there was no stopping of supply of foodgrains from the State to the Central Pool. But, after 1976 the State did not supply foodgrains to the Central Pool. In 1978-79 the State offered foodgrains to the Central Pool. The Inspectors of Food Corporation of India found the foodgrains unfit for human consumption and the offer was not accepted. There is no meaning in the State Government repeatedly saying that the State offered foodgrains to the Central Pool in 1978-79.

I would like to know what has happened to all the foodgrains procured by the State Government during these years. Sir, the Centre formulated a sound policy for equitable distribution of foodgrains throughout the country by abolishing the ban on the movement of foodgrains from one State to the other. Tamilnadu Government misutilised this opportunity by sending huge quantities of rice to Kerala. That is the cause of present scarcity of foodgrains in the State. Then, the Chief Minister resorted to the cheap stunt of fasting to attract the attention of the Centre about this. After he visited Delhi, he changed his stance.

That is why I have been saying that the Centre should at least warn the State Governments, whether they are ruled by the Congress-I party or any other party,

[Dr. Kulandaivelu]

that they are liable to be dismissed for administrative inefficiency and inept handling of important issues concerning common people. Before I conclude, I would refer to the State Government's misuse of funds provided for NREP and Food for work Scheme formulated by the Centre on the State's Self-Sufficiency schemes so that the credit goes to the State Government at the cost of Centre.

MR. DEPUTY SPEAKER: You have to obey the Chair. You must conclude. I am not going to allow you a single minute more. You have already taken more than 20 minutes. I am asking you to conclude.

DR. V. KULANDAIVELU: I am concluding, Sir. Such serious irregularities are taking place in Tamil Nadu. I want that the Centre should look into these things and set right the things in Tamil Nadu so that the people of Tamilnadu get the much-needed succour for their survival.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा जिनकी हमारे माननीय सदस्य कर चुके हैं । चाहे इधर या उधर के बोलने वाले सदस्य हों, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि वे हमारी वितरण व्यवस्था पर दोषारोपण करें । पूरे देश में वितरण और बफर स्टाफ बनाने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व इस विभाग पर है । इन सारी चीजों को देखते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेदारी इसी विभाग पर है । हमें उन बातों को भी देखना पड़गा कि किस लिमिटेशन में ये काम करते हैं । इन्होंने वितरण व्यवस्था को ही दूरस्त नहीं किया बल्कि जो प्राफिटियर्स, स्मगलर्स या ब्लैक मार्किटियर्स थे, उनके खिलाफ भी एक्सन लिया है । मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । आज सारे देश में 2 लाख 80 हजार के करीब राशन की दुकानें हैं । मार्जिन आफ प्राफिट बहुत कम है इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । महीने के अन्त में दुकानों पर सामान पहुंचता है जिससे वह पूरा वितरित नहीं हो पाता । नतीजा यह होता है कि ब्लैक मार्किट करने का मौका मिल जाता है । मैं चाहता हूं कि पूरे देश में एक ही तरह से खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए । देश के जो विभिन्न इंटीरियर भाग हैं उनमें भी एक तरह से होना चाहिए । ढुलाई में भी छूट होनी चाहिए ताकि दुकान चलाने में कठिनाई न हो ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हिन्दुस्तान के काफी हिस्सों में सूखा पड़ा है । पांच करोड़ हैक्टर भूमि सूखे से प्रभावित है । इसके अलावा बाढ़ और साइक्लोन से भी काफी प्रभावित है और इस समय 32 करोड़ लोग कठिनाई में हैं । उत्तर प्रदेश में 57 में से 46 जिले सूखे से प्रभावित हैं जिनमें मिर्जापुर सबसे ज्यादा है । मंत्री जी ने कहा कि वितरण व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है । लेकिन जो परामर्शदात्री समिति बनी है, उसके अध्यक्ष के नाते मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां दस-दस और बीस-बीस हजार यूनिट पर दुकानें हैं और जहां 20–20 किलोमीटर से राशन लाना पड़ता है, वहां कुछ सुधार होना चाहिए । आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे व्यवस्था ठीक चल सकती है । मैं माननीय डागा जी की इस बात से सहमत हूं कि जहां पर गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, और प्लानिंग कमीशन ने भी जो 6 प्रकार के एरियाज कहे हैं जैसे बाढ़, सूखा, साइक्लोन, डैजर्ट, पहाड़ी, और ट्राइबल एरियाज, इन इलाकों में विशेष रूप से वितरण की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिये जरूरी है कि राशन की दुकान दो हजार यूनिट पर हो । प्रधान मंत्री

ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्स दी हैं । इसलिये राज्य सरकारों को आप मजबूर करें कि उस के अनुसार दुकानें खोलें ताकि लोगों को खाने के लिये राशन मिल सके ।

उत्तर प्रदेश की हालत गम्भीर है । 20 करोड़ रु० गन्ना किसानों को नहीं दे सकती है वहां की सरकार क्योंकि उसके साधन सीमित हैं । वहां की राज्य सरकार ने केन्द्र से 20 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता मांगी है । मंत्री महोदय उसकी व्यवस्था करें । साथ ही जो कस्टोडियन मिल्स हैं 5, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रेट्स तय किये हैं वह नहीं दे रही हैं । एक ही जिले में एक मिल में गन्ने का दाम कम मिलता है और दूसरी में ज्यादा मिलता है । इससे किसानों में बड़ा असंतोष है जिसको आपको दूर करना चाहिये । अगर जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो लोगों को कठिनाई होगी ।

इनकी रिपोर्ट में हमने देखा कि ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स के खिलाफ़ ऐक्शन हुआ है, वहां हमने यह नहीं देखा कि आपकी वितरण व्यवस्था में लगने वाले जो हजारों कर्मचारी हैं उनको कितनों को सजा मिली है ? आज थोड़ा लगाम करने की जरूरत है ताकि कर्मचारियों में फैला भ्रष्टाचार समाप्त हो । साथ ही जहां आपने ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स को पकड़ा है, पकड़ा तो एक लाख को लेकिन सजा मुश्किल से 1 हजार को ही हो पाती है, तमाम तरह के दबाव पड़ते हैं और कठिनाइयां सामने आती हैं । इस में भी सुधार लाने की जरूरत है ताकि जो भी समाज विरोधी काम करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा अवश्य मिल सके । इसलिये आप दो पहलू जरूर देखें, एक तो चारों किस्म के जो असामाजिक तत्व हैं जैसे ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स, स्मगलर्स आदि इन के ऊपर कंट्रोल करें और दूसरी तरफ़ इनके साथ जो सांठ गांठ करते हैं कर्मचारी, चाहे वह केन्द्र के हों या प्रदेशों के, उनको निश्चित तौर से सजा मिलनी चाहिये ।

सही है कि एफ० सी० आई० की बहुत जरूरत है इतने बड़े विशाल देश के लिये । लेकिन उसमें जो कमियां, खामियां हैं जैसा पांडे जी ने भी कहा क्या यह बात सही नहीं है कि 117 करोड़ रु० का नुकसान स्टोरेज की गड़बड़ी के कारण हुआ है ? क्या इसको देश बर्दाश्त कर सकता है ? इसी तरह से रेलवे को साढ़े 5 करोड़ रु० का डैमरेज एफ० सी० आई० को देना पड़ा । इसमें सुधार होना चाहिये । फूड कोरपोरेशन में जो लोग लगे हुए हैं समय से गल्ला निश्चित तौर से वितरण के लिये नहीं देते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारियों ने कई बार केन्द्र सरकार से कहा है कि समय से अगर वितरण करें तो काफ़ी समस्यायें दूर हो सकती हैं । तो मैं चाहता हूं कि जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिये मंत्री जी प्रयास करें । और जैसा मैंने कहा तीन सालों से 1980–81 से ले कर 1982–83 तक कहीं सूखा, कहीं बाढ़ का प्रकोप रहता है । उत्तर प्रदेश में 46 जिले सूखे से प्रभावित हैं । वहीं पर 49 जिले बाढ़ से प्रभावित थे । हम आभारी हैं प्रधान मंत्री के तमिलनाडु में गई और वहां की स्थिति अपनी आंखों से देखी और 10 करोड़ रु० दिये और अतिरिक्त गल्ला भी भेजने की व्यवस्था करायी है लेकिन उत्तर प्रदेश में सितम्बर में यहां से दल गया था और जब ऐस्टीमेट लगा ही रहे थे तब तक भयंकर बाढ़ से अगस्त में उत्तर प्रदेश तबाह हो गया । तो सूखे की चर्चा करनी केन्द्र ने बन्द कर दी । स्टेट गवर्नमेंट बारबार लिख रही है लेकिन

[प्रो राम प्यारे पनिका]

केन्द्र सरकार ने लिखा कि सूखे के लिये सहायता देने में कठिनाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 164 करोड़ की मांग की है। जब यहां से दल गया तो उन्होंने सारी घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि 46 जिलों में सूखा है, यह उन्होंने माना है। मैं मंत्री जी से चाहता हूं, यद्यपि यह उनके विभाग का काम नहीं है, कृषि मंत्रालय का काम है, तथापि उनसे कहूंगा कि आप व्यवस्था करने । अन्नदाता आप बन गये हैं । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा हो रही है, वह नहीं होनी चाहिये । उत्तर प्रदेश ही नहीं जितने भी प्रदेश हिन्दुस्तान के हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, सब का बराबर ध्यान रहना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं निश्चित तौर से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मुझे विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने कार्य का संचालन किया है, यह निश्चित है कि जैसे-जैसे काम बढ़ेगा, उनके पंजे से भ्रष्ट लोग नहीं बच सकेंगे। जब अगला वर्ष आयेगा तो चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, जो आज यहां उल्टी बातें कह रहे हैं, उनके बजाय वह निश्चित तरीके से मंत्री जी की तारीफ करेंगे ।

*SHRI S. T. K. JAKKAYAN (Periyakulam): Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam I would like to participate in the debate on the Demands for Grants of the Ministry of Food and Civil Supplies and place before the House a few suggestions of mine.

Sir, I convey my deep sense of gratitude to the Hon. Prime Minister for having visited Tamil Nadu and made a personal assessment of the seriousness of drought in the State. I welcome her announcement about the sanction of Rs. 10 crores for drought relief measures, Rs. 10 lakhs from her Drought Relief Fund for individual families afflicted by drought and the despatch of 10000 tonnes of rice to Tamil Nadu forthwith. This confirms her great humanism. At the same time, this also confirm that fact that our hon. Chief Minister's recent fast has not gone in vain.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): This gives the impression that the Centre was frightened by the Chief Minister's fast and consequently decided to supply foodgrains to the State.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is for the Minister to reply. He is expressing his own views and it is for the Minister to reply to that.

SHRI S. T. K. JAKKAYAN: Sir, the hon. Prime Minister has also stated that the Central Government would take all the necessary further steps after studying the Report of the Central Team that visited Tamil Nadu and studied the extent of drought in the State. It is more than a month that the Central Team has returned to the capital and by now the report should have been submitted by the Team and the examination also should have been completed. In the matter of a critical situation like this, where the lives of common people are involved, there should not be any delay. I suggest that the Ministry should take immediate steps in the examination of this Central Team's report and rush all the necessary assistance in finance and foodgrains to the State.

I would like to take this opportunity to suggest that there should be no political predilictions in tackling drought situation. It is being said that due to mismanagement of foodgrains by the State Government this critical situation has come about in the State. I would only say that this is not based on proper assessment of the facts.

*The original speech was delivered in Tamil.

The hon. Member, Shri Kulandaivelu, who preceded me, mentioned that the State Government had offered 2 lakh tonnes of rotten foodgrains, unfit for human consumption, to the Central Pool in 1978-79. I would emphatically say that this is far from truth. The Centre asked us to take 70,000 tonnes of this rice for National Rural Employment Project and paid the money towards that. This means that 70,000 tonnes of rice were good and naturally it follows that the balance of 1.3 lakh tonnes was also good. I want that the Minister should clarify this issue so that this controversy is ended for ever.

Shri Kulandaivelu also mentioned about the prevalence of widespread blackmarketing in Tamil Nadu and he referred to non-existing administrative irregularities in the part of the State Government. I would deny this with all the force a my command. The people of Tamil Nadu have immence faith in our Puratchi Thalaivar and his Government. They have exhibited this unequivocally in the bye-elections that have been held in Tamil Nadu both for the Lok Sabha and for the Tamilnadu Assembly. The have given their seal of approval on the functioning of the Government of Tamilnadu under the dynamic leadership of our Puratchi Thalaivar by electing with overwhelming majority the AIADMK candidates in these bye-elections. In other words, it proves beyond doubt that there is no blackmarketing in Tamil Nadu and there are no irregularities on the part of the State Government.

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): Sir, this is not...

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is replying to you. Leave it at that.

SHRI S. T. K. JAKKAYAN: Sir, I would also refute his contention that there were 19 starvation deaths in Tamil Nadu. On account of paucity of time, I would not refer to official documents. But there are official documents to prove that there have been no starvation deaths in Tamil Nadu.

Coming now to the point of mismanagement of foodgrains, I would refer to the fact that the Chief Minister has personally seen to it that the number of fairprice shops is increased in the State by more than 15 per cent—from 7,000 to 17,700. He has also ordered that those getting Rs. 1000 and above per month as salary are not entitled to draw essential commodities from fairprice shops. In other words, the common people are enabled to have additional quantum of foodgrains through fairprice shops. I am sure that this calls for the commendation, and not condemnation of the efforts of our Chief Minister.

Sir, I would say that it s political anachronism not to depend upon the report on drought presented by the popularly-elected Chief Minister of the State but to depend on the report of some officials accustomed to air-conditioned environment in the Capital for taking steps to fight the drought in a State. If the Centre approves the assessment of the Chief Minister of the State about the drought situation, it will be showing respect to the people of the State who have elected him; it will nurture democracy in the country. The second alternative of depending upon the report of the official team will in course of time undermine democratic ethics in the country. I appeal to the hon. Minister not to do injustice to the people of the State. He should rush the necessary quantum of foodgrains and financial assistance needed by the State to tackle the drought situation on a war-footing. I demand that 80000 tonnes of rice and 20000 tonnes of wheat as demanded by the Chief Minister should be despatched to the State of Tamil Nadu without further delay. One who gives rice gives life on this earth. Before I conclude, I appeal to the Minister to extend the much-needed succour to the people of Tamil Nadu. I thank you very much for this opportunity given to me and I conclude my speech.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, due to the drought conditions in various States, there is a great pressure on the management of the food system in this country. There are three aspects of our food policy; one is the procurement system, two is the storage and the third is the supply system.

[Shri R. L. Bhatia]

So far as the procurement is concerned, all the States are not contributing to the Central kitty, although our friends from Tamil Nadu, West Bengal, Kerala and other States go on criticising the Centre in this respect. I would like to tell them that the States must set their house in order first. You must procure and contribute to the Central kitty, as far as you can... (*Interruptions*). I know that is the responsibility of the Central Government. They will supply you rice if you need it; if there is a drought, they will help you, but before you criticise the Central Government, you must set your own house in order. You should not be always demanding and not contributing anything to the kitty of the Centre.

Now, the whole burden is on Punjab; Punjab is contributing more than 50 per cent to the Central pool, and if you include Haryana, the two States are giving 70 per cent of the total procurement in this country. I would request the Minister that he, as the Food Minister of this country, must emphasise on all the State Governments, that they must come forward and help the Central Government in the matter of procurement of foodgrains. The procurement policy of the Government should be applicable all over the country, and should not be restricted to two or three States. This is very important. Procurement policy should be enforced strictly throughout and all the States should be asked to contribute to the Central pool as much as they can. Take for instance, the Kerala State. Ninety-five thousand tonnes of rice are a regular quota per month for them, it is being supplied to them. They have been demanding more to meet their requirement. The Minister has permitted them to purchase from Punjab and other areas ten thousand tonnes more. The Central Government will always come to their help; it is not that they do not want to help them, but the States also must come forward and set their house in order. While the Centre is prepared to extend all sorts of facilities to the States like overdrafts etc., the States should also come forward in the matter of procurement of foodgrains for the Central pool.

17.00 hrs.

With regard to storage, adequate arrangements have been made by the Centre, and every year the storage capicity is being increased, yet we find that a large quantity of foodgrains remain outside the godowns, and they are exposed to the vagaries of rain and adverse weather, and the foodgrains get spoiled. The Government is bound to procure foodgrains from the growers at a particular rate fixed for this purpose. Last year, a very big quantity of damaged wheat was purchased. I do not know, whether all that wheat has been consumed, or some quantity is still lying in the godowns. I would like a statement from the Minister as to how much of that quantity has been consumed and how much is still lying. I would also request the Minister to increase the storage capacity of the godowns so that the valuable commodity is not wasted.

Now, I come to the third aspect; and that is distribution of the foodgrains. I do not have to say much because my friends have already stated enough. Again, the distribution is with the State Governments. Here also I would request the friends sitting opposite, who always criticise the Government, that they must ask their State Governments to set their own house in order, because the distribution is with the State Governments. I know, what the depot holders are doing; everybody knows that..... (*Interruptions*). I am not yielding.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. Everybody has got the right to express his opinion? Please sit down. Is it parliamentary?.....This is not parliamentary. You have got your own views, and you must allow others to express their views.....So many hon. Members were criticising the Central Government, and nobody from this side got up and said anything.....He is within his rights to express has opinion. Can't he ask the State Governments to do better? It is not proper.

(*Interruptions*).

SHRI R. L. BHATIA: the other day there was a press report that in Delhi only 60 percent draw their rations from the fair price shops, and 40 per cent do not get their rations. I would like to ask, where that ration goes.... (*Interruptions*). As I said, there is a need for improvement in the distribution system, and since the distribution system is with the States, they should improve the system for better service..... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY SPEAKER. If your distribution system is perfect, you should keep quite.

SHRI R. L. BHATIA. So my request is that the distribution system should be streamlined. If there are defects, they should be removed at all levels—Central as well as State level.

Sir, in Punjab the agriculturists are really feeling that they should change over to some other crop from wheat. It is a constant feeling among the farmers. More and more farmers are thinking of going over to cane-growing, because they are not getting adequate price for wheat. Although this is not the direct concern of the Hon. Minister, still through him, I would request the Government that the cultivators must be given adequate price and that the minimum price of wheat should be fixed at Rs. 155.

Secondly, only after the crop arrives in the market, its prices are announced. I fail to understand what is this policy of the Government. The prices of the commodities should always be announced before-hand. The wheat has already started coming in the market, but the Government has not so far declared its prices with the result that the farmers are forced to sell it at the old price of Rs. 142.

Sir, the Government is giving quotas to the States for their flour mills and the price is fixed at which all the flour mills in India are given wheat. But we find there is a variance in the sale price of its products. In Tamil Nadu it is different; in Bengal it is different; in Orissa it is different. When the Government is procuring wheat at a particular price of Rs. 142 and subsidising that wheat and then giving it at a particular price to all the States, then its product should also be of the same price everywhere. Why should it be more in Bengal or in any other State like U.P. or in Delhi? It should be the same throughout the country.

Lastly, Sir, Basmati is exported out of India, but what we find is that even the ordinary rice is going out of the country in the name of Basmati rice. Government has no control on that. This is one of the causes why the price of rice has shot up in the country. There must be some check at the places from where Basmati is being exported or the Government should adopt some other policy so that the rice, which is consumed by ordinary and average consumers in the country does not go out because we need it very much within the country.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to all the twentyfour Members, who have participated in the debate—quite a big number on this debate. I am very grateful to them for the support, for some kind words, for their critical speach and sometimes shooting cross-bats I am specially grateful to Shri Lawrence, who opened the debate as opening batsman. He did it all round the wicket, but with a cross-bat. I advice him as an opening batsman he should be more careful in his batting so that he should know where he has to hit. In most of his speach he has said about land ceiling, irrigation, purchasing power, which are no doubt, an integral part of the Indian economy, but certainly not part of my Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Azad, you learnt about cricket from your son or you yourself are a cricketer?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Sir, I confess that I have learnt it from my

[Shri Bhagwat Jha Azad]

son, but my son has learnt the sportsman spirit from me.

Sir, the food economy of this country is such that to manage this is a very stupendous and difficult task. It is stupendous task considering the magnitude of the country and the magnitude of the problems is great specially in this particular year when I have been called upon to hold the Charge of this Ministry as the Hon. Member has said that there has been a widespread drought in the country—drought in about 42.87 million hectares affecting about 26 crores of people. But inspite of the vagarier of nature and erratic monsoons in this country, we can look back at the earlier years with pride and say that we have been able to manage well. Before this, we had drought in 1979 and 1980; and as I will subsequently say, our public distribution system or procurement and other operations in food economy have done well to control and contain prices and also have been able to come to the help of the States in this country, which the off-take in the consecutive years clearly shows.

Inspite of this, we have had no critical shortage in this country. Without straining any part of the economy, the food economy could take care of itself and could provide relief, and bread and butter that were needed by the Indian people. This could be done. We could achieve this due to proper procurement, efficient storage, maintenance of buffer stocks timely movement and organized distribution. On all these points, hon. Members have commented.

There are shortfalls and shortcomings—I must, at the outset admit it. The question is: in the light of the advice that the hon. Members have given how best can we improve the position in matters like shortages? But the fact remains that inspite of these things, things have to be looked at against the background of the magnitude of the problem, and the results achieved. I am not satisfied. So are all the hon. Members. They should not be satisfied. But the price policy in respect of procurement of the grain, has been announced. What is the objective behind it? The objective behind that policy is that we propose to give a remunerative price to the farmers, so that they can have an incentive to producee more, and produce more with the latest technique, and latest developments in the field of agriculture.

Our second aim is not only that we should support the farmers, give them the incentive price, but also see that the production that we get or what we procure, is available to the consumers, at reasonable prices. Thirdly, the aim of our food economy is that we should maintain the price level and avoid regional disparities. I agree with the hon. Members that the procurement price should be declared very soon for wheat because it has started coming into the market. APCs recommendation has been received and very shortly, we will be able to announce the price of wheat.

With APC's recommendations we have normally agreed; but at times, on a few occasions we have disagreed because though it is an expert committee, we also have advice from others. We have also the recommendations of the State Governments, which we have to take into consideration. So also we have to take into consideration the interest of the consumers and their welfare.

Some hon. Members have suggested Rs. 200/- per quintal. Some have suggested Rs. 185/- We would like very much to ask: why Rs. 200/-? Why not more? The question is that at the same time, we should also keep in mind what would be the issue price. What is the price at which the weaker sections of the community, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes whose purchasing power is very much less, will get it?

While considering the prices suggested, we have to take into consideration the vulnerable sections of our society, and also the producers and farmers. And we have to make things available to them, because

they are the consumers. They consume what we produce. Therefore, while considering these recommendations, we have to keep in mind this consideration—the most important consideration.

If we see from the procurement that we have got in 1981-82, that is, July to June we had 152 lakh tonnes that we procured compared to 1980-81 when we had only 123 lakh tonnes; but it can also be compared to 1978-79 when we had the last highest at 144 lakh tonnes. Therefore, I would say that if we see the figures we will find that it gives us the encouragement to proceed on our own way of procurement.

When I emphasise on 12 1|2 per cent I did not say that this is what we are procuring all these years. No. It was 9.7 per cent in 1979-80 and 10.4 per cent in 1980-81. We have come to 12.5 of the total production of the cereals this year. What I wanted to emphasise by this is that we are only procuring this percentage does not mean that we rest on our oars and we do not want to procure more. It all depends upon what is the production, it depends upon how much the States or the farmers are willing to give to us, because it should be always remembered that we do not want farmers to have a price which is not economical, which is not encouraging incentive to them. Therefore, in this case, we only give a support price rather if they get more in the market, they go and have it. Therefore, we have to keep all these things in mind. In this case, I would like to say that we will continue to procure, we will try to procure more, but it depends upon the production, depends upon the machinery that I have with me, its efficiency, its quick reaction, its resilience of the economy; it all depends on that.

I hope as all State Governments are procuring so also they will allow FCI as in the past to procure. I was told—I hope it is not true that some State Governments have been probably thinking that let them procure for themselves and not FCI. It will be a great setback to the Indian food economy if any State Government thinks on this line. I hope, as we had in the past done, so we will do in future. It is not a question of States demanding it and the Centre supplying it; it is not a question of some States producing it only and from there other States getting it; it is a question of the cooperation between the State Governmenss and the Central Government in managemen of the food economy which is really difficult and this year much more difficult. Therefore, I would say with this we can see that it is possible for us to manage our economy with 12.5 per cent procurement as compared to 9.7 per cent, as I said in 1979-80; it was 10.4 per cent in 1980-81. I hope in future with more production, and with better management by the FCI with our instrument of procurement or operations, we will be able to procure more. Therefore, I would say that we are on the right lines.

But one thing I would like to emphasise, that is, where the friends have criticised why don't you take the entire foodgrains, nationalise the foodgrains? This question was debated in this House and so also outside not only this year but in yester-years also. We tried once, but it was given up. My friends can very well say, you are incapable of doing it; you could not do it.

SHRI SUNIL MAITRA : Half-hearted.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I would like to say that in this country, wedded to mixed economy, it is true that a larger part, rather a major part, rather an overwhelming part of the food trade is in the hands of the private sector. We are a supplementing agency only. Therefore, what I want to highlight is this that we will certainly do your best to help Tamilnadu, Kerala, Orissa, Bihar, Maharashtra, Rajasthan and all other States, but we will be able to help them only when we have friends from Andhra Pradesh, when we have friends from Punjab and Haryana who are producing more. Therefore, it is a question of procuring it with the goodwill of surplus States and giving it to the deficit States who are producing less.

[Shri Bhagawat Jha Azad]

I will not say that they are not producing. That is not my point of view. For example, Kerala when it produces, produces other materials which are cash crops. That is there. I do not deny that. When I give 95,000 tonnes of rice to Kerala I do not do any obligation to them. What I am saying is that they are producing rice, but at the same time, they are producing rubber also and they are producing other cash-crops also for us. (*Interruptions*).

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: Even 95,000 tonnes is not enough. It is only half of the ration.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: This food economy has to be appreciated by all our friends here. That is what I am trying to bring home to the hon. Members here, that it is not possible for the Central Government to meet the entire requirements of the States. It is not possible. Even if you see it the other way, the fact remains that this contingency will be there even when we give much more than 95,000 tonnes. And even this much is given with great difficulty. Mr. Deputy-Speaker, this year due to drought, the production of rice has gone down; we had drought in a large part of the country. We mentioned it in the annual report that it is about 5 to 8 million tonnes of foodgrains. Therefore, it is not out of pleasure that I say, I meant it seriously, that people in Bihar and Eastern Uttar Pradesh, who were always eating rice not only in two meals per day but three meals per day—they were having some times a morning breakfast—have now come down to only one rice meal a day. I know that it is very difficult for our people in Kerala, Tamil Nadu and West Bengal to switch over immediately to one rich meal per day. I suppose we have to keep this in mind that in the years to come, we have to change our tastes and food habits accordingly. Therefore, when I say in this country, I mean, for the entire country treating it as a single zone, where we have a long background of our mixed economy, we have to take a decision for it, treating the whole country as a single zone. The movement of foodgrains is un-restricted now. They are allowed to be moved among all the States. Therefore, I would say, that the allocation from the central pool depends, for example, on the demands from the States. It depends upon what is available in the central pool; it depends upon the prices ruling in the market and other considerations and therefore, from month to month we are trying to put the scales even by taking into consideration all the relevant factors. I know, when the hon. lady Member says that it is only half the quota, I know that demand is there. But I also want her to realise this.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: That is not enough !

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: palan, everytime, you are getting up. He is explaining your case only. He is not explaining his case. He is explaining your own case. Why do you get up every time? (*interruptions*)

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: But, what is the result?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: That is what I am saying. Please lend me your ears. You will appreciate in a few minutes. I am coming to the point.

Mr. Deputy-Speaker, what I am saying is not that I have got some surplus foodgrains and I am not giving them. I only want the hon. lady Member to appreciate that it all depends on so many factors. Not only there is demand, but we have also to see what is available in the central pool. It also depends on how much I am able to persuade the other States to give me. I am trying and I hope I will be getting something more. I hope that it will be possible for me to give more to Kerala State. That is what I am trying. I am talking to our friends in Andhra Pradesh who have got surplus stock with them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is what the Minister is telling. When the Minister is replying you should listen.

(*Interruptions*)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Therefore, Sir, it all depends upon the demands from the different State Governments. Much depends upon what is available in the central pool. Much also depends upon other considerations. We are trying our best to do what can be done.

In the light of this, therefore, this morning I have decided to give to Tamil Nadu, foodgrains from other places. The Prime Minister has decided to give Tamil Nadu about Rs. 10.00 crores and she has also announced increased to allotment of foodgrains—from April, 15,000 tonnes of rice and 15,000 tonnes of wheat. That means, we will be able to give them 30,000 tonnes from April. (*Interruptions*) We have already given Tamil Nadu permission to purchase 20,000 tonnes of rice from Haryana and Punjab. We have now given them permission to purchase 50,000 tonnes of rice from Andhra Pradesh.

Now, coming to Kerala, I hope, the hon. Lady Member will hear me.

SHRI K. MAYATHEVAR: Rice should not be misused in Tamil Nadu....

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has gone to Kerala from Tamil Nadu.

SHRI K. MAYATHEVAR: The rice is granted by you. And you allow the State Government of Tamil Nadu to purchase rice at subsidised rates from other States also. Will you see that the rice is distributed through fair price shops only?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: To that my reply is that he should use his influence and his powerfull boys in Tamil Nadu to pressurise Tamil Nadu Government to do it better. I would advise them. I cannot interfere there.

So, far as Kerala is concerned, from 95,000 tonnes per month, we have increased it to 1.05 lakh tonnes per month. I am also giving them 25,000 tonnes of wheat. It comes to 1.30 lakh tonnes per month of allotment to Kerala. I have also given them permission to purchase 15,000 tonnes from Punjab and Haryana markets and 30,000 tonnes from Andhra Pradesh markets. (*Interruptions*)

SHRI SUNIL MAITRA: Would you please ensure that the allocations, that you have just announced, really reach Kerala?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Yes, with affirmative and definite yes, it shall reach. Please advise them to get it in time and distribute it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: For my information, would you kindly say whether Kerala has become number one or West Bengal continues to be number one?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: West Bengal still enjoys the privilege to have 20 per cent of the total procurement of the whole country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kerala will accept that because I know that they do not want to defeat West Bengal.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: We know that Orissa also has a difficult time. Therefore, I have increased their allotment by 5000 tonnes of rice and 5000 tonnes of wheat. Therefore, they will get now 15,000 tonnes of rice and 17,000 tonnes of wheat, total 32,000 tonnes whereas they were getting 22,000 tonnes, every month.

I had a very strong demand from Bihar both for wheat and rice. But I could not give them rice. I would very well advise them—they will appreciate me better than the other friends do,—to do with wheat. Therefore, I have given them 10,000 tonnes of wheat more.

I will consider the demand of other States as and when I get from them the problems as they face. What I was trying to do is what do these indicate? These indicate that the public distribution system in this country through which we are trying to distribute the foodgrains, has proved its utility. If we see the total off-take in a few years, in 1978 it was only 101.83 lakh tonnes, in 1979 it rose to 116.63 lakh tonnes in 1980 it was 149.93 lakh

[Shri Bhagawat Jha Azad]

tonnes—it was a drought year—in 1981 it was 130.14 lakh tonnes in 1982, this is to be marked, the off-take has gone up to 147.81 lakh tonnes. If we compare this, in the first six months in 1982, it was 11.82 lakh tonnes average per month, in the last six months in 1982, the average off-take was 12.82 lakh tonnes. If you compare with January 1983, it has gone up to 14.46 lakh tonnes. All those indicate that the public distribution system as it stood in the drought of 1979-80, will also stand the stress and strain of this drought also. I am not a pessimist like my Mahamantri—I am a Mantri but he was my Mahamantri—Mr. Daga who had every thing black before him to see, in comparison, I will appreciate the friends Mr. Panika, Mr. Vyas, Mr. Pandey and others who saw something better in public distribution system. I would call upon my Mahamantri, this humble Mantri will call upon the Mahamantri, that he can call a meeting of his party which is in the Government, and give us the order and advice and I will accordingly do it.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: He is not here.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Therefore, what I say is that I am not at all satisfied, nobody, in the Government, is satisfied, with our performance. We want to do much better and better and better. But the fact remains that the public distribution system, with this off-take going up every year, has stood the test of the time. That is what I want to emphasise. Therefore, I would say that kindly remember one thing in mind how can it be possible for us to meet all the demands? For example, in 1982 the total demand from all the States was 254.8 lakh tonnes but we could give them, according to our procurement, 145.9 lakh tonnes. Therefore, sometimes, the States also feel that Mr. Azad or Rao Birendra Singh, whoever he might be, he will like to make some cut. Therefore, instead of 30,000 tonnes, they put full figure of one lakh tonnes. We try our best, argue with them that we are all friends, I have not got this much. Therefore, it goes on. It is a friendly American free-style wrestling in which they demand more. Not that I am saying that there are no difficult times, mind you Sir. Please do not see it on that light. I am not saying that, otherwise the friend will say that I am belittling them in Kerala. No, Sir. Sometimes, it so happens. Therefore, what I am saying is that it is not possible for us to meet the total demand of all the States because what we procure from the surplus States in the Central pool, is not at all matching to that total demand. Therefore, even in spite of that total demand and the allocation, we have seen, as I have quoted the figures for all the 5-6 years, that we have been able to manage very well and managed to the satisfaction of the States and to the demand of the time and the challenge of the vagaries of Monsoons and others. Even apart from this, when there is drought, there is flood, even in those times also we come with the extra help. For example, we gave to Orissa 15,000 tonnes of rice when they had that difficult time due to flood. We gave 10,000 tonnes of wheat to Bihar, 10,000 tonnes of wheat to U.P. and 5,000 tonnes of rice to Assam. In this way, whenever they had other difficulties, we came to their help.

Hon. Members have said about the team that had gone. When there is a drought, the team goes. Just the team has come back from Tamil Nadu and has given its report. Immediately we will try to release, because through Employment Generation Scheme for drought-affected States, we give them the help and we have been able to give them help in the past also. They have been able to generate man-days in that.

My friend from the AIADMK has asked me to explain it; otherwise, I would not have explained it, I may tell you, because I wanted to keep neutral between those two parties. I would not have stated it otherwise. I must say that it is true that upto 1975-76 we had contribution to the Central pool from the Tamil Nadu Government.

SHRI K. MAYATHEVAR: By the DMK Government.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: All right. I agree. Who was the Chief Minister then?

SHRI K. MAYATHEVAR: Shri Karunanidhi.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Yes, Shri Karunanidhi. That should go on record. What I say, as I said the other day also, is, after that we did not get it. Tamil Nadu said "we will manage it ourselves". We thought it is better for them to give because if they give their surplus to me, I can pass it to Kerala. If Punjab has surplus, I can pass it on to Bihar. But they did not give. He wanted an explanation from me: tell me, what has happened about their 1979-80 rice, was it not good; it was not rotten. The friends from DMK said they were not good. The other friends said: give me an explanation. I would humbly say that they were offered to me at a time when ,after trying to sift better quality-grain from the other one it was just not possible for us to accept that. Technically, they said: all right, they are bad, but you give us that, take it on your account and give us something for the Food for Work Programme. They also said, whatever may be the other quantity, there are good ones also, that small amount was distributed by them for the Food for Work. But the other rice was not good. Since you wanted me to mention it I wanted it to go on record that was not good. But that is not the point for me. The Prime Miinster day before yesterday did not consider that point whether Tamil Nadu has contributed or not. That is not the question we are considering. We are only trying to say about the Central Pool that if all the Governments in their good days, in their surplus years, contribute to the Central Pool, then they will have a better right to come to us and say "look, now I have got a difficulty, you must help". Even now we are helping. We are trying our best; we are doing it. So, I would say that this should be kept in mind. I must say that when I met the Chief Minister, Shri Ramachandran, for the first time after taking up my assignment as Food Minister, I pressed this point upon him and he agreed that it would be possible for the Tamil Nadu Government in times of surplus to contribute to the Central Pool. There were some Congress Governments also, who were not in the pool. They all have to fall in line. I hope all the States in the country will be members of the Central Pool and contribute according to their mite.

With this kind of procurement, the most important thing for us is distribution, which the hon. Members have emphasized again and again. All our efforts in procurements are just trying to squeeze something from here, something from there, give something to Kerala, something to some other State. But it will not be good, unless they are distributed properly by the distribution system. That is why my friends have all emphasized it.

Shri Daga said "Mr. Minister will say very nicely 281,000 shops are there; then he will say this is all my responsibility". Yes, I say this is my responsibility, because I am a law-abiding citizen of this country. I know the Indian Constitution. I have spoken in this House as a private Member, knowing fully well what the Constitution is. The Constitution of India says that it is my duty to distribute what is available in the Central Pool, but it is the duty of the State Governments to distribute it properly. I would request them, I can monitor things, but I cannot force them. Therefore, it is a nice reply and in whatever way my Maha Mantri may take it, I would see that I am discharging my obligations under the Indian Constitution. The areas are defined and there cannot be encroachment.

Can I distribute from the Centre to all the 281,000 shops in this country? Does he mean to say that these shops are not existing? Then, let the hon. Members any day go and make a surprise check in Delhi or in their own State. I can understand that there are difficulties for cities. I can understand that in some shops things are not available in the same quantity as expected, and that is why complaints come. For example, the North Avenue-South Avenue complaint came. Quickly I heard it that day, I did not send the men the same day. After three days I wanted the Delhi Administration Food Commissioner ot send a square to North and South Avenues. They raided the shops and they brought the sample, gave it to me, which is lying with me. Sometimes it is possible

[Shri Bhagwat Jha Azad]

that human nature as it is sometimes functions, rather I should say, mal-functions, and sometimes human beings behave, in this manner. But the reply is not to condemn the entire system which has stood the test of time, but to come down heavily upon such persons through inquiries instituted by the State Governments, and in this I fully associate myself and I fully agree with Mrs. Pramila Dandavate, who said, "If you want to distribute the entire thing in the country in a better way, it requires a powerful consumer movement in this country. By putting an inspector, Sir, I will need another inspector on the inspector. Then there will be a *maha* inspector on the inspector. Sir, it is necessary to have a powerful consumer movement in the country in which case I will appreciate the situation in Kerala State. Not the Government have only done, not the Marxist or the Congress Government has done it, but it is the powerful consumer consciousness in this State which we have to arouse in other parts of the country as well, for which with whatever is available with us—we have been given something in the Sixth Five-Year Plan—to help this organisation, we will certainly help. Rather, there are some voluntary organisations in West Bengal, in Kerala and in Delhi itself. I wanted that let the State Governments tell us how they are doing. Now, I have said, they do not send the reports. But I say, it does not matter, their organisations are doing a good job, let them be given small grants and we give the grants. So, it is necessary that in the public distribution system there must be a powerful consumer movement. I say this in the House that when things are given to State Governments by the FCI, there is a joint inspection by the FCI officer and the State Government officers. Unless we get the certificate from the State Governments that the quality is good, we do not deliver them. I call upon the State Governments, let them exercise their right, and if the FCI gives rotten things, I will pull up the FCI. It is my duty to do that. But let this be also done by them.

Now, about distribution, my friends on the Opposite have said about different State Governments and they have commented. There are possibilities, I do not deny. To FCI I will come later. But what I wanted to say is that the previous system has served well. It is not only in urban areas—62,000 and odd shops, about 62,419 are in the urban areas, and 2,19,039 are in the rural areas. I agree with the hon. Member from Uttar Pradesh that in Uttar Pradesh there are less shops. What happened is, the Government have decided to hand over the shops to the cooperatives instead of to the private persons who are dealing with them. They did one thing. They removed all private agencies, but they could not open that much number on the cooperatives side. Therefore, the members are much less. I will certainly write, I have spoken already to the Civil Supplies Minister, Mr. Vasudev Singh and said, "please increase the number of your shops. I am giving you the quota not only for Lucknow and Varanasi, but also for the distant parts of Almora, Mirzapur and other places where my friends are there, and they should do it." It is necessary, and therefore, I have requested them to do it, and it is our ideal that we must have a shop for every 2000 population. In accordance with that, I must say I have not covered in 2,81,000 the distant parts, inaccessible parts. In *pahari* areas there is a need. "Inaccessible"—this was the word which stuck into the throat of one of my hon. friends. He said "Oh! what a nice thing you are saying, Mr. Minister!" I must tell the boss of the Ministers in the Party that "inaccessible" should not get stuck.

Come to the issue of Santhal Parganas, the *pahari* areas where there are shops. I hope there are shops in Barmer—difficult Rajasthan terrain. Therefore, it is not nice to belittle the system that has served the country. I appreciate the hon. Members from the Opposition who criticised but never said the system as a useless system. They said that the system must be improved by the State Government and the Central Government. I am the Chairman of the Committee which sits or meets once in six months. I do call upon them and request the Civil Supply Ministers to improve the situation. I write letters to the Chief Ministers.

I am a law abiding citizen. I understand what is the Constitution. I cannot force the State Governments, that they must do it. Can you get that done? If any of my friends can get it done, let him get it done. I would say that I request them once in six months in this regard. It is an advisory Committee. I must say that things have improved.

Shri Panika said that things reach the State very late. They are not distributed properly. When I called the last meeting, the State Governments said rather than the third week, please allot it in the second week. The moment I joined this Ministry, I have taken the decision to allot in the first week. Now they have three clear weeks to distribute. They could do it. Therefore, with experience, with such talk, with such a meeting—which is advisory on our part—but they give us a large support and advice us to do it. Therefore, I would say that we have to see to the success of the public distribution system. My friends have said that the most important thing is to make this unit viable. It has been said that you want un-employed graduates to take it over, you want swatantra sainani to take it over. It is for the State Governments to decide the criteria whom to give.

We give seven items from the Central Government. The State Governments are free to add to these items. I must say that West Bengal Government have added a large number of items. To be precise they have added nineteen items which are distributed through the fair price shops. That brings them to the viability. We are asking the State Governments to add to this list. They should arrange. They should procure and distribute so that they can make it viable. In this way, we have been able to do it.

My friend asked me a question, "What are you doing in the Sixth Plan?" In the Sixth Plan we propose to add 50,000 shops. It is my straight answer. Last year we tried to have 10,000 shops. We have reached the figure of 6026 shops. We propose to re-schedule and increase the number.

That is our scheme. That is our ambition. I think we will not fail in that. We will try out best. But it all can be done not by a fiat from me, from the Central Government, but by the co-operation of the State Governments which I am trying and getting in ample measures.

Seventeenth point of the 20 Point Programme is a point which always goads us to have more number of shops, to give them the quantity, not only the seven items, but the State Governments may add to it, to make it economically viable.

It is known that in such difficult times we must have a buffer stock. The decision by the Government of India in 1978 was it wanted us to have a buffer stock of 12 million tonnes and operational stock from 3.5 million tonnes to 8.8 million tonnes. It also wanted us that we should not go below a certain minimum and try to replenish as soon as it is diminished. We are trying to do it. But the fact remains that in difficult times we cannot stick to it, because I have to see what is happening to-day in the States rather than to think strictly in legal or technical terms about all these recommendations. We have to look to the interest of the States at the present moment. If we see the stock position, in 1979 it was 172.28 lakh tonnes. Gradually, in 1980, it was 166.42 lakh tonnes. In 1981, it was 114 lakh tonnes; it went down. In 1982 it was 115.45 lakh tonnes. In 1983, it is 125.22 lakh tonnes In 1983, it is 125.22 lakh tonnes. So, Sir, we are trying to keep it in this way and we hope that it will be possible for us to do so.

Sir, we were not importing since 1975-76. But due to the great drought which visited this country in 1979, we had to import from outside and we did so. We had imported 22.65 lakh tonnes in 1981-82 and 39.50 lakh tonnes in 1982-83. The question always comes and my friends have always said, "you are not giving to the Indian farmers what you are giving to the American farmers." I would like to say that the cost that we give to the American farmers and the cost that we

[Shri Bhagwat Jha Azad]

give to the American farmers and the cost that we give to the Indian farmers are, Sir, identical. They have their own conceptions. Of course, the landed cost, freight, insurance, distribution cost, procurement, incidental charges etc., are put into the imported one. That makes it so. But, Sir, by and large, even if I suppose that we give much more to them then what we are giving to our farmers, when do we import? We do not import every year. We do not have the intention to import at all. But the question is, when the difficulty comes, we have to import. In difficult times, we import. We have to go quickly. I must compliment the then Minister of Food and the Food Secretary because so nicely and quietly they managed the entire operation and that was one of the reasons that the Indian market did not show any sign of stress or strain or any rising prices. It is not our policy to import. But the question of import is only in difficult times. By giving more to the farmers, what would you do? We draw upon the total availability in the Indian market which does not in any way increase what we need in times of difficulty and therefore we have to import. Therefore, I would request the hon. Members to appreciate this point.

One friend Shri Bhatia and another friend Shri Dogra have said about the flour mills. We have 373 flour mills in this country. The total capacity is 82 lakh tonnes. That is what we can procure almost. Even it may be little less. What we are giving them today is about 33 lakh tonnes—40 per cent of the total capacity. It is not possible for us to give more at the present moment. They give wheat products. They give wheat to the bakeries, biscuit makers and all that. That is, they are doing a useful service. We are trying to help them. But within the limit, we are doing it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What Shri Bhatia has said is that you are giving them wheat at the subsidised rates but the products are not sold accordingly.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: That is all right. I will say what happens. They are subject to the control of the State Governments in the different States. They try to control in whatever way they can and make a proper distribution.

It is the State Governments which are doing this.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What about Delhi? Who is controlling Delhi?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: The Delhi Administration is controlling Delhi. It is a simple point. (*Interruptions.*)

AN HON. MEMBER: Delhi M.Ps.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: It is not the Delhi M.Ps. but the Delhi Administration which is controlling Delhi.

I must say that my friend Shri Paranjpe has brought a question from Tamil Nadu about the hullers and other rice-mills. At present, if you go by the conventional system—I have not prepared the brief—but my friend has asked me and I hope, I am right. In the present conventional mills, the percentage of broken-rice is much more. I think, we get 67 to 68 per cent of rice from the present one. And the rice bran that we get out of it is good for extracting oil. But it is mixed up with the husk. So, we want them to modernise the mills in which the rice percentage will be 72 to 73 per cent and the rice bran will be clear from the husk so that we can get more oil. A group of Tamil Nadu millers had come to me and I have heard them. I have heard them. Their time is September, 1983, to modernise. They say, " We have no space; we have no money" and all that. I will see what I can do. But the fact remains that modernisation has its merits. We get more rice; we get more bran and, that means, we get more oil.

Then, I come to the most controversial, the most criticised, point of this debate, that is, the FCI. Shrimati Krishna Sahi, Shri K. C. Pandey, Shri Girdhari Lal Vyas, Shrimati Pramila Dandavate, Dr. Bhoi, Dr. Kalanidhi, Shri Daga, Shri

Shailani and Shri Pranjpe, all of them are in the lot who came in appreciation of the FCI, the other way about. It is an organisation which was established in 1965. Its function is known. It has to purchase from different markets; it has to procure foodgrains; it has to store at temporary points and then they have to move the entire thing till they reach a permanent point in different States and hand over the foodgrains according to the allotment to the State Governments. They have to do this job.

It can be appreciated from the fact that the turnover in 1981-82 was to the tune of Rs. 6,248 crores and, in 1982-83, it came to Rs. 6,800 crores. It consisted of about 320 lakh tonnes in 1981-82 of foodgrains, sugar and fertilisers, all these put together. In regard to idigenous purchase, in 1981-82, they purchased 129 lakh tonnes of foodgrains as compared to 99 lakh tonnes in 1980-81. They handled, in 1981-82, about 22.6 lakh tonnes of imports. Therefore, I would say, before going to what they have been called upon to improve, let us see what a magnitude of work they are doing. This is the job of a very wide magnitude that they are doing for the country. What my friends demand and want is that it should improve much better.

SHRIMATI KRISHNA SAHI: The rats are also eating it away.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: In spite of eating away by the rats which the hon. lady member is whispering from behind, and, possibly, there are 4-footed and 2-footed which might be eating away...

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: Big rats.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Small and big rats, white and black both. In spite of that, the fact remains that the job done is a job of very wide magnitude. You imagine from this point of view that, every month, the FCI is undertaking the movement of 12.8 lakh tonnes, from one end of the country to another. They are handling about 128 lakh bags per month. That is not an easy job to be done. They are doing it. Their distribution has gone up, starting from 1978 when they had just 10.18 million tonnes, they have come to 14.78 million tonnes in 1982-83, that is, from 101 lakh tonnes they have come to 147 lakh tonnes. That is the magnitude of distribution work they are doing. Therefore, in the overall analysis, it is a good job done. But I will not speak more. Then hon. Members might be impatient to tell me, what about other points? I concede with hands up... (*Interruptions*) Therefore, I would say that the FCI is maintaining public distribution system through about 2000 depots all over the country.

18.00 hrs.

They are also subsidising the cost to inaccessible and hilly areas.

It should be appreciated that they purchase in the market to support the price. Uptill now there has been no complaint from the farmers that they had to sell under stress and strain or that they had to make distress sales. Friends have said about opening. . . . . .

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Farmers are complaining that they are colluding with the merchants.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: What I am saying is that, this is one point and that is another point. Some friends like Shri K. C. Pandey and Shri Ram Pyare Panika have said that in States like Uttar Pradesh, FCI does not purchase direct from the farmers. But it will not be fair to say that in respect of all cases. But there are places, as Hon. Members say, where they delay their operations; in between the middlemen, the Adhityas take it and they take it from Arhetiars. This is a serious complaint. I have taken note of it and I will do my best what all can be done in this matter.

I am trying to understand this FCI which is called a white elephant. I am seeing whether I will be able to ride this elephant. I will do my best.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI R. VENKATARAMAN): You tame it.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: With the blessings of Mr. Venkataraman, I will try to tame it.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Therefore, I would say that with FCI another serious complaint is about loss in storage and also in transport. That is the last point which they have mentioned. I would say that this is an important point which has to be looked into and that is why we have gone into it. I have gone into what has been gone into by the Ministry. They have done a good job. I am surprised to hear that 50 weigh-bridges are out of order, as per reports coming during the procurement season from Punjab. I myself confided to this House that this will not be permitted. Why should they be out of order? I can understand one to five bridges out of 100 going out of order. I have told my officers that this cannot happen to the bridges. Therefore, this will be done and that is why now the Secretary of the Ministry of Food has gone into this matter in great detail. Before coming to this House, I have seen for myself and we feel that there are improvements which can be made and which can reduce these losses. For example, proper weighing should be there when it is put into the truck, when the truck moves to the temporary point in the mandis and when it is put in the railway wagons. Surprisingly, they say that it has been told by the FCI that so much has been given. We do not know this. We will improve this system. When we go into storage, there must be regular check. I have seen a long note from the FCI. I have seen it, about the Vigilance, right from Headquarter to the District Headquarters. We have seen the cases in which punishment was given. I would not just take the time of the House by giving all those details. I will try to see how this can be improved, that the cases are brought to us, why there should not be proper accounting, why there should not be counting of bags in the godown and all these I will try to enforce. These are the points that have been said.

I would say that in spite of this there has been another kind of criticism and that criticism has been about administrative cost of the FCI. I would only like to say—I would not go into details—that after the net price is given to the farmer, the first important expendiure is procurement incidental which is Rs. 23.35 per quintal.

Members may say "What is this? Private trader does it at much less." I would tell the Hon. Members that this Rs. 23.35 per quintal consists of a large number of charges which are statutory. For example, mandi charge, sales/purchase tax, cost of gunny, inetrest charge and the last point, the administrative charge is Rs. 1.13 per quintal. This has to be appreciated that, in this total of Rs. 23.35, almost about Rs. 18 are satutory obligatory charges—like the mandi charges that the Punjab Government has put, pay for the gunny bags, pay the purchase tax, pay the interest. Thus, out of 23.35, 80 per cent are statutory or obligatory charges. The procurement incidental is 16.4 per cent of the procurement price; out of this, 12.67 per cent is the obligatory charge. Therefore the establishment charge of the total procurement price is 0.8 per cent. If the hon. Member desires me to tackle it still better, I will see how this 0.8 per cent can come down. But the fact remains that the other charges put by others are the obligatory or statutory charges which we have to pay. I did not know myself earlier. Had I been speaking on this debate without these facts, I myself would have been shocked that this is a terrible charge that they are giving.

Then we come to the distribution charge. After procurement charge, distribution charge comes to Rs. 27.60 per quintal. In this also the story is the same—distribution incidental to the economic cost. Economic cost means the price given to the farmer, procurement incidental and the distribution cost; they make the entire economic price. But at this price we do not give to the States. We bring it, by giving subsidy, to the issue price. Therefore, the issue price is less than that.

Therefore, I would say that, even in this distribution cost, our administrative ovrhead is Rs. 2.39. Where the hon. Members have pinpointed, where it is paining, it is giving pain, is this. We must find out how we can improve the storage where the small and big rats, black and white, eat away the grains reduce and also the loss in transit. That, we shall try. I must say that it has been looked into and looked into well, and we will try to enforce it after the debate is over with the strength of the hon. Members on my back; I will try to tackle and see how best I can do. Therefore, I would say....

AN HON. MEMBER: Why on the back only?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You mack him up on this. That is what he says.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I will be happy if my hon. friends speak nicely on my face. I will appreciate it; I will always welcome that.

I would say that in the FCI—my friends will be interested in knowing this—there are a large number of Unions but no recognised Union. They have made a demand for revision in wages. So far, they were guided by the Central pay and dearness allowance. Some of them want to stick to it because they get more by that that what they will get if they come under 'industrial undertaking'. My friend, Mr. Lawrence has come now after I have given him all the compliments. Should I repeat it? I will repeat at the end. So, I would say that I have asked the Corporation to look into this. I always believe in this that first you must decide what is due from the friends who work with you and then you demand from the FCI due from us. I would demand from the FCI employees what is my due—'my due' means the country's—and we will also certainly consider and consider sympathetically what is their due. It has to be decided how many of them want to stick to the old pattern, that is, the Central pay and dearness allowance, and how many want to come under industrial undertaking' and if they come under that, then the industrial cost will apply to them, the dearness allowance, and in that case there are other obligations also about hours of work and about other things. We shall look into it after this debate is over.

About storage of foodgrains, my friends have said about the storage capacity. I would say that, as on 31-12-1982, we had 15.7 million tonnes of hired and owned capacity with us. Hired—we take from the Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations and other agencies. In 1983-84 five lakhs tonnes of capacity are to be constructed by F. C. I. We will do it.

Mr. K. C. Pandey raised the question of the capacity being constructed with the World Bank Support. It is true that it could not be ready by 1981. It will now go over the coming years, but it was due to the reason that the land was not available and also due to other reasons. We have talked to the World Bank and now they have reconciled with our new schedule and we will try to construct them by the revised schedule. Mr. Pandey wants me to examine why it is so and whether the reasons given are really justified. I will look into that. I will see what can be done about that.

Another form of storage is that we have a pucca g ound and above it we cover by tarpaulin and other materials. In 1977 we had 7.52 million tonnes CAP and we have now reduced it to 2.37 million tonnes and the actual stock we keep is 5.45 million tonnes. This is the figure of 1977 and we have now reduced it to 0.62 million tonnes—that is only 6,20,000 tonnes CAI now is there. But this is the safets way of doing. Therefore, we are trying ou best to have scientificstorage after motiva ting at the farm level where the farmer do the entir job at the farm level. W have got teams to go round and do th job.

Therefore, by this way, I must say tha we are trying our best to manage th food economy of the country. Hon. Mem bers raised different points and I hav tried to answer them and if I could n answer some of them, I will try, if yo speak to me again.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

Now come to another aspects of my portfolio, viz., civil supplies. In the matter of edible oil, the requirements of the country are 40 lakhs tonnes. We are producing 27 to 28 lakhs tonnes. Therefore, the gap is 12 lakhs tonnes. This we are trying to fulfil by encouraging more production of oil seeds in the country and by trying to give support price and we are also trying to have an appropriate oil users' policy and also we are trying to improve oil to meet the gap. That way, about a million plus tonnes every year we are importing. Out of this we are giving for Vanaspati producers about 6.3 lakhs—60 per cent of their needs and 4.5 lakhs tonnes for direct consumption as oil, at a price of Rs. 8500/- per tonne. My friends have said—nationalise this industry. I must say that in this country we have got about 93 licensed units for producing, Vanaspati. Their licensed capacity is approximately 14 lakhs tonnes. The installed capacity is about 13 lakhs tonnes. We are producing 9.03 lakhs tonnes. I think the situation that prevailed during the Asiad, the last Divali and other festival seasons have proved that the demand and supply have been going on very well. There has been no increase in the price of Vanaspati. We are trying to maintain the price. In North India and some other parts of the country, it has been a good medium of cooking. Therefore, we are trying to do that. It is not possible to nationalise it and we do not propose to nationalise this industry.

Now I come to another important point.

Now, Sir, I come to the last important point of sugar in which many friends have taken part. They were: Sarvashri Ram Nagina Mishra, K. C. Pandey, Chandrapal Shailani, Girdharilal Vyas, Ashfaq Hussain, Madhukar and Paneka all of whom have raised important questions. What are the Important questions raised regarding sugar?

The first important question is about the arrears. The sugar policy of the Government of India was reoriented in 1980-81. Compared to the past years, we had very little production of 38.59 lakhs tonnes in 1979-80. In 1981-82 it has touched the figure of 84.38 lakhs tonnes; in 1982-83, we expect it to be about 75 to 80 lakhs tonnes. For sugar, in 1980-81, the policy was of giving a minimum support price—the statutory price—on the recovery. That policy has now paid us.

Therefore, the production in the country has increased. Compared to 38 lakhs tonnes, as I said, it has come to 84 lakhs tonnes. But, the arrears are there. For example, I would myself say that the arrear as on 15th February in 1980-81 was Rs. 94 crores. It was 14.6 per cent of the total price payable. In 1981-82 the arrear was Rs. 133.57 crores which was 17.5 per cent of the total. This year, that is, the year which is under consideration—1982-83—it is Rs 196.40 crores which is 28.4 per cent of the total. But, that does not reflect the concern of the hon. Members from U.P. and Bihar. I would say that it is much more than 28.4 per cent. I do not hide anything.

श्री रामनगीना मिश्र : उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट बकाया बाकी है ?

श्री भागवत झा आजद : मैं तो खुद ही कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैम्बर बहुत होशियार हैं। जब नगीना जी ने, पांडे जी ने और पनिका जी ने इतने जोर से कहा है तो वे मेरे फिगर्स को नहीं मानेंगे। मैं भी वहां का रहने वाला हूं।

Therefore, I would say that in U.P. the due is Rs. 76.46 crores which is 42.3 per cent of the total; in Bihar, the due is Rs. 24.26 crores but the percentage is 73.1. Therefore, these arrears are there. What we are trying is to see that the additional bank credits should be given to reduce this. They should clear the loan. For that increased cash credit should be given to them so that they should be in a position to pay off the arrears.

Sir, when we see their due or arrears in the first three months of the crushing year, it is at the peak. It is so for all the years. And then it tapers down. This arrears comes down every year. We hope these arrears will come down. The point is this. We are monitoring from here. All that we can do is this. We have requested the State Governments that they should ask the millowners to pay off the arrears because the State advised price is a price arrived at through the agreement between the State and the millowners. Therefore, they should pay it.

I would say that the difficulty is in U.P. and Bihar. Why? Maharashtra and Tamilnadu are doing all right. They are paying only an advance price initially. When the crushing season is over, they count the entire thing

Maharashtra and Tamilnadu do it on the basis of recovery and additional realisations based on the Bhargava Formula. They give fifty-fifty. The entire credit is paid off. In the case of U.P. and Bihar, there is no linking of the recovery and the statutory price. The Central Government, this year, has fixed Rs. 13|- for the recovery of 8.5 per cent according to whih in U.P., it will come to Rs. 17.40 to 18.85; in Bihar it will come to Rs. 14.10 to 17.20; in Punjab, it will come to Rs. 19.10; in Haryana it will come to Rs. 16.15. The payment that is being paid by U.P. also comes to Rs. 20.50 to 21.50; in Bihar it is Rs. 20.50; in Punjab, it will come to Rs. 20 to 23; in Haryana, it will come to Rs. 20 to 23. Even the zones that were formulated by the Government of India on the export committee basis, the prices even in those zones were not adhered to by Uttar Pradesh and Bihar. Therefore, the difficulty has come in the way. This price which has been fixed by them is not being paid by the mills because they say their capacity is not there.

Sir, it has to be kept in mind that in the sugar industry there are three partners—sugarcane growers, the industry and then the consumers. We have decided to take care of the consumer and, as such, the levy price of sugar all over the country in any shop and in any place would be Rs. 3.75 per kilo. This is the subsidised price as compared to the cost price. Therefore, on 65 per cent levy is being taken and 35 per cent is left to the millowners to make up from the market.

SHRI ASHFAQ HUSSAIN: I raised the point about custodian mills.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: There are eight mills taken by the Central Government. Five in Uttar Pradesh. One Ayodhya Mill, we have paid them. There is very little left with us. There are three other mills where the custodians are prepared for a long time to pay all the dues but the farmers say them would not accept it till they are given the State advised price.

SHRI ASHFAQ HUSSAIN: There are even arrears of the last year.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, about the arrears on the custodian mills the friends here said that they are the worst criminals. I would like to point out that the arrears are just within the 10 per cent permissible limit under the Act. Therefore, we have paid. Our difficulty is that and I must say that you kindly appreciate that one has paid and one is in a difficult situation. Three are ready to pay but the farmers say you must give us the State advised price.

Sir, I also know in the same constituency or in the same district there is one price being paid by the custodians and the other price not being paid but being said by the other mill that their price is much higher. Sir, in a country of our magnitude when something is decided after being given serious thought about the fixing of price especially and if that is not adhered to, then this kind of distortion comes in the country. It was considered, the experts came to a decision and Central Cabinet decided that the statutory price will be Rs. 13 on the recovery of 8.5 per cent. In other States, for example, Maharashtra and Tamil Nadu the cane price fixation is being done on the basis of recovery and they have no pro-

[Shri Bhagwat Jha Azad]

blem. But the States which announce their own price the arrears show that this is not the way to functioning sugar economy. They have asked for the loan from the Finance Minister. From here it has been said time and again that Rs. 20 crores worth of soft loan is being provided. I would request and I would certainly write to the State Governments and tell them that the State advised price should be paid and also plus the interest. I am aware of the Control Order in which it is provided that after 14 days they are liable to pay interest. But the question here is that the principal is not being paid. I do not deny that interest should be given but it is a question of requesting the State Governments. It has been said that we will leave off the purchase tax and also about the adjustment in the excise. Finance Minister has done it.

SHRI ASHFAQ HUSSAIN: Mills under custodianship are not paying the interest.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I have told the facts.

श्री भागवत झा आजाद : जो अशफाक साहब कह रहे हैं, वह ठीक ही होगा । मैं यह बता देना चाहता हूं कि अयोध्या मिल ने पे कर दिया है और तीन मिल में हम देने के लिये तैयार हैं । प्रश्न यह है कि वे कहते हैं कि 18 रुपए 50 पैसे नहीं लेंगे, स्टेट एडवाइस प्राइस दीजिए । मैं कहना चाहता हूं कि जो साइन्टिफिक बेसिस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया और उसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही न माने तो किस मुंह से कहें ।....(**व्यवधान**)

श्री रामनगीना मिश्र : राज्य सरकार ने साढ़े बीस रुपए पूरब में और साढ़े इक्कीस रुपए प्रति क्विंटल पश्चिम में दाम घोषित किए हैं । लेकिन जो आपकी पांच फैक्ट्रियां हैं, वे क्यों नहीं दे रही हैं ? क्या आपकी सरकार वहां भी है और यहां भी है ?

श्री भागवत झा आजाद : यही बात मैं अब तक समझा रहा था । यह हमारे लिए संभव नहीं है । आपकी राज्य सरकार ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय के खिलाफ जो उसका वैज्ञानिक आधार है वह यह है कि स्टेचुटरी प्राइस का रुपया 8.5 इकाई पर हो दिया जाए जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु फालो करता है । कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपने अपने मन से निर्णय किया । अब कठिनाई यह है कि उनकी एडवाइज पर यह पैसा दिलवाएं, हम तो उल्लंबन नहीं करेंगे ।

श्री रामनगीना मिश्र : गन्ना किसान गन्ना नहीं दे रहा था । स्टेट गवर्नमेंट ने विधान सभा में अनाउंस किया कि जो रेट समूचे देश में दे रहे हैं, वही रेट हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दिलवायेंगे । या तो वह सरकार इस्तिफा दे दे नहीं तो केन्द्र उसका दाम दिलवाए ।...(**व्यवधान**)

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I have given the facts and figures. Mr. Deputy Speaker, beyond this, I cannot add anything. Mr. Ram Nagina Mishra can very well call for the resignation—I don't know from whom in the Central Government—he is at liberty to do it; he should go to Prime Minister and Chief Minister and ask for it.

श्री कृष्ण चन्द्र पाँडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं ।....(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY SPEAKER: He has mentioned your name so many times. Are you still not satisfied? Please sit down.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I know that it is a difficult situation. But this difficult situation has been there; this distortion in the Economy has come due to the fact that we were not able to appreciate the scientific formula that was worked out by the Central Govt. experts. Sugar industry which consists of cane

growers is also an industry where the consumer has to be given Sugar at a reasonable price. We have to have the statutory price, that is, Rs. 13 linked to the recovery of 8.5. I am only saying that some of the State Governments are following it and they are managing well. Some of the State Governments whose price was much higher than this price, are in difficulty. Now the question is this: They have asked for a loan from the Finance Minister. How to pay it? All I can say is that the Central Custodian Mill will pay according to what the decision of the Central Government is,—not *ad hoc* decision, not indiscriminate decision—but a decision based on scientific calculation and scientific formla. And therefore, Sir, I will only say this. About the rest let us see how it can best be worked, how it can be done. We will do our best to help them. I have given the entire facts to hon. Members. I know the hon. Member is angry; his anger is quite justified. But the fact remains that we have to look to the canegrowers and also to the consumer. Therefore, It would say his. As a result of the 1980-81 policy of the Government of India under Mrs. Gandhi's leadership, while at one time we had only thirty-eight point something lakhs tonnes, now we have been able to produce 84 lakh tonnes sugar this year is might be the same or a little less; it may be 75 to 80 lakh tonnes this year. Therefore we are trying to have a buffer stock of 5 lakh tonnes for which we are giving 100 per cent credit for carrying the buffer stock and also the interest charge on that. Sir, this is all about the Sugar Industry.

I hope that I have been able to cover almost all the important points of hon. Members.

श्री कृष्ण पांडे : यू०पी० गवनर्मेन्ट ने जो 20 करोड़ रुपया मांगा हैं उसके लिए आपने क्या किया ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: That I have said. The State Government has asked for a Soft Loan of Rs. 20 crores. The Finance Minister is to consider about this. So, far as I am concerned, I am with you if you can go on a deputation. Therefore, Sir, once again I am grateful to all the hon. Members for their constructive criticisms for their few words of appreciation and for giving me the encouragement to do still better and also to those who played with a cross bat like my dear friend, Mr. Lawrence, who said about purchasing power, about the irrigation and electricity and all the entire economics of his party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There was only a cross bat. But it was not a boundary.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: That also he did and also sixes. So, Sir, I am grateful to the Hon'ble Members for their constructive criticisms. I hope that, in spite of the difficulty and the present drought situation, we will be able to manage our food situation. No State Governments have reported about any death due to starvation. We will still do our best, as I said, about the allocations to Tamil Nadu and also additional allocations to them. We have given to Kerala, we have given to Orissa and we have done it for Bihar also. We will try to do our best within the means that we have in the Central Pool and we hope that as we did in the past, through the public distribution system to stave off the drought of 1979-80, we are confident that the present drought situation will also be surpassed and won over by the Government of India under the able leadership of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): May just say a few words? Repeatedly I was advising our Prime Minister to have a young enough dynamic and constructive Minister in charge of both these Departments, Food and Civil Supplies. At long last, she has taken a right decision and I wish to congratulate the Prime Minister for having fulfilled our demand.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions to the Demands of the Ministry of Food and Civil Supplies together to the vote of the House, unless any hon. Member desires that any of the

cut motions may be put separately..... I think you all agree, I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.

All the Cut Motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1984, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 45 and 46 relating to the Ministry of Food and Civil Supplies."

The Motion was adopted.

Demands for Grants, 1983-84 in respect of the Ministry of Food and Civil Supplies voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on the 18th March, 1983		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES					
45	Department of Food	157,97,96,000	6,55,68,000	789,89,79,000	32,78,39,000
46	Department of Civil Supplies	79,08.,000	1,38,50,000	3,95,37,000	6,92,49,000

18.34 hrs.

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the Clock on Thursday Mar 31, 1983/*Chaitra* 10, 1905 (*Saka*)

GMGIPND—M—185 LS 3-9-83—